लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4/1/84
Parliament Library

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5—सोमवार, 7 नवम्बर, 1966/16 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 5—Monday, November 7, 1966/Kartika 16, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता०प्र० संख्या *S. Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
121.	ईरान में पाकिस्तान का सैनिक हवाई अड्डा — Military Air Base for Pakistan in Iran .	567—570
122.	कच्छ न्यायाधिकरण — Kutch Tribunal	570—575
123.	नागालैंड में युद्ध विराम की अवधि का बढ़ाया जाना — Extension of Cease fire in Nagaland	575—579
124.	राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भारत के वैदेशिक-कार्य मंत्री का भाषण — Foreign Minister's Speech in Commonwealth Prime Ministers' Conference .	579–580
125.	इन्डोनेशिया के पाकिस्तान स्थित राजदूत का वक्तव्य — Statement by Indonesian Ambassador to Pakistan	580—582
126.	वियतनाम के विसैन्यीकृत क्षेत्र में बमबारी — Bombing of Demilitarised Zone in Vietnam	583–584

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.		
127.	व्यापार सम्बन्धी प्रसारण — Commercial Broadcasting . .	585
128.	टेलीविज़न उपकरणों का निर्माण — Manufacture of T. V. Equipment .	585
129.	आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकायें — Journals published by A.I.R. . . .	586
130.	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का तथा युद्ध विराम का उल्लंघन — Air and Cease fire Violations committed by Pakistan	586

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.		
131. सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Powered Transmitters for Border Areas	587
132. ताशकन्द घोषणा की व्याख्या	Interpretation of Tashkent Declaration .	587
133. चीन द्वारा विस्फोट	Chinese Explosions . . .	588
134. सेनाध्यक्ष का रूस का दौरा	Visit of Army Chief to U.S.S.R. .	588–589
135. भारत तथा पाकिस्तान के वैदेशिक कार्य मंत्रियों की मुलाकात	Meeting of Foreign Ministers of India and Pakistan	589
136. सूचना तथा प्रसारण के माध्यमों सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Report on Information and Broadcasting Media . .	589-590
137. पाकिस्तान के लिए चीन की पनडुब्बियां	Chinese Submarines for Pakistan .	590
138. रेडियो ल्हासा	Radio Lhasa . . .	591
139. चीन द्वारा घुसपैठ	Intrusions by China . . .	591
140. मंत्रियों की आस्तियां तथा देनदारियां	Assets and Liabilities of Ministers . .	592
141. चीनी सेनाओं का जमाव	Concentration of Chinese Forces . .	592–593
142. मद्रास अणु बिजलीघर	Madras Atomic Power Station . .	593
143. पाकिस्तान को सैनिक सामान की सप्लाई	Supply of Military Equipment to Pakistan	593–594
144. रूस के विदेश उपमंत्री की भारत यात्रा	Visit of Deputy Foreign Minister of USSR	594
145. राजस्थान अणु ऊर्जा परियोजना	Rajasthan Power Project . . .	594–595
146. संयुक्त राष्ट्र संघ में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का प्रवेश	G. D. R's. admission to UNO . .	595
147. पाकिस्तान के उच्चायुक्त का स्मारकपत्र	*Aide memoire* by Pak. High Commissioner . .	595–59
148. सऊदी अरब की पाकिस्तान को सहायता सम्बन्धी लोक समिति	Popular Committee for aid to Pakistan of Saudi-Arabia.	596
149. विदेशों में भारत मूलक लोग	People of Indian Origin in Foreign countries	596–597

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
150 भारत की खाद्य स्थिति के बारे में अफ्रीकी देशों में प्रसारण	African Broadcasts About Food situation in India	597
अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
635. सैनिक समाचार	Sainik Samachar .	597
636. सैनिक समाचार	Sainik Samachar . . .	598
637. लोक सम्पर्क निदेशालय	Directorate of Public Relations .	598–599
638. हिमालय पर्वतारोहण संस्था	Himalayan Mountaineering Institute .	599–600
639. आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर	Draughtsmen and Tracers in A.I.R. .	600
640. आकाशवाणी में ड्राफ्टसमैन और ट्रेसर	Draughtsmen and Tracers in A.I.R.	601
641. आकाशवाणी में इंजीनियर	Engineering Staff in A. I. R. .	601
642. भूटान की दूसरी पंचवर्षीय योजना	Second Five Year Plan of Bhutan	602
643. अफगानिस्तान को सहायता	Assistance to Afghanistan . .	602–603
644. प्रतिरक्षा योजना पर अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of Devaluation on Defence Plan	603
645. भारतीय पत्रकारों द्वारा दक्षिण वियतनाम में हुए चुनावों के समाचार भेजा जाना	Covering of Elections in South Vietnam by Indian Journalists . . .	603
646. भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों की बैठक	Meeting between Army Chiefs of India and Pakistan	604–605
647. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में तालाबन्दी	Lock-out in Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur	605
649. आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली	A. I. R. Delhi . . .	606
650. परमाणु करार	Nuclear Agreement . . .	606
651. टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली	T. V. Centre Delhi	606
652. भारत श्रीलंका करार	Indo-Ceylonese Agreement . .	607
653. अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन स्थल	Venue of Afro-Asian Conference . .	607
654. संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को शामिल किया जाना	China's Admission to U. N. O. . .	607–608
655. ताशकन्द समझौते का पालन	Implementation of Tashkent Agreement .	608–609

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
656. पाकिस्तान के लिए ईरानी जैट विमान	Iranian Jets for Pakistan . . .	610
657. एवरो-748 कारखाना, कानपुर	Avro-748 Plant at Kanpur . . .	610–611
658. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए भारत का उम्मीदवार होना	India's Candidature for U. N. Security Council Seat	611
659. आकाशवाणी का 'हमारी अर्थ-व्यवस्था की दशा' (स्टेट आफ अवर इकानोमी) कार्यक्रम	AIR 'State of our Economy' Feature. .	612
660. पाकिस्तान द्वारा स्वीडन से हथियारों की खरीद	Purchase of Arms by Pakistan from Sweden	612
661. चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violation Committed by China	613
662. राष्ट्रीयता विहीन व्यक्तियों के बारे में भारत-श्रीलंका करार	Indo-Ceylonse Agreement on Stateless Persons	613
663. हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर	Harness and Saddlery Factory, Kanpur .	614
664. नये आयुध कारखाने	New Ordnance Factories . . .	614–615
665. प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड	Defence Production Board . . .	615–616
666. चीन द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण	Violations of Indian Territory by China .	
667. वियतनाम की समस्या	Vietnam Problem	616
668. प्रभावशाली प्रसारण पद्धति	Efficient Broadcasting System . .	616–617
669. भारत-मलयेशिया और मलयेशिया-पाकिस्तान सम्बन्ध	Indo-Malaysia and Malayasia-Pakistan Relations	617
670. ग्रामीण प्रसारण परियोजना	Rural Broadcasting Project . . .	618
671. अन्दमान द्वीप समूह के निकट विदेशी	Foreign Submarines near Andaman Islands	618–619
672. प्रत्यर्पण करार	Extradition Treaties	619–620
673. पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता	U. S. Military Aid to Pakistan .	621

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ०प्र० संख्या U. Q. Nos.		
674. अखबारी कागज़ की स्थिति	Newsprint Situation	621-622
675. संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अधिवेशन	General Assembly Session . . .	622
676. नेहरू लियाकत समझौता, 1950	Nehru Liaquat Pact, 1950 . . .	623
677. आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for A. I. R. . . .	623
678. 'मिग' कारखाने	M. I. G. Factories	624
679. पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Pillai Committee's Report . . .	624
680. विज्ञापनों पर कमीशन	Commission on Advertisements . .	624-625
681. आकाशवाणी को समाचारों का दिया जाना	Supply of News to A. I. R. . . .	625
682. राजौरी (श्रीनगर) के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	I. A. F. Plane Accident near Rajouri (Srinagar)	625-626
683. संयुक्त राष्ट्र बृहत्सभा के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल	Indian Delegation to U. N. General Assembly	626
684. भारत-चीन सीमाओं पर चीनियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Chinese on Indo-China Boarders	626-627
685. भारत सेवक समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj . .	627
686. अमृतसर नाले में सैनिकों का डूब जाना	Drowning of Defence Personnel in Amritsar Drain	627-628
687. विमान चालकों को वायु सेना छोड़ने की अनुमति	Release of Pilots from Air Force] . .	628-629
688. गुलमर्ग में अनुसन्धान प्रयोगशाला	Research Laboratory at Gulmarg . .	629
689. जादुगुडा में यूरेनियम का कारखाना	Uranium Mill at Jaduguda . . .	629-630
690. दक्षिण रोडेशिया में अवैधानिक शासन सत्ता	Illegal Regime in Sourthern Rhodesia .	630
691. हिन्द चीन क्षेत्र की जातियों की तटस्थता	Neutrality of the Peoples of Indo-China Region	631
692. केनिया से भारतीयों का निर्वासित किया जाना	Deportation of Indians from Kenya	631

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
693.	चुनीन्दा फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट	Exemption of Selected Films from Entertainment Tax	632
694.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में निर्मित विमान	Aircraft manufactured at H.A.L. Kanpur	632-633
695.	पाकिस्तान की सैनिक तैयारी	Pak. Military Build-up	633-634
696.	भारत श्रीलंका करार	Indo-Ceylonese Agreement . . .	634
697.	अमरीकी बमबारी के बारे में दक्षिण वियतनाम में भारतीय महावाणिज्यदूत का वक्तव्य	Statement by Indian Consul-General in South Vietnam on U.S. Bombing .	635
698.	शास्त्री निकेतन	Shastri Niketans	635
699.	संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव के कार्य	Functions of U. N. Secretary General] .	635
700.	ताइवान के छात्रों द्वारा वीसा के लिये आवेदन पत्र	Visa Applications from Students of Taiwan	636
701.	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय कर्मचारियों का स्वदेश लौटाया जाना	Repatriation of Indian Personnel detained in Pakistan	636
702.	बर्मा में मांडले जेल में स्मारक भवन (मैमोरियल हाल)	Memorial Hall in Mandalay Jail, Burma .	636
703.	ब्रिटिश इम्पीरियल डिफेंस कालेज के पदाधिकारियों के एक दल का दौरा	Visit by U. K. Imperial Defence College Team	637
704.	विदेशों में प्रचार	External Publicity	637-638
705.	मराठी फिल्मों के निर्माता	Marathi Film Producers] . .	638
706.	फार्म ऐंड होम रेडियो ट्रांसमिशन यूनिट	Farm and Home Radio Transmission Units	638-639
707.	रेडियो सीलोन के साथ झगड़ा	Disputes with Radio Ceylon .	639
708.	परमाणु प्रौद्योगिक उद्योग समूह	Nuclear Technological Complex .	639-640
709.	भारी जल संयंत्र	Heavy Water Plant	640
710.	फार्मोसा के लिये पारपत्र जारी करना	Issue of Passports for Formosa . .	640
711.	साल्वेज डिपो (कबाड़ भण्डार) के लिए भूमि का अर्जन।	Acquisition of Land for Salvage Depot .	641

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
712.	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को परिवहन चिकित्सा तथा आवास की सुविधायें	Transport, Medical and Housing facilities to H.A.L. Employees . . .	641-642
713.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर	Hindustan Aeronautics Ltd. Kanpur	642-643
714.	विद्रोही नागाओं की गतिविधियां	Activities of Naga Hostiles .	643-644
715.	समाचारों का प्रसारण	News Broadcast . . .	644
716.	कच्छ क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के विरुद्ध पाकिस्तान का विरोध	Pak. Protest against Construction of Road in Kutch Area . .	644-645
717.	आकाशावाणी केन्द्र, कालीकट का प्रादेशिक समाचार एकक	Regional News Units of All India Radio, Calicut . .	645
718.	मलयाली कार्यक्रम	Malayalam Programme . .	645
719.	त्रिवेन्द्रम में कमज़ोर ट्रांसमीटर	Weak Transmitter at Trivandrum .	646
720.	मिग कारखाना, कोरापुट	M.I.G. Factory, Koraput	646
721.	अम्बाझारी कारखाना	Ambajhari Factory .	646-647
722.	पोर्टेबल एयर कम्प्रैशर	Portable Air Compressors .	647
723.	हैदराबाद में वायु सेना अकादमी	Air Force Academy at Hyderabad .	647-648
724.	ढाका में भारत-पाकिस्तान संघर्ष सम्बन्धी इश्तहारों की प्रदर्शनी	Exhibition of Posters on Indo-Pak. Conflict held in Dacca	648
725.	थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के पुस्तकालय	Libraries of Army, Navy and Air Force	648
726.	सैनिक बैण्डों की भारतीय धुनें	Indian Tunes of Military Bands	648-649
727.	वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा खरीदी गई साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाएं	Weeklies and Monthlies purchased by External Affairs Ministry . . .	649
728.	बल्लभगढ़ में इलेक्ट्रोनिक फैक्टरी	Electronic Factory in Ballabhgarh .	649-650
729.	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये पेंशन की दरें	Pension Rates for J. C. Os. .	650-651
730.	तारापुर परमाणु बिजली घर	Tarapore Atomic Power Station . .	651
731.	भारतीय दूतावास के लिए प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष	Trained Librarians for Indian Mission .	651-652

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
732.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष	Trained Librarians in Indian Missions Abroad	752-753
733.	देहू मोटर-गाड़ी डिपो	Dehu Vehicle Depot	653
734.	सैनिक ट्रक दुर्घटना	Military Truck Accident . . .	654
735.	पादरी माइकल स्काट	Rev. Michael Scott . . .	654
736.	भारत चीन सीमा विवाद	Indo-China Border Dispute . . .	655
738.	तंजानिया को सहायता	Assistance to Tanzania	655-656
739.	पालम हवाई अड्डा क्षेत्र से टायर और ट्यूबों की चोरी	Theft of Tyres and Tubes from Palam Air Port area	656
740.	महाबलेश्वर सड़क पर दुर्घटना	Accident on Mahabaleswar Road . .	656-657
741.	नेपाल को भारतीय सहायता	Indian Aid to Nepal	657-658
742.	एच० एफ० 24 परियोजना	HF. 24 Project	658
743.	सैनिक समाचार	Sainik Samachar	659
744.	पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली-बारी	Firing by Pakistani Troops . . .	659-660
745.	ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य राज्य मंत्री की भारत यात्रा	Visit of British Minister of State for Foreign Affairs to India . . .	660
746.	जमाये मांस को डिब्बों में बन्द करने का संयंत्र	Freeze Meat Packing Plant . . .	660-661
747.	बर्मा में भारतीय	Indians in Burma . .	661
748.	केरल में प्रतिरक्षा उद्योग	Defence Industries in Kerala	661-662
749.	भारतीय वायु सेना में तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती	Recruitment of Technical Hands in I. A. F.	662-663
750.	जवानों को तबादले के समय निशुल्क सामान ले जाने की सुविधा	Free Luggage Facility to Jawans on Transfer Postings	663
751.	केरल में विकलांग जवानों के लिये भूमि	Land for Disabled Jawans in Kerala .	664
752.	गोआ में गिरजाघर	Church in Goa	664
753.	समाचार भारती	"Samachar Bharati" . .	664-665
754.	खून का शुष्क रक्तरस (प्लाज्मा)	Dry Plasma of Blood . .	665

अ० प्र० सं या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
755.	फगवाड़ा में हुए दंगे में प्रयुक्त प्लास्टिक बम	Plastic Bomb Used in Phagwara Outrage	665
757.	कोसीपुर तोप तथा गोला कारखाना	Cossipore Gun and Shell Factory .	666
758.	त्रिराष्ट्रीय सम्मेलन पर व्यय	Expenditure on Tripartite Conference .	666
759.	एयरमैनों की भर्ती	Recruitments of Airmen . .	666-667
760.	पादरी माइकल स्काट के दस्तावेज	Documents of Rev. Michael Scott .	667
761.	मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Stations in Mysore . . .	667-668
762.	मैसूर में ग्राम्य प्रसारण	Rural Broadcasts in Mysore . . .	668
763.	सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का मामला फिर से उठाने का पाकिस्तान का प्रयास	Pak. Move to Revive Kashmir Issue in Secruity Council	668
764.	नेपाल में भारतीय लोग	Indians in Nepal	669
765.	नागरिक अभिनन्दन समारोह में संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्र गान की गलत ध्वनि का बजाया जाना	Wrong Anthem of U. A. R. Played at Public Reception	669
	अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Unstarred Question No. 3616	670
	अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Unstarred Question No. 61	670
	ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	*Re.* Calling Attention Notice and Motion for Adjowrnment (Query) . . .	670—673
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1966–67	Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1966-67	674
	विवरण उपस्थापित	Statement presented	674
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1966–67	Demands for Supplementary Grants (Railway), 1966-67.	674
	विवरण उपस्थापित	Statement presented	674

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Commonwealth Prime Ministers Conference . . .	674
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	674
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव के बारे में विधेयक पुरःस्थापित	*Re.* Motion under Rule 388 Bills Introduced—	674
(1) कम्पनी (संशोधन) विधेयक	(i) Companies (Amendment) Bill;	675
(2) मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक	(ii) Metal Corporation of India (Acquisition of undertaking) Bill; and	675
(3) कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक	(iii) Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill .	675
अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य (सभा पटल पर रखे गये)	Statements *Re.* Ordinances (Laid on the Table)—	675
(1) कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1966; तथा	(i) Companies (Amendment) Ordinance 1966; and	675
(2) मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1966	(ii) Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Ordinance, 1966	676
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	No-Confidence Motion in the Council of Ministers	677
श्री स्वैल	Shri Swell	677
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . . .	678
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	679
श्री राजाराम	Shri Rajaram	680
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . . .	680
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	682
केरल राज्य के संबंध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution *Re.* Proclamation in relation to state of Kerala . .	683
श्री हाथी	Shri Hathi	683
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	683
श्री केप्पन	Shri Kappen	684
श्री मण्यिंगाडन	Shri Maniyangadan	685
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	686

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail . . .	689
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	690
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . . .	690
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	692
श्री मोहम्मद कोया	Shri Mohammad Koya	692
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	693
दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* incidents in Delhi . .	693
श्री नन्दा	Shri Nanda	693

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 7 नवम्बर, 1966/16 कार्तिक, 1888 (शक)

Monday, November, 1966/Kartika 16, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ईरान में पाकिस्तान का सैनिक हवाई अड्डा

*121. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री फिरोडिया :
श्री राम सहाय पांण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री लीलाधर कटकीए :
श्री वि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम जर्मनी से खरीदे गये एफ-86 सेबर जेट विमानों के, जिनके बारे में भारत ने पहले ही ईरान, पश्चिम जर्मनी और कनाडा से विरोध प्रकट किया था, पाकिस्तान द्वारा ईरान को लौटा दिये जाने के तुरन्त बाद ईरान की सरकार ने अपने राज्य-क्षेत्र में पाकिस्तान को पूर्ण सैनिक हवाई अड्डा दे दिया जहां पर पश्चिम जर्मनी, से ईरान द्वारा खरीदे गये वे जेट विमान पाकिस्तान के नियन्त्रण में रखे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान को एक सैनिक हवाई अड्डे की सुविधा प्रदान की है जहां एफ-86 हवाई जहाज पाकिस्तान के नियन्त्रण में रहेंगे। ईरान उन्हें पाकिस्तान से वापस लाने पर सहमत हो गया है। सरकार ने पूछताछ की है लेकिन पाकिस्तान और ईरान के बीच इस प्रकार के प्रबन्ध होने के बारे में सूचना नहीं मिल सकी है।

Shri Vishram Prasad: May I know whether Government have lodged any protest against this air-base being given to Pakistan, if so, whether they have received any reply or information in regard thereto?

Shri Dinesh Singh: We did not lodge such a protest.

Shri Vishram Prasad: I would like to know whether this Pakistani air-base in Iran has created any danger to India, if so, how far the Government is prepared to meet this danger?

Shri Dinesh Singh: We have got no information that such an air-base has been constructed.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमरीकी सरकार के इस कथन को ध्यान में रखते हुये कि भारत और पाकिस्तान को कोई घातक हथियार नहीं दिया जायेगा तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान और ईरान दोनों एक ऐसे सैनिक संगठन के सदस्य हैं जिसका अमरीका मुख्य साझीदार है, क्या भारत सरकार ने अमरीका को ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया है कि इन सैनिक समझौतों में साझीदार उसके किसी साथी ने एफ–86 सेबर जेट विमान, जो और भी अधिक घातक हथियार हैं, पाकिस्तान को दिये हैं, यदि हां, तो अमरीकी सरकार से उसका क्या उत्तर मिला है ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में हमें जो चिन्ता है वह अमरीकी सरकार को बता दी गयी है

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर क्या है, वे इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने कहा है कि उनकी वही नीति है जो माननीय सदस्य ने बतायी है।

Shri M. L. Dwivedi: Some jet planes were supplied to Pakistan through Iran and, it is reported that they have been sent back to Iran. I would like to know whether Pakistan can use those very planes against India, if any situation arises, from the said air-base; if so, whether Government of India have in this connection addressed the country from where these planes were brought?

Shri Dinesh Singh: We have already told the House about the correspondence made with the countries concerned.

Shri Madhu Limaye: Our Government said that West Germany has violated the agreement reached between Canada and West Germany in this respect by giving these jet planes to Iran. But Bonn Government have refuted it by saying that they have not violated the said agreement. Will the Minister give us true information about it?

Shri Dinesh Singh: According to our information these planes were supplied to West Germany by Canada on the condition that West Germany will not give these planes to any other country without consulting Canadian Government. On this basis we said like that. Whatever it is, some countries have put pressure on Iran to take those planes back from Pakistan.

Shri Madhu Limaye: I want your protection, Sir. 'Whatever it is' what does it mean? I would like to know the real position whether Bonn Government are telling a lie or our Government have issued a wrong statement?

Shri Dinesh Singh: We have not got true copy of that agreement. So I cannot tell you in specific terms.

डा० म० मो० दास : क्या हमने ईरान सरकार के साथ एक सांस्कृतिक करार के अलावा और भी कोई अन्य द्विपक्षीय करार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रसंगानुकूल नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार ने इस सूचना के उद्गम का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये उन विदेशी समाचार पत्रों से सम्पर्क स्थापित किया है जिन्होंने यह सूचना प्रकाशित की थी ?

श्री दिनेश सिंह : हमने किसी भी विदेशी समाचार-पत्र को इस सम्बन्ध में नहीं लिखा ।

श्रीमती सावित्री निगम : एक सूचना तो हमारे मन्त्रालय को हमारे ईरान स्थित दूतावास ने दी है तथा दूसरे समाचारपत्रों से यह सूचना मिली है । इनमेंसे कौनसी सूचना प्रमाणित मानी जाय ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने जो सूचना दी है वह दोनों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है ।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार का ध्यान एक ईरानी नेता के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 'भारत को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हैं' । यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो प्रसन्नता की बात है कि ईरानी नेता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और वे हमारे खिलाफ पाकिस्तान को मदद नहीं देंगे । परन्तु यदि कोई ऐसी बात का हमें पता चलता है तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम ईरान सरकार का ध्यान उस ओर दिलायें ।

Shri Kishen Pattanayak: I would like to know whether Government is convinced that there can be no air-base in Iran for Pakistan?

Shri Dinesh Singh: I have given the information which I have got. To say that it is there for it is not there, is very difficult. There is an agreement between them and on this basis we can hold possibility of its existence there.

श्री कपूर सिंह : एक बार मन्त्री महोदय ने कहा कि स्थिति ऐसी है और उसके बाद यह कहा कि इस सम्बन्ध में की गयी पूछताछ का कोई उत्तर नहीं मिला है । क्या मंत्री महोदय इसे और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने कहा है कि हमें सूचनाएं समाचारपत्रों से मिली हैं । मेरे कथन में कोई विरोधाभास नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : हाल ही में एक इस्लामी शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अन्य अरब देश एक साथ बैठ कर विचार-विमर्श करेंगे । उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो ऐसा सम्मेलन हुआ ही नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने ईरान से आये हुये विमानों के पुर्जे भारत-पाक संघर्ष में बरबाद हुये अपने जेट विमानों को ठीक करने के उद्देश्य से निकाल लिये थे और ईरान को लौटाये जाने वाले विमानों की मरम्मत के लिये पाकिस्तान ने ईरान से नये पुर्जे मंगाये थे; यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमने यह सब जानकारी सभा के गत अधिवेशन में दी थी । उन्होंने कहा था कि ये विमान वहां मरम्मत के लिये भेजे गये थे । अतः उनकी मरम्मत के लिये पाकिस्तान को अवश्य ही पुर्जे दिये गये होंगे ।

कच्छ न्यायाधिकरण

\+

*122. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री मधु लिमये :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ रण विवाद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: उस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपे जाने का मुख्य कारण यह था कि हमने यह आशा की थी ऐसा करने से पाकिस्तान की भावनाओं में कुछ परिवर्तन होगा और दोनों देशों के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने का मार्ग खुल जायेगा । सरकार यह बताये कि क्या वह उद्देश्य पूरा हो गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : गत भारत-पाकिस्तान सशस्त्र संघर्ष के होने से पहले ही इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपे जाने को स्वीकार कर लिया गया था । भावनाओं में जो परिवर्तन हुआ है वह तो अब प्रत्यक्ष है ही । वास्तव में, इस समझौते के सम्पन्न होने के बाद ही दोनों देशों में असली लड़ाई शुरू हुई ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह भावनाओं के परिवर्तन के परिणामस्वरूप था ?

श्री स्वर्ण सिंह : हां, परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है । इस सम्बन्ध में हमारे जो अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व हैं उनका सम्बन्ध इस व्यापक उद्देश्य से नहीं जोड़ना चाहिए । यह एक विशेष प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में यह समझौता किया गया था कि यह मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया

जाय । अब यह मामला एक न्यायाधिकरण के सामने है और इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री नि० चं० चटर्जी भारत का पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता दे रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कुछ जानकार सूत्रों से मालूम हुआ है कि इस मामले से सम्बन्धित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो भूतपूर्व कच्छ राज्य के अभिलेखों से प्राप्त किया गया था, गुम हो गया है और भारत सरकार के अधिकार में नहीं है । क्या यह अफवाह सत्य है या असत्य है और उक्त दस्तावेज के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह अफवाह बिल्कुल असत्य है जिसका खण्डन पहले भी किया जा चुका है ।

श्री नि० चं० चटर्जी : मैं यह आश्वासन दिलाता हूं कि मूल दस्तावेज जेनेवा में हैं । मैं उसे देख चुका हूं और उसकी एक नकल मेरे कागजात में भी है । इस अफवाह के लिये कोई आधार नहीं है ।

Shri Vishwa Nath Pandey: Who are the persons, who have been helping in presenting Indian case before the tribunal? How much have Government spent on them?

श्री स्वर्ण सिंह : वहां पर हमारे महान्यायवादी श्री दफ्तरी मुख्य रूप से सरकार की ओर से वकालात कर रहे हैं जो भारतीय हितों का ध्यान रखते हुये न्यायाधिकरण के सामने भारत की ओर से यह मामला प्रस्तुत कर रहे हैं । श्री नि० चं० चटर्जी इस सम्बन्ध में उनकी मदद कर रहे हैं । हमारे दल में और भी कुछ सदस्य हैं और हमारा मामला बहुत ही अच्छी प्रकार न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि जब जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एक बड़े ही उपयुक्त वातावरण में कच्छ के मामले से सम्बन्धित दस्तावेजों का अध्ययन शनैः शनैः कर रहा था, उसी समय कच्छ में सशस्त्र पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ की, यदि हां, तो क्या न्यायाधिकरण और ब्रिटिश सरकार को यह तथ्य बता दिया गया है और यदि हां तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वे कोई बात न कहें जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न्यायाधिकरण की कार्य-पद्धति पर आक्षेप हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने क्या कहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उपयुक्त वातावरण । (सेल्यूब्रीयस क्लायमेट) और शनैः शनैः (टार्डिली) जैसे शब्दों के प्रयोग से तो न्यायाधिकरण की कार्य-पद्धति पर आक्षेप आता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य सरकार तथा उसके प्रतिनिधियों के बारे में जो चाहें सो स्वतन्त्रतापूर्वक कह सकते हैं परन्तु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों को तो वाद-विवाद से परे रखना ही वांछनीय है ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह मेरे प्रश्न को गलत समझ रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से यह अपील करता हूं कि ऐसा रवैया अपनाना राष्ट्रीय हित में नहीं हैं । दूसरा प्रश्न उन्होंने कच्छ में घुसपैठ के सम्बन्ध में पूछा है । यह प्रश्न प्रसंगानुकूल

नहीं है । यदि वे इस सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो उन्हें एक पृथक् प्रश्न प्रतिरक्षा मन्त्रालय को भेजेना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः प्रतिरक्षा मन्त्रालय ही देता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप ने इस सभा में कई बार यह विनिर्णय दिया है कि एक मंत्री को प्रश्न का उत्तर सही-सही देना चाहिये और यदि अधिक नहीं तो कम से कम इतनी सावधानी अवश्य बर्तनी चाहिये जितनी कि हम सदस्य बर्तते हैं । हमारे पास आपका विनिर्णय है ।

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या मैं श्री कामत और सभा को यह जानकारी दे सकता हूं कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल ने यह आग्रह किया कि इसका स्थान लन्दन रखा जाये हमने इसका विरोध किया । भारत की ओर से महान्यायवादी ने इसका कड़ा विरोध किया और कुछ कारणों से जिनको मुझे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जो प्रत्यक्ष हैं । हम नहीं चाहते थे कि इसका स्थान लन्दन रखा जाये । अन्त में न्यायाधिकरण ने हमारे सुझाव को स्वीकार कर लिया और उसने उसी स्थान को निश्चित किया । अतः जिनीवा को रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री कामत ने अनुकूल वातावरण और न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सुस्ती का जिक्र किया तो मंत्री ने इसका उत्तर दे दिया है और पूछा कि इन प्रश्नों को उठाने की क्या आवश्यकता थी । मैं इसको महसूस करता हूं; मैंने अनेक बार कहा है कि उनको प्रश्न पूछने में और उत्तर देने में यथार्थ होना चाहिये परन्तु जब कोई सदस्य इन चीजों को लाता है तो मंत्री को उनका उत्तर देना पड़ता है । उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिये ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आपके विनिर्णय के आगे सर झुकाता हूं । मेरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान थोड़ा है परन्तु "salubrious" का अर्थ है अच्छा और स्वस्थ वातावरण; इसमें कोई गलती नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : 'salubrious' शब्द से कोई आक्षेप नहीं लगता ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रो० हेम बरुआ भी मेरा समर्थन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वातावरण के अनुकूल होने पर आपत्ति नहीं की थी । परन्तु जब इसको पहले अनुकूल बताया गया था और फिर धीमापन का उल्लेख किया गया तो दोनों बातों के साथ कहने पर आक्षेप आता है । अतः माननीय मंत्री का कहना उचित था और उनको वह वक्तव्य देना चाहिये था ।

श्री हरिविष्णु कामत : मैं नहीं जानता कि आक्षेप का क्या अर्थ है । मैं ने कहा था 'कुछ धीमेपन से' । अगली सुनवाई छः महीने बाद अप्रैल में है . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, just now the hon. Minister stated and also Shri Chatterji advocated that the original of the instrument of accession of and its copy are safe. The question is that one copy was missing. There were two copies, one was with Maharao and the other with the Central Government. My question is whether one of the two copies has been lost and secondly, whether another important document of the British regime relating to delimitation of boundary especially of Kanjarkot area, has been lost, if so, how is it likely to influence the judgement of the Kutch Tribunal?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने महान्यायवादी से बातचीत की है और उसने मुझे कड़ी सलाह दी है कि लिखित, मौखिक या दस्तावेज के रूप में न्यायाधिकरण के सामने क्या साक्ष्य पेश किया जायेगा यह विषय विवाद का विषय नहीं होना चाहिये और यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। हमें ऐसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिये जिससे कि साक्ष्य के प्रमाणीकृत होने के बारे में कोई सन्देह पैदा हो जाये . . . (**व्यवधान**) मैं बैठ नहीं रहा हूं। इस तरह खड़े होने का कोई फायदा नहीं है।

Shri Madhu Limaye: What is the evidence kept .....

श्री स्वर्ण सिंह : जब किसी सदस्य पर अध्यक्ष की निगाह न पड़े उस सदस्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

Shri Madhu Limaye: I am speaking to the hon. Speaker why are you angry? He has no right to be angry. Why he is interrupting? **(Interruption).**

Mr. Speaker: Order. You should first hear the reply.

Shri Ram Sewak Yadav: Is he giving a reply or a sermon? **(Interruption).**

श्री स्वर्ण सिंह : हमने ऐसे बहुतेरे उपदेश सुने हैं और इस तरीके से चलने की हमारी कोई इच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह दस्तावेज़ गुम है ?

श्री स्वर्ण सिंह : बिल्कुल कुछ भी गुम नहीं है। हमारे कब्ज़े में क्या दस्तावेज़ हैं या हम किन किन दस्तावेज़ों को पेश करने का इरादा रखते हैं या वे कहां रखे हैं इनके बारे में मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करता हूं। यह जानकारी देना राष्ट्रहित में नहीं है।

Shri Madhu Limaye: Sir, my submission is what evidence have they kept. **(Interruption).** Sir, I want to appeal to you . . .

Mr. Speaker: You say something is missing. He says that nothing is missing.

Shri Madhu Limaye: My question was different. There were two original copies. Is one of the two copies missing?.....**(Interruption).** What evidence have they kept?

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, I rise on a point of order. Why this question is not answered categorically?

Mr. Speaker: I have got the answer from him. Shri Shree Narayan Das.

श्री श्रीनारायण दास : क्या न्यायाधिकरण ने प्रक्रिया सम्बन्धी सभी प्रश्नों का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो न्यायाधिकरण को निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय कर लिया गया है और वास्तव में दलीलें आरम्भ हो गई हैं। हमारे पक्ष ने अभिभाषण पहले ही समाप्त कर लिया है और मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान की ओर से न्यायाधिकरण के सामने अभिभाषण अब दिया जा रहा है। तब हम उत्तर देंगे। इस समय निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि फैसला किस समय तक उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 3 या 4 महीने और अवश्य लग जायेंगे।

श्री रंगा : इन प्रश्नों में न जाते हुए कि वहां पर भारत सरकार और कच्छ के महाराव के बीच हुए करार की तीन प्रतियां थीं या चार प्रतियां थीं या केवल एक प्रति थी और क्या वह एक प्रति गुम हो गई है और महाराव को दी गई कोई प्रति पेश की गई है या इस प्रकार का कोई प्रश्न, क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि महान्यायवादी सहित उपलब्ध उच्चतम विधि विशेषज्ञों द्वारा उनको यह सलाह दी गई है कि उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष स्वयं जो दस्तावेज़ रखी है वह हमारे प्रयोजनों के लिये काफी है और उससे हमारे राष्ट्र के मामले का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मेरे साथी श्री नि० चं० चटर्जी ने जो कि चर्चा के समय वहां उपस्थित थे सभा को आश्वासन दिया कि कोई दस्तावेज़ गुम नहीं है और जहां तक . . .

Shri Madhu Limaye: He has not said this. You should not hide anything behind the covering of what he said.

श्री स्वर्ण सिंह : . . . हमारे राष्ट्रीय हितों का सम्बन्ध है वे बहुत ही सक्षम हाथों में हैं और हमारे पास सभी सम्बन्धित साक्ष्य हैं । मैं कठिन नहीं होना चाहता और यह मेरी आदत भी नहीं है परन्तु राष्ट्रीय हित नाम की भी कोई चीज़ है और जब हमें हमारे अपने परामर्शदाता यह परामर्श देते हैं कि हमारे पास क्या दस्तावेज़ है, कहां पर है, क्या कोई चीज़ गुम है या मौजूद है या नहीं है के बारे में कोई भी चर्चा एक ऐसा मामला है जिस पर खुले आम या सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिये, मुझे उस सलाह को अवश्य स्वीकार करना चाहिये और सभा का संरक्षण चाहूंगा ।

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, I rise on a point of order. The hon. Member Shri Chatterji has nowhere stated in his speech whether the document is missing or not .....

Shri Madhu Limaye: He has simply stated that there is one instrument of accession.

Shri Ram Sewak Yadav: But the hon. Minister under the cover of his statement, has stated in his reply that he has answered those points also. This is not proper. Such doubts spread through the country whether some document is missing or not. Therefore, it would be proper if a clear answer comes from the Minister in this regard.

Mr. Speaker: He has given a clear reply.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में कच्छ के मामले को प्रस्तुत करने के लिये हमने कच्छ के महाराव से गुजराती में लिखे हुए सभी दस्तावेज़ प्राप्त कर लिये हैं और क्या वे हमारे कब्ज़े में हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : गुजराती, अंग्रेजी और मैं समझता हूं कि सिंधी में भी दस्तावेज़ों की संख्या बहुत बड़ी है । हमारे दल ने उनको देख लिया है जिसने कि उस क्षेत्र से लन्दन से तथा अन्य कार्यालयों से सभी साक्ष्य इकट्ठा करने में कई महीने तक काम किया है; सभी सम्बन्धित दस्तावेज़ इकट्ठे कर लिये हैं और हमारे कब्ज़े में हैं ।

श्री हेम बरुआ : श्री नि० चं० चटर्जी ने अभी कहा कि उन्होंने राज्यारोहण की लिखत को जिनीवा में देखा है । मैं उस दस्तावेज़ को प्रामाणिकता पर सन्देह नहीं करता । क्या यह सच नहीं है कि राज्यारोहण की मूल लिखत जिस पर कि जब लार्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे कच्छ

राज्य के प्रमुख तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए थे भारत सरकार की फाइलों से लापता थी और उसे लन्दन में हमारे उच्चायुक्त श्री जीवराज मेहता को महाराव से प्राप्त करना पड़ा था।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में कच्छ के महाराव का शामिल किया जाना हमारे लिये लाभकर होता या नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मामले को वकीलों का एक दल तैयार कर रहा है और हमारी ओर से बहस कर रहा है। जबकि हम सभी जानकारी को चाहे वह कहीं भी उपलब्ध हो प्राप्त कर सकते हैं यह साधारण व्यक्तियों का प्रतिनिधिमण्डल नहीं है।

श्री नाथ पाई : सर्वोपरि वकीलों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपनी पूरी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि यद्यपि भारत का पक्ष बहुत मजबूत है फिर भी इस मामले को उचित रूप से न्यायाधिकरण के समक्ष न रखने के कारण हम इसको हार सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमण्डल पूरा समय देकर काम कर रहा है जबकि हमारा प्रतिनिधिमण्डल ऐसा नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया है।

श्री नि० चं० चटर्जी : भारत के पक्ष का प्रतिनिधित्व पूरी तरह उचित रूप से तथा पर्याप्त रूप से किया गया है।

नागालैण्ड में युद्ध विराम की अवधि का बढ़ाया जाना

+

*123. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के ईसाई नेताओं ने राज्य में शान्ति समझौते की अवधि को 15 अक्तूबर, 1966 को समाप्त होने के बाद 45 दिन तक बढ़ा देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). चर्च नेताओं से भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है हालांकि रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने युद्ध विराम की अवधि 31 दिसम्बर, 1966 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया। बहरहाल छिपे नागाओं ने तार द्वारा यह प्रस्ताव किया था कि 15 अक्तूबर, 1966 से अवधि को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया जाये। सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और युद्ध-विराम की अवधि 15 दिसम्बर, 1966 तक बढ़ा दी गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : जहां तक मैं जानता हूं प्रधान मंत्री तथा छिपे नागा नेताओं में चार बार बातचीत हुई है। बातचीत के सद्भावना के वातावरण में होने के अतिरिक्त इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है।

श्री दिनेश सिंह : जिस समय बातचीत की प्रगति की जानकारी हम सभा को देते रहे हैं। अन्तिम बातचीत पर हम एक पूरा विवरण देंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : बातचीत कब तक चलेगी और क्या इस बातचीत के लिये जो कि दो वर्ष से भी अधिक से चल रही है हमारी ओर से या उनकी ओर से कोई समय सीमा रखी गई है ?

श्री दिनेश सिंह: ऐसी बातों के लिये कोई समय सीमा रखना बहुत कठिन है। जब तक कि नागालैंड में शान्ति रहती है और हम इस प्रश्न को शान्ति से हल करना चाहते हैं तब तक हमें बातचीत करनी होगी। बातचीत बहुत ही मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई है और मुझे आशा है कि हम नागा नेताओं को अपनी बात के लिये मना लेंगे।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the underground Nagas have been declared as absconders or not? Is it not disgraceful on the part of the Government to accept the telegram of absconded persons?

Shri Dinesh Singh: It is not disgraceful. They will certainly send telegrams in connection with the talks which we are holding with them.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या माइकल स्कॉट के चले जाने से नागा विद्रोहियों की हठधर्मी में परिवर्तन आया है और क्या वे भारत की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री दिनेश सिंह : माइकल स्कॉट की उपस्थिति से इस बातचीत में सहायता नहीं मिल रही थी। उनके जाने के बाद बातचीत ठीक चल रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या छिपे नागाओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधान मंत्री 14 मद वाले ज्ञापन पत्र से यह स्पष्ट है कि अब तक जो बातचीत हुई है उसमें उनकी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ; यदि हां, तो क्या इन परिस्थितियों में भारत सरकार के पास, छिपे हुए नागाओं के साथ समझौता वार्ता करने की जिम्मेदारी को सुसंगठित नागालैंड की सरकार को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वहां के हठधर्मी लोग यह पूरी तरह समझ लें कि भारत के विरुद्ध कोई भी सराहनीय कार्यवाही बेकार है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह नहीं कहूंगा कि बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रगति हुई है। इस प्रश्न पर हम एक पूरा विवरण देंगे। इसका सम्बन्ध केवल युद्ध विराम से है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि विस्तार की इस अवधि में विद्रोही नागाओं के कुछ वर्गों ने अपनी स्थिति मजबूत बनाने और अपनी सशस्त्र शक्ति को बनाने का प्रयत्न किया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, हमें समय समय पर समाचार मिले हैं कि नागा लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी ओर यह भी महसूस किया जाता है कि जब कि ये शान्ति वार्ता चल रही है इस मामले को शान्तिपूर्वक हल करने की उनकी तीव्र इच्छा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह खुशी की बात है कि बातचीत में प्रगति हुई है। यदि ऐसा है तो, क्या हम समाचारपत्रों की खबरों को गलत समझें कि यहां पर आये नागा विद्रोहियों ने कहा :

(क) कि वे किसी युद्धविराम में रुचि नहीं रखते ; और

(ख) कि वे भारत से पूर्ण स्वतन्त्रता की अपनी मूल मांग पर टिके हुए हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने पिछली बार कहा था कि नागाओं ने अपना दृष्टिकोण बताया है और हमने अपना दृष्टिकोय बताया । अभी बातचीत चल रही है और जब बातचीत चल रही होती है तो प्रगति होती है और शान्तिपूर्ण हल की हमेशा ही उम्मीद होती है ।

Shri M. L. Dwivedi: What are the reasons for the talks going on between Government of India and Underground Naga leaders being continuously postponed and blocked and are you hopeful of finding a solution to it in the near future?

Shri Dinesh Singh: Sir, when such talks are going on, it is very difficult to give a detailed account of it and this creates bottlenecks for the future talks. Since the talks are still going on, there is a scope for a peaceful solution being evolved. This House must appreciate that every time this issue is raised I have to repeat this answer. I think we should once consider It. Finally, this House is aware of the manner in which these talks are going on with the Nagas. This House also adopted that and we are also making efforts for that. We are hopeful of finding a peaceful solution.

Shri M. L. Dwivedi: I want to know the reasons of the deadlock in the talks.

Mr. Speaker: That he has already stated that going in detail blocks the way for further talks.

श्री स० चं० सामन्त : गिरजाघर के नेताओं द्वारा क्या कारण बतलाये गये थे और क्या उन कारणों से समय बढ़ाया गया है या सरकार ने अपनी ओर से समय बढ़ाया था ?

श्री दिनेश सिंह : इसका उत्तर मैंने मुख्य उत्तर में दे दिया है ।

श्री सुबोध हंसदा : अखबारों में यह समाचार आया है कि करीब 2500 नागा पूर्व पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए छिपे नागाओं ने युद्धविराम का समय बढ़ाने के लिये कहा है । क्या सरकार को इसका पता है और क्या यह सच है कि ये नागा पूर्व पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : भूमिगत नागाओं से इस बात का जिक्र किया गया था और उन्होंने इस बात के लिये इन्कार किया है कि पाकिस्तान में कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या गोली न चलाना संबंधी करार केवल नागालैण्ड तक ही सीमित है या मनीपुर के उखरूल उप-प्रभाग पर भी यह लागू होता है ?

श्री दिनेश सिंह : उखरूल उप-प्रभाग भी इस करार के अधीन है ।

Shri Ram Sewak Yadav: May I know whether it can be assessed from the conversation which took place between the representatives of Nagas and Government of India that Nagas are prepared to accept any other agreement other than the agreement for a fully independent state? I would like to know the number of people other than Nagas killed during such period till such conversation goes on or a cease-fire agreement is reached with them?

Shri Dinesh Singh: I have just told all this in details. The question of coming together arises only when both the parties have different points of view.

Shri Ram Sewak Yadav: This is not the answer of my question.

Mr. Speaker: The Minister cannot go into details of the conversations while they are going on.

Shri Ram Sewak Yadav: What about the second part of my question?

Shri Dinesh Singh: The information about it has been from time to time placed on the Table of the House.

श्री जोकीम अल्वा : क्या यह सच है कि साइमन आयोग के समय से ही नागा लोग एक पृथक् राज्य की मांग कर रहे हैं और उनकी इस मांग को समाप्त करने में काफी समय लगेगा ? क्या यह भी सच है कि भारत की प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण बनाये रखने की हमारी नीति दृढ़ है और यह बात नागा नेताओं को स्पष्ट रूप से बता दी गयी है ताकि वे सामूहिक रूप से इस पर विचार कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : बात ऐसी ही है। हमने अपना दृष्टिकोण उनके सामने रखा है।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether Government of India have received any such information since Michael Scott left this country that Naga hostiles have relations with some foreign countries and they have been continuously receiving the arms from them through Burma and Pakistan; if so, what steps Government have taken to check it?

Shri Dinesh Singh: It is being placed before the House from time to time. We conveyed our concern in this respect to Naga leaders. They deny it that they are sending some Nagas to foreign countries to collect the arms.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : बरमा सरकार पर यह जो आरोप लगाया गया है कि वह नागाओं को ऐसा करने के लिये उत्साहित करती है, वह बिल्कुल गलत है। हमारे बरमा सरकार से बड़े अच्छे संबंध हैं और दोनों सरकारें सद्भाव और सहयोग से कार्य करती हैं।

श्री रंगा : क्या सरकार को यह पक्का विश्वास है कि उसे नागालैण्ड के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री अंगामी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिलू आवो का इस संबंध में पूर्ण सहयोग, सहायता और मंत्रणा मिलेगी ? क्या सरकार नागा विद्रोहियों के साथ समझौता-वार्ता करने के संबंध में इन दोनों नेताओं से सम्पर्क बनाये हुये है ?

श्री दिनेश सिंह : नागालैण्ड सरकार का हमारे साथ निरन्तर सम्पर्क बना रहता है और हम उनके साथ सम्पर्क में रहते हैं। बात-चीत के दौरान नागालैण्ड के मुख्य मंत्री भी मौजूद थे।

श्री रंगा : क्या सरकार को भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शीलू आवो का सहयोग भी प्राप्त है।

श्री दिनेश सिंह : हमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री का सहयोग प्राप्त है।

श्री स्वैल : नागा नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ऐसा समाचार मिला था कि वार्ता सफलता-पूर्वक आगे बढ़ रही है, परन्तु नागा प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री कुघातो सुखई ने वार्ता समाप्त होने पर कलकत्ते में कहा कि बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है। इनमें से कौन सी बात सही है ? श्री कुघातो सुखई ने एक 14-सूत्रीय ज्ञापन भी जारी किया है। क्या सरकार उस ज्ञापन के उत्तर में कोई वक्तव्य जारी कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : भूमिगत नागाओं का प्रतिनिधि मंडल अपने साथियों से परामर्श करने वापिस गया है और इस हद तक बात सफल रही है। यह उनका कार्य है कि वे अपने साथियों से परामर्श करके हमें बतायें। यदि बातचीत आगे नहीं चलती तो हमें समझना चाहिए कि बातचीत ठप्प हो गयी है। जहां तक 14-सूत्रीय ज्ञापन का संबंध है, यह सच है कि श्री कुघातो सुखई ने एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया था। इसमें अधिकता भूतकालिक घटनाओं का उल्लेख है। हमने इस पर कोई विचार नहीं किया है क्योंकि अब हमारे वर्तमान संबंधों और भविष्य में होने वाले ताल-मेल का अधिक महत्व है।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री दिनेश सिंह : मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बारे में एक वक्तव्य दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं।

राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भारत के वैदेशिक-कार्य मंत्री का भाषण

*124. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० जो० नायक :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 सितम्बर, 1966 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "प्रातः संस्करण के समाचार पत्रों द्वारा भारतीय मंत्री के भाषण की उपेक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और क्या यह सच है कि ब्रिटेन के समाचार-पत्रों ने ब्रिटेन की सरकार के इशारे पर 8 सितम्बर, 1966 को राष्ट्र मण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भारत के वैदेशिक कार्य मंत्री के भाषण को जानबझ कर कोई स्थान नहीं दिया अथवा उसको कोई महत्व नहीं दिया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन की सरकार के साथ इस विषय पर बात-चीत की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) सरकार का ध्यान समाचार की ओर आकर्षित किया गया है लेकिन यह समाचार पूरी तरह ठीक नहीं है। लंदन के कुछ अखबारों में भाषण का सारांश छपा था और उसमें जो बातें उठाई गई थीं, उन पर प्रशंसात्मक टिप्पणी भी दी गई थी। सम्मेलन में किए गए भाषणों के मलपाठ प्रेस को सुलभ नहीं है क्योंकि सम्मेलन की कार्यवाही प्रकाशित नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं।

श्री श्रीनारायण दास : मंत्री महोदय ने बताया कि जो समाचार छपा था, वह बिल्कुल सच नहीं था। उनके भाषण का किस हद तक प्रकाशन होना चाहिए था क्योंकि उसका इतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे लिये यह बताना तो मुश्किल है कि उनके भाषण का कितना प्रचार होना चाहिए था, परन्तु इसका हमारे देश में काफी प्रचार हुआ जहां लोग यह जानने के इच्छुक थे कि हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने क्या कहा है।

श्री श्रीनारायण दास : मंत्री महोदय के भाषण में क्या बात ऐसी थी जो ब्रिटेन के समाचार पत्रों को अच्छी नहीं लगी ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे इसका पता नहीं है।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is a complaint of our Foreign Minister himself that his full speech has not been given to the British press; if so, what steps he has taken in respect thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): I am not concerned with the publicity of my full speech in any foreign country, if it has got full publicity in our own country. A countries policy has effect on press also. What we said about Rhodesia was unpolatable to British Press.

Shri Kishen Pattnayak: Is it a fact that British Government have congratulated the Indian delegation for adopting a moderate attitude on Rhodesian issue, and they have not cared for the discontent expressed by African countries over it?

Shri Dinesh Singh: Congratulations are always welcome from whatever quarter it comes. It is apparent that we have very good relations with African countries and they have selected our Foreign Minister as their spokesman for representing their view on this issue.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि राष्ट्र मण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के समाप्त होने पर हमारे विदेश मंत्री ने लन्दन में यह कहा था कि राष्ट्रमण्डल इस सम्मेलन के बाद अधिक शक्तिशाली बन गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रोडेशिया के मामले पर राष्ट्र मण्डल के टूट जाने का खतरा पैदा हो गया था और सभी अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रमण्डल छोड़-देने की धमकी दी थी, क्या हमारे विदेश मंत्री उपरोक्त समाचार की अपने अनुमान के आधार पर पुष्टि करते हैं।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने स्वयं ही यह कहा है कि राष्ट्र मण्डल टूटते टूटते बचा है। इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रमण्डल की शक्ति और बढ़ गयी है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को यह पता है कि ब्रिटेन में कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो भारतीय आकाक्षाओं का राजनैतिक स्तर पर विरोध करते हैं, यदि हां, तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि हमारे कुछ भूतपूर्व प्रशासक हमारे स्वतन्त्र होने पर अप्रसन्न हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। अगला प्रश्न।

इन्डोनेशिया के पाकिस्तान स्थित राजदूत का वक्तव्य

+

*125 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डोनेशिया के पाकिस्तान स्थित राजदूत द्वारा 10 सितम्बर, 1966 को कराची में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इण्डोनेशिया अब भी काश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में इण्डोनेशिया को भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट बताने के लिये क्या कार्रवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां। सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान में इण्डोनेशिया के स्वर्गीय राजदूत ने, अपने विश्वास-पत्र प्रस्तुत करने के बाद, यह कहा था कि इण्डोनेशिया सरकार ने हाल के परिवर्तनों के बावजूद कश्मीर पर हमारे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस बात की पुन: पुष्टि की कि इण्डोनेशिया, श्री भुट्टो और आदम मलिक के बीच हुई बातचीत के बाद जारी की गई सम्मिलित विज्ञप्ति से अब भी आबद्ध है।

(ख) और (ग). गत सितम्बर मास में जब इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री, श्री आदम मलिक भारत की यात्रा पर आए थे, तब कश्मीर पर तथा भारत-पाकिस्तान संबंधों पर पुन: जोर देकर भारत के निश्चय से अवगत करा दिया गया था। इस विषय पर इण्डोनेशिया सरकार के विचार श्री मलिक की भारत-यात्रा के बाद जारी की गई सम्मिलित विज्ञप्ति के निम्नलिखित वाक्य में दिए गए हैं :—

> "इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे मामले शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किए जाएंगे जिसके लिए ताशकन्द घोषणा में आधार मौजूद हैं।"

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य देकर कि भारत और पाकिस्तान को काश्मीर संबंधी विवाद का हल काश्मीर की जनता की इच्छाओं के अनुकूल करना चाहिए, पाकिस्तान की इस मांग का समर्थन किया है कि काश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि अखबारों में एक ऐसा समाचार छपा था कि इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने काश्मीरी लोगों की इच्छा की बात कही है परन्तु यह बात वक्तव्य में नहीं कही गयी थी। यह केवल अखबारों की खबर थी जिसे शायद पाकिस्तान ने बाद में जोड़ दिया होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: सऊदी अरब के बादशाह द्वारा प्रेरित अखिल इस्लामी संगठन का पाकिस्तान और इन्डोनेशिया के पारस्परिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री दिनेश सिंह: हमें इस प्रकार के किसी अखिल इस्लामी संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi: The ambassador of Indonesia in Pakistan has said that Indonesia supports Pakistan on Kashmir issue. May I know whether Government have received any assurance from Indonesia that Indonesia favours Indian side on this issue?

Shri Dinesh Singh: As far as the Joint Communique issued after the conversation of Adam Mallik with Z. A. Bhutto is concerned, it did not contain

any statement to this effect. It only states that all the problems between the two countries should be resolved peacefully. I referred to that.

Shri M. L. Dwivedi: I would like to know whether Indonesia supports India on this issue?

Mr. Speaker: It is quite a different question.

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार ने इन्डोनेशिया की सरकार का ध्यान इस खबर की ओर दिलाया है जिससे पाकिस्तान द्वारा जोड़ा गया बताया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : हम पूरे विवरण के मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

डा० म० मो० दास: क्या सरकार इन्डोनेशिया की गृह तथा विदेश नीति के बारे में यह सोचती है कि इन्डोनेशिया की नीति में विशेषकर काश्मीर के सम्बन्ध में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन आयेगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रकल्पित उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इन्डोनेशिया द्वारा भारत में एक शिष्टमंडल भेजे जाने के उत्तर में एक शिष्टमंडल वहां भेज कर काश्मीर पर अपनी नीति से उन्हें अवगत कराया जाये ?

श्री दिनेश सिंह : कार्यवाही के लिए यह एक सुझाव है ।

Shri Rameshwaranand: The hon. Minister has just stated that it was not understood from the statement made by the Foreign Minister of Indonesia that they support Pakistan on the Kashmir issue. May I know the essence of his statement? Do the Government of Indonesia hold this view that Kashmir is under our control and if not, has he tried to make them understand the reasons due to which Kashmir is under our control?

Mr. Speaker: This is a different question.

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को यह मालूम है कि इन्डोनेशिया में सरकार के बदल जाने के पश्चात् वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान की तुलना में भारत के बारे में अधिक सख्त रवैया अपनाया है और यदि हां, तो सरकार ने इन्डोनेशिया के साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : यह हमारा मूल्यांकन नहीं है कि उन्होंने सख्त रवैया अपनाया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि कम-से-कम पाकिस्तान के विदेश मंत्री तथा इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में काश्मीर को एक विवादग्रस्त राज्यक्षेत्र बताया गया है और बल्कि उन्होंने तो काश्मीर विवाद को जिसे हम एक विवाद नहीं मानते हैं, सम्मानपूर्वक तथा शान्ति पूर्वक सुलझाने का सुझाव भी दिया है और यदि हां, तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि इन्डोनेशिया की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ? वे हमारे साथ मित्रता गांठने का प्रयत्न कर रहे हैं और वे पाकिस्तान के साथ भी मित्रता गांठने का प्रयत्न करते रहे हैं ।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैं ने कहा, हम विवरण के सही पाठ के मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

वियतनाम के विसैन्यीकृत क्षेत्र में बमबारी

+

*126 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
डा० रानेन सन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर वियतनाम की सरकार ने वियतनाम संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को इस वर्ष सितम्बर, 1966 में वियतनाम के विसैन्यीकृत क्षेत्र में अमरीका द्वारा की गई बमबारी के विरुद्ध विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का प्रधान होने के कारण इस विषय में सरकार का क्या मत है ; और

(ग) वियतनाम के दोनों पक्षों की पारस्परिक बातचीत कराने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उन प्रयासों का अब तक क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार यह देखने को उत्सुक रही है कि दोनों पक्ष विसैन्यीकृत क्षेत्र के बपर दर्जे का आदर करें और उसने 1954 के जेनेवा करार की व्यवस्थाओं के अनुरूप उस दिशा में सभी कदम उठाने की कोशिश भी की है।

(ग) भारत सरकार ने वियतनाम समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान पाने में सहायता देने के लिए राजनयिक सूत्रों के जरिये कई बार कोशिशें की हैं। आम तौर पर भारत की कोशिशों की सराहना की गई है लेकिन युद्ध में लगे विभिन्न पक्षों के बीच मतभेद अभी दूर नहीं हो पाए हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : राष्ट्रपति जानसन द्वारा 5 सितम्बर को लंकेस्टर में दिये गये वक्तब्य को, जिस में उन्होंने दक्षिण वियतनाम से अमरीकियों को इस शर्त पर निकालने के लिए समय निश्चित करने की पेशकश की थी कि उत्तर वियतनाम द्वारा भी ऐसी ही कार्यवाही की जाये, ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस पेशकश का ब्यौरा मंगाने और इस आधार पर चलते हुए विरोधी पक्षों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार किया है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं, हम इस पेशकश के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। पहले तो यह स्वीकार्य नहीं होगी और दूसरे हमारी इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि उत्तर वियतनाम में बमबारी बिना किसी शर्त के बन्द कर देनी चाहिए।

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि संयुक्त अरब गणराज्य दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम तथा चीन का भी मित्र है, क्या सरकार का विचार संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति से यह अनुरोध करने का है कि वह विरोधी पक्षों को एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार करें ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति को ऐसा कहने का हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी पक्ष अर्थात न ही उत्तर वियतनाम और न ही दक्षिण वियतनाम, जेनेवा समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है । क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग विसैन्यीकृत क्षेत्र पर आक्रमण रोकने में असफल सिद्ध हुआ है, इसलिए क्या इस आयोग के सभापति के रूप में कार्य करते रहना अब भी आवश्यक है ?

श्री दिनेश सिंह : यही एक बात है जिस पर सभी पक्ष सहमत हैं कि आयोग अपना कार्य करते रहें ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच नहीं है कि 1954 के जेनेवा समझौते में एक विशिष्ट खंड था जिसमें यह कहा गया था कि सभी विदेशी सैनिकों को निश्चित समय में दक्षिण तथा उत्तर वियतनाम को अवश्य खाली कर देना चाहिए और यदि हां, तो जब भारत सरकार विरोधी पक्षों को जेनेवा के प्रकार का अथवा जेनेवा सम्मेलन के लिए तैयार करने हेतु अभी प्रयत्न कर रही है तो भारत सरकार द्वारा यह मांग न करने के क्या कारण हैं कि वियतनाम से विदेशी सैनिकों को निकाल लिया जाये ?

श्री दिनेश सिंह : यह कहना सही नहीं है कि भारत सरकार ने यह मांग नहीं की है ; हमने कहा है कि वहां से सभी विदेशी सैनिक वापस बुला लिये जायें ।

श्री दी० चं० शर्मा : ब्रिटेन और सोवियत संघ जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापति थे । क्या इन दो देशों की सरकारें जेनेवा सम्मेलन को पुनः बुलाने के लिए सहमत हैं और यदि नहीं, तो इन में से कौन जेनेवा सम्मेलन को पुनः बुलाने के पक्ष में नहीं है ?

श्री दिनेश सिंह : दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं । यह एक उलझा हुआ प्रश्न है और इस का एक साधारण उत्तर देना बहुत कठिन है ।

श्री नाथ पाई : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न संख्या 667 को, जिसका दायरा बहुत ही विस्तृत है अतारांकित प्रश्न के रूप में रखा गया है, हालांकि मैं ने नियम 36 और 37 की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें अपना प्रश्न पूछना चाहिए ।

श्री नाथपाई : आपको हमारी शिकायतें जाननी चाहिएं ।

क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं कि इन चार भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी वक्तव्यों अर्थात (क) उन द्वारा वाशिंगटन में दिया गया संयुक्त वक्तव्य, (ख) उन द्वारा काहिरा, बेलग्रेड और मास्को के शानदार दौरे पर जाते समय ले जाये गये प्रस्ताव, (ग) उन द्वारा मास्को में दिये गये वक्तव्य और (घ) शिखर सम्मेलन के पश्चात् जारी की गई विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की इस निर्दयतापूर्ण संघर्ष तथा इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): मेरे विचार में इन वक्तव्यों में कोई परस्पर विरोध नहीं है । हमारी स्थिति इस सभा में और कई अन्य अवसरों पर स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

*127. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती विमला देवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सम्बन्धी प्रसारण आरम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह प्रसारण कब से आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है और इस पर सरकार का निर्णय यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा ।

टेलीविजन उपकरणों का निर्माण

*128. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 25 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पारेषण (ट्रांसमिटिंग) उपकरणों की सप्लाई तथा धीरे धीरे उनका निर्माण करने में सहयोग प्राप्ति के लिए विदेशी फर्मों/संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). भारत ऐलक्ट्रोनिक्स लि० ने, जिनको विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने का काम सौंपा गया था, इन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है और आशा है कि शीघ्र ही प्रस्ताव मिल जायेंगे । सरकार आशा करती है कि रिपोर्ट प्राप्त होते ही निर्णय कर लिया जाएगा ।

आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकायें

*129. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं का प्रकाशन एक करार के अन्तर्गत गैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) इस व्यवस्था से इस समय इन पत्रिकाओं के प्रकाशन में होने वाली हानि कहां तक कम हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). अभी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसलिए अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कब तक क्रियान्वित हो जाएगा और इस व्यवस्था के कारण आकाशवाणी की पत्रिकाओं में होने वाली हानि कहां तक कम हो जायेगी।

पाकिस्तान द्वारा वायु-सीमा का तथा युद्ध विराम का उल्लंघन

130. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 सितम्बर से 30 अक्टूबर, 1966 तक की अवधि में पाकिस्तान ने भारतीय राज्य क्षेत्र में कितनी बार वायु-सीमा का तथा युद्ध-विराम का उल्लंघन किया ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) 1 नवम्बर, 1966 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सितम्बर के पश्चात् पाकिस्तान ने 3 अन्तरिक्ष अतिक्रमणों समेत जम्मू तथा काश्मीर में 236 युद्ध विराम उल्लंघन किये हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अन्तराष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय अन्तरिक्ष के दो उल्लंघन किये हैं।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में सभी युद्ध-विराम उल्लंघनों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को शिकायतें भेजी गई हैं। पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा रणवीर सिंह पुरा क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार अतिक्रमण के एक प्रयास को हमारी सुरक्षा सेनाओं ने निष्फल कर दिया था। चूंकि पाकिस्तानियों द्वारा गोलाबारी जारी रही सेक्टर कमांडरों की बैठकें आयोजित की गई थीं। जिनके फलस्वरूप 11 नवम्बर, 1966 को युद्ध-विराम हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार अन्तरिक्ष उल्लंघनों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजे गये हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर

*131. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामान्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
डा० म० मो० दास :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 8 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के भारत विरोधी प्रचार का खंडन करने के लिए भारत-चीन सीमाओं पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के सम्बन्ध में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): ट्रांसमीटर लगाने, स्थान और सामान हासिल करने और इमारतें बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है । सीमावर्ती क्षेत्रों में इन ट्रांसमीटरों की प्रगति की अवस्था का ब्योरा देना जन हित में नहीं होगा ।

ताशकन्द घोषणा की व्याख्या

*132. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने यह कह कर कि काश्मीर भारत का अंग नहीं है, ताशकन्द समझौते को एक नई चुनौती दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) अपने एक नोट में पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके अनुसार यह सच नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत संघ का अंग राज्य है ।

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को बता दिया है कि इस विषय पर उनके विचार कानून और तथ्यों से मेल नहीं खाते । सरकार ने इन विचारों को अस्वीकार कर दिया है ।

पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच इस विषय पर जिन नोटों की अदला-बदली हुई है वे सदन की मेज़ पर रख दिए गए हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 7230/66**]

चीन द्वारा विस्फोट

*133. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा अणुबम का विस्फोट किये जाने के बाद तथा एक के बाद दूसरा विस्फोट करते रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या इसके बारे में चीन के सीमावर्ती देशों में हुई प्रतिक्रिया का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुमान का क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) परमाणुबम बनाने के बारे में इन देशों का इस समय क्या मत है ;

(घ) क्या चीन द्वारा बमों का विस्फोट किये जाने के बाद से उनके रवैये में कोई अन्तर आया है; और

(ङ) क्या यह सच है कि चीन की परम णु शस्त्रास्त्र संबन्धी प्रगति के कारण चीन के कुछ सीमावर्ती देशों में आतंक की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा अब उनकी विदेश नीतियों पर इस आतंक का प्रभाव पड़ रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मास्को आंशिक परीक्षण रोक संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में चीन के अधिकांश पड़ौसी देश उसके द्वारा विश्व के जनमत की अवहेलना पर अप्रसन्न हैं। जबकि व्यर्थ चिंता और घबराहट का कोई संकेत नहीं है, तो भी नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्रों द्वारा हाल में किए गए अणु अस्त्र विस्फोट से एशिया के वे देश जिनका चीन दुश्मन है, चीन के बढ़ते हुए खतरे को समझ गए हैं। केवल उत्तर विएतनाम, उत्तर कोरिया और कम्बोडिया ने चीन के आणविक विस्फोटों का स्वागत किया।

(ग) इन्डोनेशिया में 1964 और 1965 में एक अणु बम बनाने के प्रस्ताव के बारे में कुछ बात हुई थी। इस क्षेत्र की किसी अन्य सरकार ने ऐसा बम बनाने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है।

(घ) इस क्षेत्र के अधिकांश देशों को चीन से सैनिक और राजनीतिक खतरे की जानकारी है। उन के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है।

(ङ) सरकार के पास इस विषय पर इस तथ्य के अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है कि चीन के ताजे विस्फोट से बहुत से देशों को काफी चिंता हुई है।

सेनाध्यक्ष का रूस का दौरा

*134. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 में सेनाध्यक्ष के रूस के दौरे का क्या प्रयोजन था ; और

(ख) रूसी अधिकारियों के साथ हुई उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मुख्य बलाधिकरण यू० एस० एस० आर० के चिरकाल के एक निमंत्रण के उत्तर में यह एक सद्भावना यात्रा थी।

(ख) यात्रा से सद्भावना अंकुरित हुई है और उसने दोनों देशों के वर्तमान मैत्रीपूर्ण संबन्धों को और दृढ़ बनाया है ।

भारत तथा पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्रियों की मुलाकात

*135. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन में तथा न्यूयार्क में उनकी पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री के साथ औपचारिक मुलाकात हुई थी ;

(ख) उन बैठकों में किन-किन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) क्या पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री ने लन्दन हवाई अड्डे पर दोनों देशों के विवादों को उठाने की कोशिश की थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मैं कई मौकों पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भोरज़ादा से मिला था; इनमें लन्दन का वह रात्रि भोज भी शामिल है जिसमें वह मेरे साथ थे और बाद में न्यूयार्क की एक रात्रि-भोज पार्टी में भी मैं उनसे मिला था जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। हमारी कोई औपचारिक बैठकें नहीं हुईं। हमारी बातचीत के दौरान हमने अन्य बातों के अलावा भारत-पाक सम्बन्धों पर चर्चा की ?

(ग) मैं लन्दन हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से नहीं मिला ।

सूचना तथा प्रसारण के माध्यमों सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन

*136. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री फिरोडिया :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती विमला देवी :
श्री राम सहाय पाण्डय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 25 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन को कहां तक कार्यरूप दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). चन्दा समिति की 55 सिफारिशों पर सरकार का निर्णय 24 अगस्त, 1966 को सदन की मेज पर रख दिया गया था। तब से 125 और सिफारिशों पर निर्णय कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन की मेज पर शीघ्र ही रख दिया जायेगा। 39 सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है। निर्णयों को कार्यान्वित करने का काम जारी है।

पाकिस्तान के लिए चीन की पनडुब्बियां

*137. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री तुला राम :
डा० पू० ना० खां :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बड़े :
श्री किन्दर लाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल में पाकिस्तान को अपनी कुछ पनडुब्बियां दे दी हैं; और पाकिस्तान फ्रांस से भी कुछ पनडुब्बियां प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है ;

(ख) क्या पनडुब्बियां दिये जाने तथा तत्सम्बन्धी बातचीत से भारतीय समुद्र तट की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पाकिस्तान द्वारा चीन से किसी पनडुब्बी की अधिप्राप्ति के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तदपि रिपोर्ट है कि पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से एक करार सम्पूर्ण हुआ है जिसके अनुसार पाकिस्तान को तीन पनडुब्बियां प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग). भारत को पनडुब्बियों से संकट का निरंतर ध्यान है और उसका सामना करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों के विस्तार प्रकट करना लोक हित में नही होगा।

Radio Lhasa

*138. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to broadcasts by a person named Yashpal Panda from Radio Lhasa in Tibetan language wherein the prosperity of Tibet without Dalai Lama and condition of Tibetan refugees in India has been described; and

(b) if so, the steps taken by Government to counteract such propaganda?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) **No,** Sir.

(b) Does not arise.

चीन द्वारा घुसपैठ

*139. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री फिरोडिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री नाथ पाई :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कृ० चं० पंत

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी चीन द्वारा 7 सितम्बर 1966 के बाद बड़े पैमाने पर कोई घुसपैठ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : एक विवरण जिसमें 7 सितम्बर 1966 से अब तक भारतीय तथा सिक्किम के राज्य क्षेत्र में की गई घुसपैठ का ब्योरा दिया हुआ है, सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 7231/66] इसे बड़े पैमाने पर घुसपैठ नहीं कहा जा सकता। चीन सरकार को विरोध-पत्र भेज दिये गये हैं।

मंत्रियों की आस्तियां तथा देनदारियां

*140. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** 9 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक मंत्री को प्रधान मंत्री को प्रति वर्ष अपनी आस्तियों तथा देनदारियों का विवरण देना होता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष किस तिथि तक;

(ग) क्या उनकी जांच की जाती है और यदि हां, तो किसके द्वारा ;

(घ) प्रधान मंत्री की आस्तियों, देनदारियों तथा व्यापार सम्बन्धी हितों का विवरण किसको दिया जाता है; और

(ङ) क्या आचार संहिता सभा पटल पर रखी जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्तिमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) 31 मार्च तक ।

(ग) प्रधान मंत्री इन्हें देखते हैं।

(घ) अपने साथियों के विवरणों के साथ प्रधान मंत्री भी अपनी आस्तियों, देनदारियों का विवरण अभिलेख में रख देते हैं हालांकि प्रधान मंत्री से सम्बन्धित इस मामले के बारे में संहिता में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है।

(ङ) 18 नवम्बर, 1964 को संहिता की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई थी।

चीनी सेनाओं का जमाव

*141. **श्री फिरोडिया :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बसुमतारी :
श्री कृ० चं० संत :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत चीन सीमा के सभी मोर्चों पर हाल में चीनी सेनाओं का भारी जमाव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) चीनियों का पर्याप्त संख्या में स्थापत्य तिब्बत में जारी है और वह समस्त सीमा पर अपने लाजिस्टिक सामर्थ्य में सुधार कर रहे हैं। यद्यपि कोई नए जमाव नोटिस में नहीं आए चीनीयों का उत्तर पूर्वी सीमा के पार कबाइली जनता में शत्रुतापूर्ण प्रचार जारी है ।

(ख) देश की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित उपाय किए गए हैं।

मद्रास अणु बिजलीघर

*142. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास अणु बिजलीघर के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सन्तोषजनक व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित विदेशी मुद्रा कहां से उपलब्ध होगी और उसकी शर्तें—संक्षेप में क्या होंगी; और

(ग) क्या अवमूलन के पश्चात् इस बात का अनुमान पुनः लगाया गया है कि इस बिजलीघर पर कुल कितनी पूंजी खर्च होगी तथा कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यद्यपि इस परियोजना के लिये अब तक कोई विदेशी ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि इसकी उच्च प्राथमिकता तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए हम किसी देश विशेष से सहायता लिये बिना इसे स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं।

(ग) जी, हां। अनुमान है कि अवमूल्यन के पश्चात इस पर 29 करोड़ रुपये की विदेशी मद्रा की आवश्चकता पड़ेगी ।

पाकिस्तान को सैनिक सामान की सप्लाई

*143. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके द्वारा पिछले सत्र में दिये गये वक्तव्य के बाद से पाकिस्तान ने अब तक और क्या-क्या सैनिक सामान प्राप्त किया है; और

(ख) सरकार द्वारा अमरीका, कनाडा, जर्मनी तथा ईरान को पूर्व प्रकट किये गये विरोध की प्रतिक्रिया तथा परिणाम क्या रहे हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (अ० म० थामस) : (क) 8 अगस्त को रक्षा मंत्री द्वारा उल्लिखित सप्लाइयों के अतिरिक्त, रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान ने 200 से अधिक विमान ध्वंसक तोपें और अन्य फुटकर साज सामान प्राप्त कर लिया है और फ्रांस में दो पनडुब्बियों का आर्डर दिया है।

(ख) यू० एस० ए० ने भारत और पाकिस्तान को केवल अधातक साज सामान बेचने की नीति दुहराई है। पाकिस्तान में प्राप्त अधिकतर एफ०–86 विमान ईरान को वापस चले गए हैं, और उसके पश्चात एफ०–86 विमानों का कोई विक्रय नहीं हुआ।

रूस के विदेश उपमंत्री की भारत यात्रा

*144. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस के विदेश उपमंत्री सितम्बर, 1966 में भारत आये थे ;

(ख) उनके साथ क्या बातचीत हुई थी; और

(ग) क्या निर्णय हुए?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उप विदेश मंत्री, श्री एन० पी० फिरयूबिन ने 22 से 25 सितंबर 1966 तक भारत की यात्रा की।

(ख) श्री फिरयूबिन के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और भारत-सोवियत संबंधों पर विचार-विनिमय हुआ।

(ग) इस विचार-विमर्श का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर दोनों सरकारों द्वारा अपने-अपने विचार एक–दूसरे के सामने रखना मात्र था। इस कारण, किसी तरह के निर्णय का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान अणु ऊर्जा परियोजना

*145. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान अणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण-कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पीछे रही है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) अवमूल्यन का इसकी मशीनरी की लागत तथा इसके निर्धारित निर्माण कार्य-क्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) राजस्थान अणु-शक्ति परियोजना के 200 मेगावाट बिजली के पहले एकक के निर्माण-कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 4 महीने पीछे चल रही है। आशा है कि यह 1969 के अन्त तक चालू करने के लिये तैयार हो जायेगा ।

रुपये के अवमूल्यन से पहले एकक के लिये आयातित मशीनों के मूल्य में 11.25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अवमूल्यन का निर्माण-कार्य के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रवेश

146. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने सितम्बर, 1966 में भारत सरकार को एक नया ज्ञापन भेजा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को शामिल किये जाने के पक्ष में विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया बताई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त का स्मारकपत्र

147. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने सरकार को एक स्मारकपत्र दिया है जिसमें संसद् में अगस्त, 1966 में गैर-सरकारी सदस्यों के उस एक विधेयक के पुरःस्थापन के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी भारतीय नागरिक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रोजगार प्राप्त करने तथा उस राज्य में सम्पत्ति का मालिक बनने का अधिकार देने का उपबन्ध करना है ;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक के विरोध में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा क्या बुनियादी तर्क पेश किये गये हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह : (क) से (ग):—नई दिल्ली में 5 सितंबर, 1966 को विदेश मंत्रालय को दिए गए पाकिस्तान हाई कमीशन के स्मारक-पत्र और उसके उत्तर की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 7232/66]

सऊदी अरब की पाकिस्तान को सहायता सम्बन्धी लोक समिति

148. **श्री दे० द० पुरी**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सऊदी अरब में पाकिस्तान को सहायता देने के लिए आरम्भ किये गये आन्दोलन के पश्चात् सऊदी अरब की पाकिस्तान को सहायता सम्बन्धी लोक समिति द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में सरकार को पता है;

(ख) क्या भारत तथा सऊदी अरब के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को दृष्टि में रखते हुए सऊदी अरब की सरकार से इस मामले में बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सऊदी अरब में गैर सरकारी समितियों ने लगभग 20 लाख रियाल इकट्ठे किए और उन्हें जेद्दा-स्थित पाकिस्तान के राजदूतावास को सौंप दिया ।

(ख) जेद्दा में और यहां पर सऊदी अरब के राजदूत के जरिये इस आशय की गंभीर शिकायतों के जवाब में, कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत-पाकिस्तान के मामलों में पक्षपात न दिखाया जाए, हमें सऊदी अरब ने यह कहा कि पाकिस्तान को कोई ऋण नहीं दिया गया है। लेकिन प्राइवेट दलों द्वारा किए गये संग्रहों के बारे में कोई खास विरोध प्रकट नहीं किया गया।

People of Indian Origin in Foreign Countries

*149. **Shri Vishram Prasad:**
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Daljit Singh:
Shri Ramapathi Rao:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the foreign countries from where the persons of Indian Origin are being compelled to come back to India;

(b) whether Government propose to prevent such repatriates from coming over to India by using diplomatic influence; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) A large number of Indian nationals and persons of Indian Origin have returned from Burma. Some have returned from the East African countries as well. Return of about 5 lacs of persons of Indian Origin is provided under the Indo-Ceylon Agreement.

(b) and (c). Diplomatic channels are utilised according as the necessity arises. Particular care is taken to see that persons of Indian origin are not forced to come to India against their wishes.

African Broadcasts about Food Situation in India

***150. Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that misleading news bulletins have been broadcast in the African countries about food situation in India;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the steps taken to counteract the same?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). Some exaggerated reports emanating from world news agencies have received publicity on the Radio and in the Press in certain African countries.

(c) Corrective action was and continues to be taken by our Diplomatic Missions as necessary. Official contradictions have also received publicity in these countries.

सैनिक समाचार

635. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैनिक समाचार में सहायक पत्रकारों से उनकी सेवा की शर्तों और वेतनक्रमों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या उन्होंने यह मांग की है कि अन्य मंत्रालयों और केन्द्रीय सूचना सेवा के सहायक पत्रकारों को जो सेवा की शर्तें उपलब्ध हैं उन पर भी वह ही सेवा की शर्तें लागू की जायें ;

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या एक प्रतिरक्षा सूचना सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जब से 1963 में सहायक पत्रकारों के स्थानों का निर्माण हुआ है, सेवा की शर्तों और वेतन मान के सम्बन्ध में इन पदों को धारण करने वालों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक समाचार

636. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक समाचार के लेखकों से कम भुगतान और देर से भुगतान के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) लेखकों को इस समय किन दरों पर भुगतान किया जाता है ; और

(ग) क्या इन दरों में संशोधन करने के कोई प्रस्ताव हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग) वर्तमान पारिश्रमिक दरों के विरुद्ध लेखकों से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है :—

(1) **गद्य लेख** (यथानुपात 1000 शब्दों के अन्दर) 12 रुपये 50 पैसे से 40 रुपये तक प्रति 1000 शब्द और अधिकाधिक 50 रुपये प्रति हजार हजार जो किसी अंक में प्रकाशित प्रति लेख के लिए किसी लेखक को दिया जाता है ।

(2) **कविताएं**—7 रुपये से 25 रुपये प्रत्येक ।

(3) चित्र, रेखाचित्र, कार्टून इत्यादि 5 रुपये से 50 रुपये प्रत्येक ।

उपरोक्त सीमाओं के अन्तर्गत वास्तविक अदायगी की राशि प्रत्येक लेख के गुणस्वरूप को आंकते निर्धारित की जाती है ।

(4) तदपि अच्छे लेख आकर्षित करने के लिए पारिश्रमिक की वर्तमान दरों के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है ।

लेखक को पारिश्रमिक उस का लेख सैनिक समाचार में प्रकाशित होने के पश्चात् और जभी आवश्यक उपचार सम्पूर्ण हो जाते हैं, दिया जाता है ।

अदायगी में विलम्ब की शिकायतों की जांच की जाती है और अदायगी शीघ्र कर देने के यत्न किए जाते हैं ।

लोक सम्पर्क निदेशालय

637. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में और दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर लोक सम्पर्क निदेशालय में कितने अधिकारी हैं ;

(ख) लोक सम्पर्क निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कितने कितने और कौन कौन से वर्ग के कर्मचारी हैं ;

(ग) निदेशालय में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अवैतनिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या क्या है तथा उनके सम्बन्धित रैंक क्या हैं ; और

(घ) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जनता तथा समाचार पत्रों द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के लोक सम्पर्क निदेशालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) स्वीकृत जनशक्ति में मुख्यालयों में 22 राजपत्रित अफसरों और 62 अराजपत्रित कर्मचारियों का उपबन्ध है, और क्षेत्रीय तथा फील्ड यूनिटों में 29 राजपत्रित अफसरों तथा 42 अराजपत्रित कर्मचारियों का ।

(ग) नियमित कमीशन प्राप्त अफसर 13

ग्रुप कैप्टेन . . .	1
ले० कलनल . . .	3
मेजर-स्क्वा० लीडर-लें० कोमोडोर	8
कैप्टेन	1
योग	13

मानपदसेवी अफसर . 16

कलनल	1
ले० कलनल-कोमोडोर	1
मेजर	7
कैप्टेन-लैफ्टिनेंट . .	7
योग	16

(घ) त्रुटियों का, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श सहित एक वृहत् अध्ययन किया गया है, और इन त्रुटियों को यथा सम्भव दूर करने के लिये उपाय किए जा रहे हैं ।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

638. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय पर्वतारोहण संस्था की मुख्य पाठ्यचर्या क्या है ;

(ख) इस संस्था में प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ; और

(ग) इस संस्था में भर्ती होने के लिये किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) (क) तथा (ख) हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग लड़कों और लड़कियों के लिए बेसिक एडवांस और पाठ्यक्रम चलाती है । प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 35 दिन है ।

(1) बेसिक पाठ्यक्रम

थ्योरिटिकल पाठ्यक्रम में शामिल है नक्शा पढ़ने, हिमालय के वनस्पत्य और पशुओं, पर्वतीय संकट, स्वास्थ्य और सफाई, साज सामान की देख रेख और अन्य सम्बद्ध विषयों में निर्देशन ।

फील्ड प्रशिक्षण में चट्टानों पर चढ़ने, बर्फ और हेम कार्य तथा दराड़ों से उद्धार की तकनीकें बेस कैम्प में सिखाई जाती हैं, जो लगभग 14000 फुट ऊंचा होता है। विद्यार्थियों को लगभग 19000 फुट की ऊंचाई तक चढ़ना होता है ।

(2) एडवांस पाठ्यक्रम :— इसमें शामिल है :—

(क) पर्वतारोहण के उच्च तकनीकों में प्रशिक्षण ।

(ख) संभाव्य नेताओं और वृहत अभियानों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण ।

(ग) वृहत् अभियानों के लिए प्रायोजन ।

(घ) 2,0000 फुट से अधिक ऊंची चोटियां चढ़ना ।

(ग) बेसिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पर्वतारोहण तकनीक की पहले से जानकारी आवश्यक नहीं । 18–40 आयुवर्ग के छात्र और जो संस्था द्वारा नियत आवश्यक चिकित्सा योग्यता रखते हों, बेसिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के अर्ह हैं। जो छात्र बेसिक पाठ्यक्रम में पास हो जाते हैं और "क" और "ख" वर्गीकृत किये जाते हैं, साधारणतया एडवांस पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए अर्ह समझे जाते हैं ।

(2) एडवेंचर पाठ्यक्रम

संस्था 15 से 19½ वर्ष की आयु वाले लड़कों के लिए प्रति वर्ष दो एडवेंचर पाठ्यक्रम चलाती है। उन्हें कठिनाइयों पूर्ण भू-भाग में चट्टानों पर चढ़ना, शिविर लगाना, नक्शा पढ़ना, कम्पस कार्य, प्राथमिक उपचार, उद्धार क्रिया इत्यादि सिखाई जाती है ।

आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समेन और ट्रेसर

639. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) ड्राफ्ट्समैन और ट्रैसर के मंजूर पदों पर नियुक्ति न की जाने के कारण वे पद कितनी बार व्यपगत हुए ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी में ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर

640. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने प्रतिशत ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर स्थायी किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति बिना पारी स्थायी बनाये गये ;

(ग) क्या हाल में उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आकाशवाणी में 33. 3 प्रतिशत ड्राफ्ट्समैन और 33. 3 प्रतिशत ट्रेसर स्थायी किये गये हैं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) और (घ) संभरण इंजीनियर के अधीनस्थ कार्यालय में एक ट्रेसर को स्थायी करने के विरुद्ध आकाशवाणी महानिदेशालय (योजना और विकास यूनिट) के ट्रेसरों से कुछ अभ्यावेदन मिले थे, परन्तु वे ठीक नहीं पाये गये, क्योंकि मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नियुक्तियां अलग अलग की जाती हैं और कर्मचारियों को स्थायी भी अलग अलग रूप से किया जाता है ।

आकाशवाणी में इंजीनियर

641. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी तीन के इंजीनियरी कर्मचारियों में से कितने अनुभवी व्यक्तियों ने आकाशवाणी की सेवा छोड़ दी है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या श्रेणी 3 के इंजीनियरी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी ;

(ङ) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी ;

(च) क्या प्रतिवेदन देने में विलम्ब होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) श्रेणी 3 के इंजीनियरी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी ।

(घ) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Second Five Year Plan of Bhutan

642. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of Bhutan have sent their draft Second Five Year Plan to Government for advice; and

(b) if so; the extent of aid proposed to be given by Government for Bhutan's Second Five Year Plan?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The draft was received only recently and is being studied. The extent of aid has not yet been decided.

Assistance to Afghanistan

643. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3556 on the 29th August, 1966 and state:

(a) whether Afghan Government's request to Government to render assistance for some of their schemes has been finally considered;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the amount of assistance proposed to be provided?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Decisions on some proposals have been taken and others are under examination.

(b) It has been decided that a 100-Bed Children's hospital will be constructed in Kabul and India will help run the hospital for an initial period of 2 years. Afghan Doctors, Nurses and Dieticians will be given training in India so that they may eventually take over from Indian personnel. In the meantime suitable Indian personnel will be deputed.

It has also been agreed to supply specified agricultural equipment and implements to Afghan State Farms.

A team of industrial economists and engineers to undertake a study of an Industrialisation programme of the Herat Province will be sent.

A Chemist is being deputed for a Laboratory in Kabul for the testing and analysis of Asafoetida.

300 chairs are being provided for the rehabilitation of a Cinema of the Afghan Women's Society.

Sports goods are being gifted for distribution amongst schools in Afghanistan.

Other proposals are under consideration.

(c) It is not possible to give at this stage an estimate of the total amount of assistance proposed to be provided.

Effect of Devaluation on Defence Plan

644. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the amount out of the funds earmarked for the current year in the Five Year Plan for Defence Production which is likely to be utilised according to the latest estimates; and

(b) the extent of likely increase in the plan expenditure for this year as a result of devaluation?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) It is expected that the budgeted allocation of Rs. 145 crores in the current year for Defence Production will be spent in full.

(b) About ten per cent.

भारतीय पत्रकारों द्वारा दक्षिण वियतनाम में हुए चुनावों के समाचार भेजा जाना

645. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले सितम्बर में अनेक पत्रकारों तथा समाचार सम्वाददाताओं को दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय संविधान सभा के लिये 11 सितम्बर, 1966 को हुए चुनावों के बारे में समाचार भेजने के लिए विशेष रूप से विमान द्वारा भारत से सैगोन ले जाया गया था ;

(ख) इस यात्रा की व्यवस्था किसने की थी ; और

(ग) ये पत्रकार किन-किन भारतीय समाचारपत्रों अथवा समाचार एजेन्सियों के प्रतिनिधि थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) हमारी सूचना के अनुसार मद्रास से प्रकाशित "हिन्दू" के प्रतिनिधि, श्री ई० के० राम स्वामी ही एकमात्र ऐसे पत्रकार थे जो इस चुनाव के लिए सैगोन गये थे। वह वियतनाम गणराज्य के निमंत्रण पर गए थे और उसी ने उनकी यात्रा का और रहने का सारा खर्च उठाया था।

(ग) मद्रास के "हिन्दू" को छोड़ कर सरकार को किसी अन्य समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी के विषय में नहीं मालूम जिसने इस उद्देश्य के लिए सैगोन में अपना प्रतिनिधि भेजा हो।

भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों की बैठक

646. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प० ना० तिवारी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री वारियर :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री बसुमतारी :
श्री सुरेन्द्रनापाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किरोडिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लोनाधर फारूकी :
श्री दाजी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कोलला वैंकैया :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री दे० जी० नायक :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और भारत की सेनाओं पर तनाव कम करने के लिए 13-14 सितम्बर, 1966 को पाकिस्तान के मुख्य सेनापति के भारत के दौरे के दौरान उनके तथा भारत के सेनाध्यक्ष के बीच हुए करार की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या दोनों देशों के सेनाध्यक्षों के बीच "सीधी लाइन" के माध्यम से सीधे टेलीफून सम्पर्क स्थापित करने का निर्णय इस समझौते में शामिल है ; और

(ग) क्या काश्मीर में 1949 की युद्ध-विराम रेखा के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा भी इस समझौते में शामिल है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 13–14 सितम्बर, 1966 को हुई मुख्य सेनापति, पाकिस्तान और सेनाध्यक्ष, भारत के बीच नई दिल्ली में वार्तालाप के ब्यौरे की एक प्रति संलग्न है ।

(ख) देखा जाएगा कि करार में मुख्य सेनापति, पाकिस्तानी सेना और सेनाध्यक्ष, भारत के बीच टेलीफून-रेडियाई संचार की उपलब्धी है ।

(ग) इस प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है। तदपि, जो भी करार तय पाया है वह सभा के पटल पर रखे गये ब्यौरे में दर्शाया गया है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 7233/66]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में तालाबन्दी

647. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमना सुरतान :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक लिमिटेड कानपुर के प्रबन्धकों ने 10 सितम्बर, 1966 को तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी ;

(ख) क्या विमानों के वास्तविक उत्पादन में लगे हुए कर्मचारी 6 सितम्बर, 1966 से गैर-कानूनी हड़ताल पर थे ;

(ग) हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक लिमिटेड कर्मचारी संघ की मांगें क्या हैं ; और

(घ) झगड़े को निपटाने और विमानों का उत्पादन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कहां तक प्रयास किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) एच० ए० एल० कर्मचारी संघ की मुख्य मांगें एच० ए० एल० कानपुर के कृत्य की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना; अब तक के विमान निर्माण डिपु के वैमानिकों और असैनिकों की कम्पनी कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति की शर्तें; वेतन-मानों के संशोधन; केंद्रीय सरकार की दरों पर मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्तों की अदायगी ; बोनस की अदायगी; डिपुटेशन भत्ते की अदायगी; निर्धारित समय के बाद काम करने के लिए भत्ते; उपयुक्त परिवहन और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी थीं।

(घ) मांगों पर समय समय पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है। तालाबन्दी 10 अक्तूबर, 1966 को खुली थी और फैक्टरी ने फिर से काम करना आरम्भ कर दिया है।

कार्मिकों में से एक बड़ी संख्या ने कम्पनी कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति की स्वीकृति भी अब तक सूचित कर दी है।

A.I.R. Delhi

649. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of areas which have been taken away from their respective stations and brought under the jurisdiction of Delhi Station of the All-India Radio; and

(b) the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No area has been taken away from the jurisdiction of any station and brought under the jurisdiction of Delhi Station of the All India Radio in the last few years.

(b) Does not arise.

परमाणु करार

650. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा भारत के साथ अपने परमाणु करार को अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने के लिये राजी हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा इस देश की रजामंदी तथा सहमति से किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली

651. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दिल्ली में वर्तमान टेलीविजन केन्द्र का एक उपनगरीय स्टेशन स्थापित करने का काम आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये टेलीविजन केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-श्रीलंका करार

652. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में श्रीलंका सरकार ने एक नई जनगणना कराई जिससे मालूम हुआ कि केवल 8,20,000 भारत मूलक व्यक्ति नागरिकता विहीन हैं जब कि 1964 में हस्ताक्षर किये गये भारत-श्रीलंका करार में यह संख्या 9,75,000 बताई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनसंख्या के आंकड़ों में इस अन्तर के कारण 1964 के करार में किसी परिवर्तन के किये जाने की आवश्यकता होगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). आंकड़ों में कोई फ़र्क़ नहीं है क्योंकि 8,20,000 के आंकड़ों का संबंध केवल उन भारत मूलक लोगों से है जो एस्टेट क्षेत्रों में रहते हैं और इनमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो नगरों में रहते हैं । इसलिये 1964 के करार में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन स्थल

653. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व भारत ने अफ्रीकी-एशियाई एकता संघ के स्थायी सचिवालय का औपचारिक रूप में लिख कर यह मांग की थी कि पांचवें अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के स्थान को पेकिंग से बदलने के बारे में चर्चा की जाये ;

(ख) यदि हा, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक -कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। लेकिन यह पता चला है कि अफ्रो-एशियाई एकता संगठन की भारतीय संस्था ने जो एक गैर-सरकारी संगठन है, उक्त एकता संगठन के कुछ सदस्यों की इस मांग का औपचारिक रूप से समर्थन किया है कि अगले सम्मेलन का स्थान पीकिंग से बदल दिया जाए।

(ख) यह और पता चला है कि स्थान बदलने के प्रश्न पर अफ्रो-एशियाई एकता संगठन की परिषद् की मीटिंग में निर्णय किया गायेगा जो जल्दी ही होने वाली है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को शामिल किया जाना

654. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई देशों ने जिनमें कुछ तटस्थ देश भी शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से चीन को इस विश्व संघ में शामिल करने के लिये अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी उनकी इस अपील में शामिल है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) अलबानिया, अल्जीरिया, कम्बोडिया, कांगो (ब्रजविल), क्यूबा, गिनी, माली, रूमानिया और सीरिया की सरकारों के अनुरोध पर महासभा के 21वें अधिवेशन की कार्यसूची में चीन लोक गणराज्य के प्रतिनिधित्व का मद शामिल कर लिया गया है। यह मद महासभा के समक्ष बहस के लिये अभी नहीं आया है।

ताशकन्द समझौते का पालन

655. श्री वासुदेवन नायर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हु० चा० लिग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री किरोडिया :
श्री बासप्पा :
श्री र.० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री फ० ना० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरी विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री लोलाधर कटकी :
श्री नी० रं० लास्कर :
श्री अल्वारेस :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री ब्रजवासी :
श्रीमती जमूना सुल्तान :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताशकन्द समझौते की शर्तों के अनुसार वार्ता का अगला दौर चलाने के प्रश्न पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच हाल में हुए पत्र-व्यवहार का क्या कोई परिणाम निकला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है; और

(ग) अगली बैठक कहां और किस तारीख को होगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत एक और मीटिंग आयोजित करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसमें भारत सरकार ने ताशकन्द घोषणा पर पूरी तरह अमल करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और उन्हें सामान्य बनाने की दृष्टि से कोई पूर्व-शर्त लगाए बगैर भारत और पाकिस्तान के बीच सभी चले आ रहे मतभेदों पर बातचीत करने की इच्छा कई बार स्पष्ट कर दी है। ताशकन्द घोषणा पर ईमानदारी से अमल करने की इच्छा से, भारत सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, जैसे व्यापार पर इकतरफा तरीके से प्रतिबंध हटाना, रोके हुए सामान को छोड़ना और भारत तथा पाकिस्तान में व्यापार तथा आवाजाई को सुविधाजनक बनाने के लिये दोनों देशों के बीच तमाम भूमि यातायात जांच चौकियों को खोल देने की पेशकश करना।

पाकिस्तान सरकार ने ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत एक और मीटिंग आयोजित करने के हमारे प्रस्तावों का तथा संबंधों को सामान्य बनाने के बारे में हमने जो ठोस पेशकश की थी, उसका निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाये, पाकिस्तान सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत सरकार को चाहिये कि वह ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत एक और मीटिंग करने के पहले काश्मीर प्रश्न के बारे में पूर्व-आश्वासन दे। इस रवैये का मतलब मीटिंग के लिये पूर्व-शर्त लगाना है जो ताशकंद घोषणा के अनुरूप नहीं है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ताशकंद घोषणा पर दोनों पक्षों द्वारा और आगे अमल तभी अच्छी तरह हो सकता है जबकि वे इस इच्छा से कोई पूर्व शर्त लगाए बगैर मीटिंग करें जिससे कि सहमति का क्षेत्र विस्तृत हो सके और यथासंभव अधिकाधिक क्षेत्रों में अधिक प्रगति की जा सके और किसी खास प्रश्न पर प्रगति अन्य प्रश्नों पर प्रगति करने में बाधा का कारण न बने। पाकिस्तान द्वारा इस तरह की बात का विरोध करने से दोनों सरकारों के बीच सफलतापूर्वक पत्र-व्यवहार होने में रुकावट पड़ी है और इसलिये पाकिस्तान के साथ फिलहाल कोई मीटिंग आयोजित करना संभव नहीं हुआ है।

पाकिस्तान के लिये ईरानी जेट विमान

656. श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
डा० लक्ष्मी मल सिंघवी :
श्री फिरोडिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरी विष्णु कामत :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व ईरान की सरकार ने भारत को पक्का आश्वासन दिया था कि उसने जो नब्बे के करीब एफ 86 सेवर जेट विमान सफाई तथा मरम्मत आदि के लिये पहले पाकिस्तान में भेजे थे, वह उन्हें शीघ्र ही ईरान वापस मंगवा लेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ईरान ने पाकिस्तान से इन लड़ाकू विमानों को वापस मंगाने के संबंध में कोई निश्चित समय निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ईरान उस निर्धारित समय पर दृढ़ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : ईरान की सरकार ने बार-बार यह कहा था कि विमान पाकिस्तान केवल सफाई, मरम्मत तथा रूपभेद के लिये भेजे गये थे और वे ईरान वापस आ जायेंगे। पश्चिम जर्मनी के अधिकारियों ने जिन्होंने विमान ईरान को उसके अपने प्रयोग के लिये बेचे थे, हाल ही में बताया था कि कुछ विमानों के अलावा, जिन की अभी मरम्मत हो रही है, सभी एफ 86 विमान ईरान वापस आ गये हैं। हमें यह भी बताया गया है कि वे विमान, जिनकी मरम्मत हो रही है, भी ईरान वापस आ जायेंगे।

एवरो–748 कारखाना, कानपुर

657. श्री दाजी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरी विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री कृ० चं० पंत :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कानपुर स्थित एवरो-748 कारखाने की पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के मार्गोपाय ढूंढने में सफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की उत्पादन दर क्या है और इन विमानों के भावी खरीदार कौन हैं, और

(ग) उनकी मागों क्या हैं और वे किस हद तक पूरी की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) 1959 में जब कानपुर में एच० एस० 748 के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित किया गया था ऐसा लगता था कि 150 विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस समय केवल 27 विमानों के लिये आई० ए० एफ० से आर्डर है और 15 के लिये आई० ए० सी० से। इस छोटे से आर्डर के कारण उत्पादन के पहले प्रायोजित रेट तक के लिये विकास संभव नहीं हो पाया। कानपुर में प्राप्य संयंत्र 9 विमान प्रतिवर्ष के वार्षिक उत्पादन के पर्याप्त निर्धारित किया गया है। कानपुर में सेविवर्ग की वर्तमान एस्टेबलिशमेंट प्रतिवर्ष 5 विमानों के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। एच० एस० 748 विमानों का मुख्य प्रत्याशित क्रेता आई० ए० सी० है। स्थापित क्षमता तक विकास तब तक संभव नहीं जब तक एच० एस० 748 के लिए पर्याप्त आर्डर प्राप्त न हों। यात्रियों के यातायत में वृद्धि और विदेश. भ्रमिकों से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं के फलस्वरूप, आई० ए० सी० को शायद एच० एस० 748 की अधिक आवश्यकताएं पड़ें। तदपि, आवश्यकताओं के पक्के अनुमान और आर्डर आने में कुछ समय लगेगा।

(ग) अब तक भारतीय वायु सेना को 6 विमान दिये गये हैं। कानपुर के कारखाने में निर्मित एक विमान को, आई० ए० सी० द्वारा वांछित, परिवर्तन करने के लिये यु० के० भेजा गया है। आशा है यह विमान दिसम्बर 1966 तक आई० ए० सी० को देने के लिये तैयार हो जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिये भारत का उम्मीदवार होना

658. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कोल्ला बेंकया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के स्थान प्राप्त करने की संभावना का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार चुनादों के परिणामों के बारे में आशावान है लेकिन विभिन्न सरकारों द्वारा दिये गये समर्थन के आश्वासन गोपनीय हैं और बताए नहीं जा सकते। चुनाव जल्दी ही होने वाला है।

('स्टेट आफ अवर इकानोमी') कार्यक्रम

659. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए विषयों पर "स्टेट आफ अवर इकानोमी" हमारी अर्थव्यवस्था की दशा शीर्षक के अन्तर्गत आकाशवाणी से कुछ समय पहले चालू किये गये प्रसारण सफल सिद्ध हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो साधारण जनता पर उनका क्या असर पड़ा है; और

(ग) वक्ताओं के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) "स्टेट आफ अवर इकानोमी" अर्थात हमारी अर्थ-व्यवस्था की दशा पर आकाशवाणी के प्रसारण लगभग सितम्बर 1966 के मध्य में शुरू किये गये थे और ये लगभग नवम्बर, 1966 के मध्य तक चलेंगे। इनका श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह जानने के लिए इन में से कुछ प्रसारणों का पहले से ही सर्वेक्षण किया जा रहा है। इनके प्रभाव का सारे प्रसारणों के समाप्त होने और सर्वेक्षण के परिणाम संकलित होने के बाद ही पता लगेगा।

(ग) वार्ताकारों को चुनने में जिन मुख्य बातों का ख्याल रखा जाता है वे हैं : व्यक्ति विशेष का उसके कार्य-क्षेत्र में स्थान, प्रसारण किए जाने वाले विषय का स्वरूप और प्रसारण करने में जिन बातों की विशेष जरूरत होती है, उनकी दृष्टि से इन व्यक्तियों की योग्यता।

पाकिस्तान द्वारा स्वीडन से हथियारों की खरीद

660. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने स्वीडन में एक प्रसिद्ध शस्त्र कारखाने को अस्त्र-शस्त्र खरीदने के लिए एक आदेश दिया है जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् इस आदेश द्वारा सब से अधिक हथियार मंगाये जा रहे हैं जिनमें टैंक-भेदी राकेट, स्वचालित हथियार तथा बोफरों सहित तोपखाने के उपकरण शामिल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है।

चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

661. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में चीनी विमानों ने कितनी बार हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया ;

(ख) इन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थानवा) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं हुआ ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीयता विहीन व्यक्तियों के बारे में भारत-श्रीलंका करार

662. श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयता विहीन व्यक्तियों के बारे में भारत-श्रीलंका करार के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत कोलम्बो में जो सम्मिलित समिति स्थापित की गई थी, उसकी बैठकें नियमित रूप से होती रही हैं ; इनका उद्देश्य करार पर अमल करने के विभिन्न उपायों पर विचार करना और उन्हें तय करना था । पता चला है कि श्रीलंका की सरकार राज्यविहीन व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता देने के लिए श्रीलंका की संसद में जल्दी ही कानून पेश करने वाली है । उसके बाद, भारत-श्रीलंका की नागरिकता की अर्जियां मंगाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे ।

हार्नेस एण्ड सडलरी फैक्टरी, कानपुर

663. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में क्रोम तथा वनस्पति से चमड़ा कमाने का संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हार्नेस तथा सैडलरी फैक्टरी कानपुर में वेजीटेबल टेनिंग के लिए एक पुराना संयन्त्र पहले से काम कर रहा है। फैक्टरी के पास एक कामचलाऊ क्रोम टेनिंग संयंत्र भी है। निकास में सुधार के लिए तथा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इन दोनों संयंत्रों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नये आयुध कारखाने

664. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री दाजी : **श्री मधु लिमये :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नये आयुध कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो जिन कारखानों में अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में कोई नये आयुध कारखाने स्थापित किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) नये आयुध कारखानों में बरंगांव और तिरुचिरापल्ली कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

(ख) चार नये आयुध कारखानों में से दो ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया।

(ग) उत्तर प्रदेश में जो नई फैक्टरी स्थापित की जा रही है, वह है एकसेलरोटिड फ्रीज़ ड्राईड मीट फैक्टरी। यह उन फैक्टरियों में से एक नहीं होगी जिनका नियन्त्रण आयुध कारखानों के महा निदेशक के अधीन है।

प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड

665. श्री स० मो बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्रति-रक्षा उत्पादन बोर्ड बनाने के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि बहुत अधिक केन्द्रीयकरण के परिणाम स्वरूप आयुध कारखानों में अकुशलता आ गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : रक्षा उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के निरीक्षण के लिए मई 1964 में एक रक्षा उत्पादन बोर्ड स्थापित किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

चीन द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण

666. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो प्रस्तावों के पश्चात भी चीनियों ने कई बार भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया है ;

(ख) यदि हां, तो कोलम्बो प्रस्तावों से पहले कुल कितनी भूमि पर चीनियों का कब्जा था और क्या कोलम्बो प्रस्तावों के पश्चात उन्होंने और अधिक भूमि अपने कब्जे में कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । कोलम्बो प्रस्तावों के तैयार हो जाने के बाद भी, जिसे वे "सिद्धान्त रूप से" मानना स्वीकार करते हैं, चीन सरकार ने हिन्द-चीन सीमा और तथाकथित "वास्तविक नियंत्रण रेखा" का बार-बार उल्लंघन किया है । उन्होंने जान-बूझकर उत्तेजनात्मक कार्रवाइयां भी की हैं और सिक्किम तथा भूटान में घुसपैठ की है । इन उल्लंघनों का ब्यौरा उन नोटों की प्रतियों में दिया जा चुका है जिनकी अदला-बदली भारत और चीन के बीच हुई है और जो समय-समय पर सदन की मेज़ पर रखे जा चुके हैं ।

(ख) और (ग). अक्तूबर-नवम्बर 1962 में चीन के भारत आक्रमण से पहले चीनी सैनिकों ने लद्दाख में लगभग 12,000 वर्गमील के भारतीय प्रदेश पर कब्जा कर लिया था । 1962 के चीनी हमले के बाद, चीनी सैनिकों ने लगभग 2,500 वर्ग मील पर और अधिकार कर लिया । आज

लद्दाख में भारत की लगभग 14,500 वर्गमील भूमि पर चीनी सैनिकों ने गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है जब कि नवम्बर 1962 से लद्दाख ने चीनी अधिकार के अन्तर्गत कुल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 1963 में चीन सकार ने गैर कानूनी तरीके से और तथाकथित चीन-पाक सीमा करार के परिणामस्वरूप 2,000 वर्गमील से कुछ अधिक पाक-अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र ले लिया जिसे पाकिस्तान ने दिया ।

वियतनाम की समस्या

667. श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हांसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री नाथ पाई :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा कोई और कदम उठाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नये प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) उसके सम्बन्ध में अमरीका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). भारत सरकार उन सिद्धान्तों को बराबर दोहराती रही है जो उनके ख्याल में वियतनाम समस्या के हल का आधार बन सकते हैं। बहरहाल, उन्होंने कोई नए प्रस्ताव नहीं रखे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभावशाली प्रसारण पद्धति

668. श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण के बाद जनता प्रभावशाली प्रसारण प्रणाली की वास्तविक आवश्यकता को कहां तक महसूस करने लगी है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रसारण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के महत्व की सराहना की है ;

(ग) वर्तमान व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या चौथी योजना में निर्धारित की गई राशि प्रसारण को प्रभावशाली बनाने के लिये पर्याप्त है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क). चीनी और पाकिस्तानी हमले के बाद हमारे देश के लोग प्रसारण प्रणाली को सूचना के शक्तिशाली माध्यम के रूप में समझने लगे हैं। पाकिस्तान के साथ लड़ाई बन्द होने के तुरन्त बाद किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि सूचना के माध्यम के रूप में आकाशवाणी का नम्बर सर्वोपरि था।

(ख). जी, नहीं।

(ग). शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाकर वर्तमान प्रसारण व्यवस्था को मजबूत करना और नए ट्रांसमीटर लगा कर, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

(घ). प्रसारण-व्यवस्था के विकास के लिए जितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है वह प्राथमिकताओं और किफायत की आवश्यकता और योजना-बद्ध कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिए उसके वास्तविक उपयोग की क्षमता के अनुरूप है।

भारत-मलयेशिया और मलयेशिया-पाकिस्तान सम्बन्ध

669. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि गत वर्ष भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर सुरक्षा परिषद में हुई बातचीत के दौरान मलयेशिया के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणी के लिये मलयेशिया ने क्षमा याचना की है।

(ख) क्या सरकार ने मलयेशिया से यह जानकारी मांगी है कि क्या पाकिस्तान के इस वक्तव्य में कोई सचाई है :

(ग) यदि हां, तो मलयेशिया के साथ पुनः राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये पाकिस्तान ने मलयेशिया पर यदि कोई शर्त लगाई है तो वह क्या है ; और

(घ) क्या पाकिस्तान के साथ मलयेशिया के नये संबंधों के बाद भारत-मलयेशिया संबंधों में कोई परिवर्तन हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत-मलयेशिया के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे हमशा की तरह अत्यन्त मैत्रीपूर्ण है।

ग्रामीण प्रसारण परियोजना

670. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 लाख निरक्षर किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि तथा खाद्य संगठन—तथा यूनेस्को के विशेषज्ञों के संयुक्त दल ने एक ग्राम्य प्रसारण परियोजना तैयार की है और योजना आयोग की सलाह पर मंत्रालय इस पर पुनरीक्षण कर रहा है ;

(ख) क्या रेडियो फार्म फोरम संगठित करने की व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ग) इस पर कितना खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां।

(ख) : रेडियो ग्राम गोष्ठियां पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं, इनकी वर्तमान संख्या 13,269 हैं। प्रश्न के (क) भाग में बताई गई संयक्त प्रायोजना के संबंध में प्रायोजना के सारे क्षेत्र में छोटी छोटी किसान गोष्ठियां आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) अभी यह बताना सम्भव नहीं कि इस पर कितना खर्च आयेगा क्योंकि अभी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अन्दमान द्वीप समूह के निकट विदेशी पन्डुब्बियां

671. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सेझियान :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री फिरोडिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद।
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कपूर सिंह :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री महेश्वर नायक :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री बागड़ी :
श्री नाथ प.ई :
श्री हेम बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 में अन्दमान द्वीप के समीप कुछ पनडुब्बियां देखी गई थीं ;

(ख) क्या यह पता लगा लिया गया है कि ये पोत किस देश के थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये पोत पाकिस्तान द्वारा बंगाल की खाड़ी में प्रयोग करने के लिये चीन से प्राप्त किये गये थे ;

(घ) क्या यह प्रश्न भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच हाल ही में हुई बैठक में उठाया गया था ; और

(ङ) : सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) अन्दमान के आसपास सितम्बर, 1966 में किसी पनडुब्बी के देखे जाने के सबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) शत्रुदेशों की पनडुब्बियों से संकट के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क है, और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों की सुरक्षा को सशक्त बनाने के उपाय कर रही है।

प्रत्यर्पण करार

672. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन देशों के साथ प्रत्यर्पण करार नहीं किये गये हैं ;

(ख) उन देशों के साथ इस प्रकार के करार करने की दिशा में क्या प्रयत्न किये गये :

(ग) ऐसे देशों में भारत से बच कर भागे अपराधियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ; और

(घ) : इस समय इन देशों में भाग कर गये भगोड़े अपराधियों की संख्या कितनी है; जिन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) स्वतन्त्रता से लेकर अब तक भारत ने केवल निम्नलिखित देशों के साथ ही प्रत्यर्पण संधियां की हैं ;

1. भूतान
2. सिक्किम
3. नेपाल

इसके अलावा, स्वतन्त्रता से पूर्व निम्नलिखित देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं :

अल्बानिया	कोलम्बिया	फिनलैण्ड
अर्जन्तीना	क्यूबा	जर्मनी
आस्ट्रिया	चेकोस्लोवाकिया	यूनान
बेल्जियम	डेन्मार्क	ग्वातेमाला
बोलिविया	इक्वादोर	हैती
चिली	एस्टोनिया	हंगरी
आइसलैण्ड	लक्समबर्ग	पुनासा
ईराक	मैक्सिको	पैराग्वे
इटली	मोनाको	पेरू
लैटबिया	नीदरलैंडस	पोलैण्ड
लाइबेरिया	निकारागुआ	पुर्तगाल
लिथुआनिया	नार्वे	सल्वाडोर
स्पेन	स्वीडन	स्विटज़रलैण्ड
स्वन गरीनें	संयुक्त राज्य अमरीका	यूगोस्लाविया
थाई देश	उरुग्वे	

विश्व के बाकी देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधियां नहीं हैं ।

(ख) जब कभी किसी खास देश के साथ प्रत्यर्पण संधि करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब इस प्रकार की संधि करने की कोशिश की जाती है । किसी अन्य देश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत शुरू करने में, पारस्परिकता के आधार पर भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए इस प्रकार की संधि के उपयोग की संभावना, इस प्रकार की संधि के कितनी बार उपयोग करने की संभावना आदि पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है ।

(ग) अगर कोई फरार अपराधी भारत से भाग कर एक ऐसे देश में चला जाता है, जिसके साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और यह वांछनीय समझा जाता है कि फरार अपराधी को पकड़ कर वापस भारत लाया जाए ताकि उस पर मुकदमा किया जा सके और उसे सजा दी जा सके तो भारत सरकार सामान्य तौर पर संबद्ध देश की सरकार को प्रत्यर्पण के अनुरोध पर विचार करने की अपनी इच्छा के बारे में अवगत करा देती है । अगर अन्य देश की सरकार का उत्तर अनुकूल हो तो उस देश की सरकार से यह यह अनुरोध किया जाता है कि वह हमारे फरार अपराधी को प्रत्यर्पण संबंधी अपने म्यूनिसिपिल कानून के अनुसार पकड़ कर हमारे पास भेज दे । अगर वह विदेश की सरकार पारस्परिकता का आश्वासन मांगती है, तो ऐसा आश्वासन उस देश पर अपना प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 लागू करते हुए सरकारी गजट में समुचित अधिसूचना जारी करके दिया जा सकता है ।

(घ) पूरी तरह पूछताछ किए बगैर यह कहना संभव नहीं है कि ऐसे देशों में भागे हुए फरार अपराधियों की संख्या कितनी है, जिनके साथ फिलहाल भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है ।

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता

673. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को फिर से अमरीकी सहायता दिये जाने के बारे में नवीनतम संकेत क्या हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . जहां तक भारत सरकार को मालूम है अमरीकी सरकार का अब भी यही निर्णय है कि वह भारत की तरह पाकिस्तान को भी ऐसे ही हथियार बेचने की इजाजत देगी जो घातक न हों।

भारत सरकार विश्वास करती है कि भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए अमरीका की इस नीति का पालन किया जाएगा।

अखबारी कागज की स्थिति

674. श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज परामर्श समिति की देश में अखबारी कागज की स्थिति के पुनर्विलोकन के बारे में हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई ;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) इस वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) : जी, हां।

(ख) तथा (ग) . 1966-67 में 1,16,374 मीटर टन अखबारी कागज आयात किया जाएगा। इसमें आम चुनाव के लिए विशेष रूप से नियत 5000 मीटर टन अखबारी कागज तथा 1965-66 के आयात के निर्धारित लक्ष्य से जो 7000 मीटर टन अखबारी कागज आयात न हो सका था वह भी शामिल है। इसके अतिरिक्त आशा है कि नेपा अखबारी कागज का 26,000 मीटर टन और सफेद छपाई कागज का 20,000 टन कागज समाचार पत्रों को वितरण करने के लिए मिल सकेगा।

यू० एस० एंड नान प्राजेक्ट लोन के अन्तर्गत अमरीका से 20,921 मीटर टन अखबारी कागज को आयात करने की व्यवस्था है। राज्य व्यापार निगम ने अभी तक 5,268 मीटर टन के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। निगम ने शेष 15,653 मीटर टन कागज के लिए फिर से टेन्डर जारी किये हैं।

अवमूल्यन के बाद यू० एस० एंड नान-प्राजेक्ट लोन के अन्तर्गत अखबारी कागज के आयात के लिए 20 लाख अमेरीकन डालर और नियत किए गए। क्योंकि पहिले अमेरीका से प्रतियोगी प्रस्ताव नहीं आ रहे थे इस कारण यह निर्णय किया गया कि अखबारी कागज की अतिरिक्त मात्रा केनेडियन डेवलेपमेन्ट लोन असिस्टेन्स के अन्तर्गत कनाडा से मंगाया जाए। राज्य व्यापार निगम ने पहिले ही इस सम्बन्ध में टेन्डर जारी कर दिये हैं। जो अखबारी कागज अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाना है, उसको प्राप्त करने के लिए भी कार्रवाई कर ली गई है।

1967 के व्यापार योजना की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रूस से 10,000 मीटरी टन, पौलैण्ड से 2000 मीटरी टन तथा चेकोस्लोवेकया से 2000 मीटरी टन अखबारी कागज आयात करने के लिए कदम उठा लिये गये हैं।

जो संकेत मिले हैं, उनको देखते हुए 1966-67 में अखबारी कागज की सप्लाई सन्तोषजनक रहेगी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा का अधिवेशन

675. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में चीन को राष्ट्र संघ में शामिल करने के बारे में प्रश्न उठाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय शिष्टमंडल ने इस विषय पर क्या रवैया अपनाया ; और

(ग) इस अधिवेशन में और किन किन विषयों पर चर्चा हुई और प्रत्येक विषय पर क्या निर्णय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र में चीन लोक गणराज्य के प्रतिनिधित्व का प्रश्न महासभा के 21वें अधिवेशन की कार्यसूची में शामिल किया गया है किंतु यह अभी तक विचार के लिए सामने नहीं आया है।

(ख) इस प्रश्न पर भारत सरकार के रवैये में कोई अंतर नहीं आया है।

(ग) इस समय यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि महासभा का अधिवेशन अभी चल रहा है और शायद दिसम्बर 1966 के अन्त तक चलता रहे।

नेहरू-लियाकत समझौता, 1950

676. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए नेहरू-लियाकत समझौते की स्थिति पिछले भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात क्या रही है और क्या दोनों देश इसकी शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यह समझौता होने के बाद से पाकिस्तान द्वारा अब तक इसका उल्लंघन किये जाने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी करार है। इसमें प्रत्येक देश से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अल्प-संख्यक लोगों को अन्य लोगों के साथ पूर्ण रूप से नागरिक समानता मिले और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा कि उस देश के अन्य राष्ट्रिकों के साथ किया जाता है।

हालांकि भारत में अल्पसंख्यकों की हिफाजत की गई है और उनके अधिकारों को निरंतर और प्रभावकारी ढंग से सुरक्षित रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की निरंतर अवहेलना और उन्हें परेशान करके समझौते की व्यवस्थाओं का बराबर उल्लंघन किया है।

(ख) नेहरू-लियाकत समझौते के शुरू होने से लेकर ही पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया है और हमारे ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जिनसे यह पता चलता है कि पाकिस्तान में चाहे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के बारे में हो या रोजगार के अवसर पाने के बारे में हो, अवसर की समानता उपलब्ध नहीं है और न मुनासिब तौर पर वहां जान माल की सुरक्षा ही है। अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों के साथ आम-तौर से बुरा बर्ताव किया जाता है।

आकाशवाणी के लिए निगम

677. **श्रीमती विमला देवी** :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 25 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के लिए स्वायत्तशासी निगम बनाने के बारे में चन्दा समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मिग कारखाने

678. श्रीमती विमला देवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मिग कारखाने स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखानों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मिग कारखाने के भवनों के निर्माण में प्रगति सन्तोषजनक है ; नासिक में पहली प्रावस्था के लिए आवश्यक भवन तैयार है।

संयत्र तथा मशीनों और साजसमान की उपलब्धि, सेविवर्ग की भर्त्ती और प्रशिक्षण तथा दस्तावेजों के अनुवाद का काम भी योजना के अनुसार प्रगति कर रहा है।

(ख) मिग-21 विमानों का संयोजन आरम्भ हो चुका है।

पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

679. श्रीमती विमला देवी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की कार्यकुशलता तथा कार्य साधकता में सुधार करने के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित पिल्ले समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रिपोर्ट छप रही है और जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी। विभिन्न सिफारिशों क. छानबीन करने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है।

विज्ञापनों पर कमीशन

680. श्री चं० व० विष्ट : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन समाचारपत्रों पर जो भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र संस्था के सदस्य नहीं है उनको दिये जाने वाले विज्ञापनों पर वर्तमान 15 प्रतिशत का कमीशन छोड़ने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक किया जायेगा ; और

(ग) समाचारपत्रों की दो श्रेणियों के बीच यदि कोई भेदभाव है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). यह फैसला किया गया है कि तत्काल से सभी समाचार-पत्रों से चाहे वे इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के सदस्य हैं या नहीं, उन को दिए जाने वाले वर्गीकृत विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत का कमीशन छोड़ दिया जाए।

(ग) सभी समाचार-पत्रों से, जिन में इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के सदस्य भी शामिल हैं, सजावटी और वर्गीकृत दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत का कमीशन देने के लिए कहा गया था। परन्तु जहां वे समाचार-पत्र, जो सोसायटी के सदस्य थे, वर्गीकृत विज्ञापनों पर कोई कमीशन देने के लिए रजामन्द नहीं हुए, वहां दूसरे समाचार-पत्र सजावटी और वर्गीकृत दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत का कमीशन देने के लिए रजामन्द थे।

आकाशवाणी को समाचारों का दिया जाना

681. **श्री ज० व० सिं० विष्ट :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार अभिकरणों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि चूंकि अवमूल्यन से उन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिये सरकार को उस अंशदान को बढ़ा देना चाहिए जो वह आकाशवाणी को समाचार भेजने के लिए इन अभिकरणों को दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय कर लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) आकाशवाणी को अपनी समाचार सेवायें देने वाले प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, ने यह प्रार्थना की है कि अंशदान की दरें बढ़ा दी जाएं ताकि अवमूल्यन के कारण बढ़े हुए खर्च की पूर्ति हो सके।

(ग) इन दो समाचार एजेन्सियों की प्रार्थना विचाराधीन है।

राजौरी (श्रीनगर) के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

682. **श्री विश्वनाथ पण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 3 सितम्बर, 1966 को राजोरी (श्रीनगर) के निकट एक विमान दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के तीन अफसर मारे गए ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या थे ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां, इसके अतिरिक्त एक अफसर और एक वैमानिक भी जो दोनों उस विमान में थे, घावों के कारण बाद में मर गए।

(ख) तथा (ग). दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है। दुर्घटना का कारण, कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पता चल पाएगा।

संयुक्त राष्ट्र वृहत्सभा के लिये भारतीय प्रतिनिधिमंडल

683. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प० ह० भील :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 सितम्बर, 1966 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र वृहतसभा की आरम्भ होने वाली कार्यवाही में एक भारतीय दल ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल में कितने सदस्य थे ; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय किया गया ;

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) जी हां।

(ख) भारतीय शिष्ट मंडल में 24 सदस्य हैं जिनमें से 10 न्यूयार्क-स्थित भारतीय स्थायी मिशन के सदस्य हैं।

(ग) दिसम्बर 1966 में अधिवेशन की समाप्ति पर ही कुल खर्च का पता चलेगा।

भारत-चीन सीमाओं पर चीनियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

684. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चीनियों द्वारा भारत-चीन सीमा पर भारत विरोधी प्रचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। चीनी सैनिक खासतौर से भारत की दशा के बारे में नितांत झूठी कहानियां कह कर भारतीय सैनिकों के मनोबल और अनुशासन को गिराने की कोशिश में सिक्कम तिब्बत सीमा की कुछ जगहों पर लाउड-स्पीकरों के ज़रिये भारत-विरोधी प्रचार करते रहे हैं। चीन सरकार ने भारतीय सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय पर इन प्रसारणों के प्रभाव का बिल्कुल गलत अनुमान लगाया क्योकि उन्होंने तो इस प्रकार के भोंडे प्रचार से सिर्फ मनो-विनोद ही किया।

(ख) चीन के झठे प्रचार का खंडन करने और भारत के प्रति उनके आक्रामक इरादों का भंडा-फोड़ करने के लिए उपयुक्त उपाय करते गए हैं। हमारे सैनिकों को जो सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं, उसमें

वे भारत में होनेवाली घटनाओं के निरतंर संपर्क में रहतें हैं—खासतौर से रेडियों सेटों और अक्सर होने वाले व्यक्तिगत पत्राचार आदि के जरियें घर के संपर्क में। अन्य उपायों में सीमा के पार लाउड-स्पीकरों द्वारा प्रतिकारी प्रसारण करना शामिल हैं।

भारत सेवक समाज को अनुदान

685. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कार्य क्षेत्र के माध्यम से योजना सम्बन्धी प्रचार-कार्य करने के लिए भारत सेवक समाज को दिया जाने वाला अनुदान मूल्यांकन समिति की सलाह के विपरीत धन की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत सेवक समाज के लोक कार्य क्षेत्रों को अनुदान, योजना आयोग द्वारा दिया जाता है। आयोग ने सूचित किया है कि यह अनुदान योजना प्रचार के लिए नहीं है और उसे बन्द करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है। सूचना और प्रसरण मंत्रालय, भारत सेवक समाज के जन जागरण विभाग को योजना सम्बन्धी प्रचार के लिए अनुदान देता है। यह अनुदान उनकी चार स्वीकृत योजनाओं अर्थात् (1) जन-सम्पर्क, (2) भारत सेवक पत्रिका, (3) पुस्तिकाओं और (4) बुलेटिनों के लिए दिया जाता है। भारत सेवक समाज के जन जागरण विभाग को दिया जाने वाला अनुदान बंद नहीं किया गया है। सार्वजनिक लेखा समिति के निदेश के अनुसार, समाज को अनुदान की अदायगी उसके द्वारा अपना समेकित हिसाब सरकार को पेश करने के बाद ही की जाएगी।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अमृतसर नाले में सैनिकों का डूब जना

686. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के तीन व्यक्ति सितम्बर, 1966 में किसी समय अमृतसर नाले में डूब गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) 13 सितम्बर, 1966 को चार सैनिकों की एक टुकड़ी हुडियारा प्रवाह के निकट एक जलाक्रान्त क्षेत्र में टेलीफून लाइनों के निरीक्षण के लिए तैनात की गई थी। वह सभी तैराक थे और उनके पास दण्ड भी थे। उन्होने त्रुटिग्रस्त लाइन को ठीक कर दिया, परन्तु वह अपनी यूनिट को लौट न सक क्योंकि तब तक गाड़ी छूट चुकी थी। दूसरे दिन प्रातः लौटने से पहले उन्होंने जी० टी०मार्ग पर एक सैनिक स्थान से निरीक्षण किया कि आया लाइन काम कर रही या नहीं। लाइन अभी

अच्छी तरह ठीक नहीं हुई थी और उसे ठीक करने के लिए वे पुनः वहीं लौट गए। उन में से एक स्नैपवायर के दो ढ़ीले सिरों को पक्का करने के प्रयास में उन्हें अच्छी तरह खेंचने के अभिप्राय से आगे बढ़ा, और प्रवाह में गिर गया। चूकि वह बाहर नहीं आया, उसके दो साथी उसे बचाने को पानी में कूद पड़े ; पर तु वह भी बाहर नहीं आए। चौथे ने संकट का आभास पाकर शोर मचाया, और कुछ असैनिक उसकी सहायता को आए, परन्तु वे तीनों सैनिक से विवर्ग के शव ही ढूंढ़ पाए। सभी शव सैनिक हस्पताल अमृतसर को भेजे गए और शव परीक्षण तथा मृतकों सम्बन्धी न्यायालय की जांच के पश्चात् उनका दाह संस्कार कर दिया गया। इस मामले की छान बीन के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी प्रगतिशील है।

विमान चालकों को वायु सेना छोड़ने की अनुमति

687. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भगवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या वायु सेना से विमान चालकों को असैनिक विमान चालकों के रूप में जाने की अनुमति दी जाती है ताकि वे भारत के असैनिक वायु सेवा विनियमों के अन्तर्गत काम कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों को वायु सेना छोड़ने की अनुमति किन शर्तों पर दी जाती है ;

(ग) कितने विमान चालकों को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया में सेवा करने के लिए वायु सेना छोड़ने की अनुमति दी गयी है ;

(घ) क्या असैनिक एयर लाइनों में भर्ती होने के बाद उन्हें वायु सेना से कुछ लाभ उपलब्ध होते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो वे लाभ क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में नियुक्ति के लिए 12 विमान चालकों को सेवा से विमुक्त किया गया है। इनमें से 8 आग्जिलरी एयर फोर्स के विमान चालक थे और 12 अल्पकालीन कमीशन प्राप्त असफसर। आग्जिलरी एयर फोर्स अफसरों ने अपनी कमीशनों के लिए त्यागपत्र दिये थे और अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों की कमीशनें उनके आई० ए० सी० में प्रवेश पर समाप्त कर दी गई हैं। इन अफसरों को आंतरिक उपदान देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, स्थायी कमीशन धारण करने वाले 19 विमान चालकों को डिपुटेशन पर भेजा गया है और उनके स्थायी तौर पर उस संगठन में खपाया जाना उनके एक वर्ष की प्रोवेशन अवधि सफलता पूर्वक सम्पूर्ण करने पर निर्भर होगा। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रोवेशन अवधि सम्पूर्ण न कर पाए, आई० ए० एफ० सेवा में लौट आयेंगे। एयर इण्डिया में उनकी प्रोवेशन अवधि आई० ए० एफ० में वर्दी भत्ते कार्यवाहक पदोन्नति के सिवाय सब उद्देश्यों में लिए आई०

ए० एफ० सेवा के तौर पर गण्य होगी। डिपुटेशन के दौरान वह अफसर, वेतन और भत्ता तथा अन्य उपलब्धियों के लिए आई० ए० एफ० नियमों के अधीन शासित होंगे। एयर इण्डिया में डिपुटेशन के कारण मृत्यु और निर्योग्यता के मामले में अफसरों के हताहत होने के निर्णय एयर इंडिया या वायु सेना के नियमों के अनुसार होंगे जो अधिक लाभकर होंगे, शेष के लिए एयर इण्डिया उत्तरदायी होगा। जो अफसर एयर इण्डिया द्वारा खपा लिए गए, उन्हें उसी तिथि से वायु सेना के नियमों के अनुसार पद और सेवा के अनुरूप रिटायर होने की पेन्शन उपदान लाभों सहित सेवा से विमुक्त पर दिया जाएगा जिस दिन से उन्हें उस सेवा में खपा लिया गया।

गुलमर्ग में अनुसन्धान प्रयोगशाला

688. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलमर्ग स्थित उच्च शिखर अनुसन्धान प्रयोगशाला में फिर से काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे वहां से हटा कर कहीं अन्यत्र ले जाने का है ;

(ग) क्या काश्मीर के अतिरिक्त उत्तर भारत में किसी स्थान पर नई उच्च शिखर अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित करने की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रयोगशाला के लिये स्थान अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जादुगुडा में यूरेनियम का कारखाना

698. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जादुगुडा में यूरेनियम के कारखाने का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने ने कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ग) इस कारखाने की कुल क्षमता कितनी है और क्या यह पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है ; और

(घ) क्या इस कारखाना में इसके निकटवर्ती खानों का दैनिक उत्पादन पूरी तरह काम में आ जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इस मिल का, जिसे प्रति दिन 1,000 टन कच्चे यूरेनियम को साफ करने के लिये बनाया गया है निर्माण-कार्य लगभग पूरा होने वाला है और कुछ अनुभागों को चालू करना पहले ही आरम्भ कर दिया गया है ।

(घ) जी, हां ।

दक्षिण रोडेशिया में अवैधानिक शासन सत्ता

690. **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रोडेशिया में अवैधानिक जातिवादी सरकार के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों के अनुसार विभिन्न देशों ने किस हद तक कार्य किया है और उन संकल्पों का सम्मान किया है ;

(ख) क्या इस संबंध में जातिवादी सरकार को बाध्य करने के लिये कोई नया प्रयत्न किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किया गया है और उसका क्या प्रभाव हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र के बहुत से सदस्य राज्यों में संयुक्त राष्ट्र के रोडेशिया संबंधी विभिन्न प्रस्तावों में कथित कार्रवाई को कार्यरूप दिया है। लेकिन, कुछ देशों ने अवैध सरकार के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर आंशिक प्रतिबंध ही लगाया है। केवल दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल ने ही संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अवहेलना की है और वे विद्रोही सरकार के साथ न सिर्फ व्यापार कर रहे हैं और अन्य संबंध बनाए हुए हैं बल्कि उन्होंने इसे पहले से और ज्यादा कर दिया है।

(ख) और (ग) हाल ही में लंदन में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विस्तार के साथ विचार किया गया था। इस बात पर ध्यान दिया गया है कि अगर स्मिथ सरकार विद्रोह को समाप्त करने के लिए प्रारम्भिक और अपरिहार्य कदम नहीं उठाती तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार इस वर्ष के खत्म होने से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव के रखने में सम्मिलित होने को राजी हो जाएगी जिसमें कि रोडेशिया के विरुद्ध कारगर और चुने हुए आदेशात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है।

हिन्द-चीन क्षेत्र की जातियों की तटस्थता

691. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द-चीन क्षेत्र की जातियों की तटस्थता तथा उनके आत्म-निर्णय के अधिकार को कायम करने एवं उसकी गारंटी करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या; और

(ख) हमारे प्रधान मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया था तथा फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो प्रस्ताव रखा था, उनके बारे में सम्बद्ध देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है तथा अन्य देशों से उन प्रस्तावों की जो सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भारत ने अब तक क्या अनुमान लगाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) भारत सरकार को यह मालूम नहीं है कि इस संबंध में हाल ही में कोई ठोस प्रगति हुई हो।

(ख) प्रधान मंत्री ने 7 जुलाई, 1966 को जो सुझाव दिए थे, उनकी सामान्य प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने वियतनाम समस्या पर कुछ विचार व्यक्त किए थे, उनका भी कुछ देशों में स्वागत हुआ है। वियतनाम की समस्या बड़ी पेचीदी है और ये प्रस्ताव समाधान खोजने में सहायक हैं।

कीनिया से भारतीयों का निर्वासित किया जाना

692. **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री राम सहाय पाण्डेय** :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया की सरकार ने 15 अगस्त, 1966 को भारतीय मूल के छह व्यक्तियों के निर्वासन के बारे में 'वायस आफ कीनिया' द्वारा किये गये आपत्तिजनक उल्लेख के बारे में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा भेजे गये पत्र का कोई उत्तर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा कैनिया की सरकार को यह स्पष्ट किये जाने के पश्चात् भी, कि ब्रिटिश पारपत्र वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भारत न भेजा जाये, ऐसे व्यक्तियों को भारत भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को भारत भेजा गया है और इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कीनिया स्थित हमारे हाई कमिश्नर के विरोध के उत्तर में उन्हें जबानी तौर पर आश्वासन दिया गया है कि अगस्त, 1966 के दौरान वायस आफ कीनिया से जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें कही गई थीं, वे कीनिया सरकार की नहीं हैं और यह कि इस तरह की घटनाओं को फिर न होने देने की हर कोशिश की जायेगी। लगता है कि वायस आफ कीनिया इस आश्वासन के अनुसार आचरण कर रही है।

(ग) और (घ). कीनिया से भारत को विपत्तन होने के कोई और मामले नहीं हुए हैं।

चुनिन्दा फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट

693. श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी ।
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सुझाव पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है, कि फिल्म सेंसर बोर्ड को एक ऐसे प्रस्ताव का विचार करना चाहिये कि जिसके द्वारा वह अति सौन्दर्य बोधक एवं कलात्मक उच्चता वाली चुनींदा सोद्धेश्य फिल्मों को राज्य सरकारों से मनोरंजन कर से छूट दिलाने की सिफारिश करे ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) में दिये गये सुझाव के साथ साथ ऐसी फिल्मों के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा उत्पाद-शुल्क लौटा दिये जाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ख) सरकार ऐसी सोद्देश्य फिल्मों को करों की छूट देने का विचार कर रही है जो सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर हों और कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हों। इस प्रकार की फिल्मों का अंतिम चयन एक समिति करेगी जो इस उद्धेश्य के लिये विशेष रूप से गठित की जायेगी। इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर जो फिल्में कर से छूट के योग्य होंगी उन पर यह समिति विचार करेगी। इस योजना का ब्योरा तय किया जा रहा है।

Aircraft Manufactured at H.A.L. Kanpur

694. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of aircraft manufactured every year in the Kanpur unit of the Hindustan Aeronautics Limited and the number of aircrafts, from amongst them, which are received back in the factory for repairs;

(b) the total annual expenditure incurred on the salaries of workers and management;

(c) the reasons for not manufacturing the parts of aircrafts in the factory and importing cent per cent parts from abroad; and

(d) the arrangements made to ensure that the factory does not run in loss?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) The number of aircraft already manufactured by the Kanpur Division is as follows:—

1964-65	3
1965-66	3
1966-67	2

(Upto October, 1966).

None of the aircraft has been received back for repairs by Kanpur Division, H.A.L.

(b) The annual expenditure incurred on the salaries of workers and management from the time the Aircraft Manufacturing Depot, Kanpur was merged in Hindustan Aeronautics Limited is as follows:—

1-6-1964 to 31-3-1965	Rs. 61·78 lakhs.
1965-1966	Rs. 95·21 lakhs.

(c) It is not economical to produce all the parts indigenously, related to the small order of aircraft on the factory at Kanpur. In the first phase of manufacture covering 16 aircraft, the manufacture at the Factory at Kanpur consisted mainly of assembly. In the second phase covering 12 aircraft, indigenous manufacture of detail parts relating to fuselag has been taken up.

(d) The factory can work at a profit only if there is an adequate order for the transport aircraft. Additional requirements of the Indian Airlines Corporation are being assessed and when further orders are placed, it is expected that economic production would be achieved.

पाकिस्तान की सैनिक तैयारी

695. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री फिरोडिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० च० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :

श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लारकर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बासप्पा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री तुलाराम :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान ने अन्य देशों के हथियार और गोला बारूद की सहायता से अपनी आन्तरिक तथा बाहरी सैनिक तैयारी किस हद तक की है; और

(ख) भारत ने ताशकंद घोषणा के बाद चीन तथा पाकिस्तान की सांझी धमकी तथा सैनिक तैयारियों का सामना करने के लिये कितनी तैयारी की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पाकिस्तान की सैनिक तैयारी का अन्दाजा, विशेषकर चीन से प्राप्त सैनिक सप्लाइयों के फलस्वरूप तथा अन्य देशों से सहायता के साथ इस सदन में रक्षा मंत्री द्वारा 1 और 8 अगस्त, 1966 के दिये वक्तव्यों में पहले ही दिया जा चुका है; स्पष्ट है कि हाथियार जुटाने की क्रिया जारी है।

(ख) चीन और पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा के लिये संकट का सामना करने के लिये हमने उपाय किये हैं। उनके विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

भारत-श्रीलंका करार

696. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1964 में भारत-श्रीलंका समझौता होने के बाद कितने भारतमूलक राष्ट्रिकता विहीन व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई हैं अथवा कितने लोगों को भारत लौटाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत भारतीय भूल के किसी राज्य विहीन व्यक्ति को श्रीलंका की नागरिकता अभी नहीं दी गई है।

खबर है कि 6,639 व्यक्तियों में से, जिन्हें अक्तूबर, 1964 से भारतीय नागरिकता दी गई है लगभग 1500 व्यक्ति भारत वापस आ गए हैं।

Statement by Indian Consul-General in South Vietnam on U.S. Bombing

697. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1624 on the 8th August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry regarding the statement made by India's Consul-General in South Vietnam on U.S. bombing of North Vietnam has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when it is likely to be completed?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) to (c). The enquiry regarding the statement alleged to have been made by the Officer is in progress and is expected to be completed shortly.

शास्त्री निकेतन

698. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में शास्त्री निकेतन स्थापित करने में सहायता देने के बारे में कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) इस समय शास्त्री-निकेतनों की स्थापना में सहायता देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है ; सहायता के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव के कार्य

699. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965–66 की विश्व की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव के प्रतिवेदन पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने महा-सचिव के कार्यों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई पहल की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव के कार्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बताए गए हैं और उनका क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके ही बढ़ाया जा सकता है; इस पर अभी विचार नहीं हो रहा है ?

ताइवान के छात्रों द्वारा वीसा के लिये आवेदन पत्र

700. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन गणतन्त्र (ताइवान) के छात्रों के वीसा संबंधी आवेदनपत्र सरकार द्वारा मंजूर नहीं किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । लेकिन ऐसे ताइवानी विद्यार्थी इसके अपवाद हैं जो भारत में पैदा हुए हैं ; जिनके परिवार भारत में बसे हैं और जो अध्ययन के लिए ताइवान जाते हैं ; उन्हें भारत वापस आने के लिए वीज़ा दिये जाते हैं ।

(ख) भारत चीन गणराज्य (ताइवान) को मान्यता नहीं देता और न भारत के उसके साथ कोई कौंसली संबंध हैं ।

पाकिस्तान में नजरबंद भारतीय कर्मचारियों का स्वदेश लौटाया जाना

701. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय कर्मचारियों के स्वदेश लौटाये जाने के बारे में 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भारतीयों को जो अब भी पूर्वी पाकिस्तान में हैं रिहा करवाने तथा उनको भारत में लाने के सम्बन्ध में सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तान से अभी तक अंतिम रूप से कोई उत्तर नहीं आया है । भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले पर लिखा-पढ़ी कर रही है ।

बर्मा में मांडले जेल में स्मारक भवन (मेमोरियल हाल)

702. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 29 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांडले जेल के स्मारक भवन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा अन्य देश-भक्तों के सम्मान में संगमरमर के शिलाखंड लगाने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). बर्मा सरकार को इस विषय में हमारी रुचि की जानकारी है लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

ब्रिटिश इम्पीरियल डिफस कालेज के पदाधिकारियों के एक दल का दौरा

703. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीची बावा :
श्री ब० कु दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ब्रिटिश इम्पीरियल डिफेंस कालेज के पदाधिकारियों के 15 सदस्यीय दल ने भारत का चार दिन के लिए दौरा किया है ;

(ख) दौरे का प्रयोजन क्या था और भारत में दौरे के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इनके दौरे के परिणामों का कोई अनुमान लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ङ) भारत में उस दल के दौरे के लिए व्यय किसने किया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). इम्पीरियल कालेज, लन्दन के 15 कर्मचारीगण और छात्र अफसरों पर सम्मिलित एक दल ने देश का 7 सितम्बर से 15 सितम्बर, 1966 तक और पुन: 18 से 20 सितम्बर, 1966 तक भ्रमण किया।

ऐसे भ्रमणों का उद्देश्य है छात्र अफसरों के दृष्टिकोण को उदार बनाना। दल ने दिल्ली अतिरिक्त आगरा, अम्बाला, श्रीनगर, कलकत्ता, पूना, बंगलौर, मद्रास और बम्बई का भ्रमण किया। प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए श्रीनगर में वह 4 दिन रहे। हमारे राष्ट्रीय रक्षा कालेज के दल भी पडोस देशों के भ्रमण करते रहे हैं।

(ग) तथा (घ). स्वयं छात्र अफसरों के लिए लाभकर होने के अतिरिक्त ऐसे भ्रमण सद्भावना पैदा करते हैं।

(ड़) यात्रा, परिवहन, खानपान और वास्य पर उठा खच भ्रमकों ने स्वयं वहन किया। रक्षा मंत्रालय और सेवाओं के अधिकरणों द्वारा विशेष मनोरंजन पर उठा खर्च भारत सरकार ने वहन किया।

विदेशों में प्रचार

704. **श्री फिरोडिया :**
श्री बासप्पा :
श्री रामसहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विशेषत: अफ्रीकी देशों में प्रचार कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). विदेशों में प्रचार कार्य को मजबूत बनाने के प्रश्न पर बराबर विचार किया जाता है और जब कभी संभव होता है, प्रचार को समुन्नत करने के लिए कदम उठाये जाते हैं। अफ्रीकी देशों में ग्यारह प्रचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

Marathi Film Producers

705. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri S. C. Samanta:
Shri P. C. Boroaah:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri Sonavane:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Marathi Film Producers have asked for some facilities from Government for the development of their industry;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government have any proposal under consideration to give encouragement to those who are producing films in Indian languages?

The Minister for Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). The Marathi Film Producers have invited the attention of Government to certain difficulties encountered by them in regard to incidence of taxation, increased exhibition facilities and financial assistance for production profilms of Government is already seized of these problems which are common to the Film Industry and is considering measures to alleviate the hardships to the extent practicable which will facilitate production and exploitation of Films in Indian languages.

फार्म एंड होम रेडियो ट्रांसमिशन यूनिट

706. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री हु० चं० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फार्म तथा घरेलू रेडियो पारेषण (ट्रान्समिशन) केन्द्रों में प्रसारण कार्य आरम्भ हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इन पर कितना खर्च हो रहा है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसे कितने केन्द्रों के चालू होने की संभावना है ;

(घ) क्या इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि से कोई सहायता मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी और कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) : कृषिकों के उपयोग की खेती सम्बन्धी तथा अन्य तकनीकी जानकारी देने के लिए इस समय केवल 10 फार्म और घरेलू यूनिटें काम कर रही हैं ।

(ख) 9 यूनिटें जून, 1966 में चालू हुई थीं और दसवीं यूनिट का 13 अगस्त, 1966 को उद्घाटन हुआ था। 1966–67 में इन यूनिटों पर 4,70,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रकार की कम से कम 10 और यूनिटें स्थापित करने का विचार है ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि से सहायता प्राप्त करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) इस प्रायोजना के लिए कितनी विदेशी सहायता ली जाय, इस के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

रेडियो सीलोन के साथ झगड़ा

707. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेडियो सीलोन से फिल्मी गीतों तथा विज्ञापनों के प्रसारण पर ली जाने वाली रायल्टी (स्वामित्व) से सम्बन्धित झगड़े को निपटा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बातचीत चल रही है। इंडियन मोशन पिक्चर प्राडयूसर्स एसोसिएशन और रेडियो सीलोन के बीच बात चीत चल रही है।

परमाणु प्रौद्योगिक उद्योग समूह

708. **श्री रा० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में एक परमाणु प्रौद्योगिक उद्योग समूह स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य तथा कृत्य क्या होंगे ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्योग समूह में यूरेनियम कंसेंट्रेट्स को "कांडू" प्रकार के रीएक्टरों के लिए, जिनका निर्माण परमाणु शक्ति का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है, यूरेनियम आक्साईड पयूराल एलीमेंटस में परिवर्तित किया जायेगा। परमाणु बिजली घरों, अनुसन्धान संस्थानों, चिकित्सा संस्थाओं तथा उद्योग से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोनिक इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कम्पोनेंट्स बनाने के लिए हैदराबाद में एक इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी स्थापित करने का भी विचार है ।

भारी जल संयंत्र

709. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी जल संयंत्र का निर्माण-कार्य जिसके चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने की संभावना थी, आरम्भ हो चुका है;

(ख) क्या राजस्थान अणु-शक्ति केन्द्रों को, जिनका निर्माण किया जा रहा है चलाने के लिये इस परियोजना को कार्यान्वित करना बहुत जरूरी है; और

(ग) इस परियोजना का अनुमानित पूंजी व्यय कितना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) स्थान के चयन के सम्बन्ध में जांच और उपकरण के बारे में विशिष्ट विवरण तथा डिज़ाइन तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) सामान्य प्रकार के भारी जल के पावर रीएक्टरों उदाहरणार्थ राजस्थान अणु-शक्ति केन्द्र तथा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले अणु शक्ति केन्द्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देश में भारी जल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना अत्यावश्यक है।

(ग) अवमूल्यन के पश्चात् इस परियोजना की 21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत थी।

फारमोसा के लिये पारपत्र जारी करना

710. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की नीति यह है कि भारतीय नागरिकों को फारमोसा जाने के लिये पारपत्र जारी न किये जायें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : फारमोसा के लिए पासपोर्ट जारी करने की भारत सरकार की नीति नहीं है क्योंकि भारत फारमोसा को मान्यता नहीं देता।

Acquisition of Land for Salvage Depot

711. Shri Brij Raj Singh:..
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had acquired 110 Bighas of land in Nangal Raya Village of Delhi in 1947 for setting up a salvage depot;

(b) whether it is also a fact that no depot has been set up there so far;

(c) whether it is also a fact that neither the compensation has been paid to the land-owners nor their land has been restored to them; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) In 1943, land measuring 262·25 acres from Nangal Raya and other adjoining villages near Delhi Cantonment was requisitioned for defence purposes. In 1946, an area measuring 252·42 acres was de-requisitioned but an area of 18·39 acres therefrom was not surrendered and continued on hire. Thus, an area measuring 28·22 acres occupied by the Salvage Depot continued in military occupation. Out of this area, 9:83 acres is held on requisition and 18·39 acres on hire.

(b) No. Sir. The land was occupied by the Army Salvage Depot upto March 1965. It is now occupied by the Fire Services Research Development and Training Establishment of the Ministry of Defence.

(c) and (d). The aforesaid land is required for defence purposes, and cannot therefore be restored to the land-owners. As regards payment of compensation, Government have sanctioned payment of rental compensation of Rs. 883 per annum in respect of 18·39 acres of land held on hire. Owing to the delay on the part of the local revenue authorities in furnishing the names and addresses of the land-owners, the execution of hiring agreements and payment of rents could not be effected. This work is likely to be completed shortly.

As regards the requisitioned land measuring 9:83 acres, the compensation as assessed by the Collector has been paid for the period from 1943 till 1946. In respect of the period thereafter, the compensation was offered in 1955 by the Collector to the land-owners who refused to accept the same and thus the amounts were deposited in the treasury. Since then, the land-owners have not come forward to accept the recurring compensation fixed by the Collector.

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को परिवहन चिकित्सा तथा आवास की सुविधायें

712. श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों को परिवहन, चिकित्सा तथा आवास सुविधायें नहीं दी जाती हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में अपनी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। एच० ए० एल०, कानपुर कुछ परिवहन बसें चलाता है। चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में उन्होंने ई० एस० आई० योजना चलाई है। उन्होंने अपने कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 283 क्वार्टर भी प्राप्त किये हैं।

(ख) तथा (ग). जी हां।

इन सुख सुविधाओं का उपबन्ध कम्पनी का उत्तरदायित्व है जिसके हां, वर्तमान सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उदाहरणत: उ० प्र० परिवहन से साहाय्यित बसें चलाने के लिए लिखा पढ़ी की है और उत्तर प्रदेश सरकार से फैक्टरी के निकट अधिक राज्य साहाय्यित वास्य भवनों के निर्माण के लिए।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटड, कानपुर

713. **श्री नम्बियार :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में केवल विमानों के पुर्जों को जोड़ने का काम होता है और सभी पुर्जे बाहर से आयात किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में पिछले सात वर्षों में कितने विमानों का निर्माण किया गया;

(ग) निर्मित विमानों में से कितने विमानों की मरम्मत फैक्टरी में की गई; और

(घ) सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने तथा इस मामले में आत्म-निर्भर बनने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) एच० एस० 748 विमानों के संघटों के प्रगतिशील देशीय निर्माण का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए पग उठाये गये हैं, परन्तु छोटे आर्डर के कारण प्रयास सीमित है।

(ख) निर्माण की पहली प्रावस्था में अब तक 8 विमान निर्मित किये गये हैं, और अन्य 8 निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाओं में हैं। दूसरी प्रावस्था जिस में 12 विमान हैं फ्यूजलेज से सम्बन्धित डिटेल पार्ट्स का देशीय निर्माण हस्तगत है।

(ग) अब तक मरम्मत के लिए कोई विमान लौट कर प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) सभी उन अवयवों का देशीय निर्माण आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होगा, जो कानपुर के कारखाने में विमानों के छोड़े से आर्डर से सम्बन्धित है । निर्माण की पहली प्रावस्था में, जिसमें 16 विमान हैं, कानपुर के कारखाने में निर्माण मुख्यत: संयोजन कर रहा है । दूसरी प्रावस्था में जिसमें 12 विमान हैं, फ्यूजलेज से सम्बन्धित डिटेल पार्ट्स का देशीय निर्माण हस्तगत है । आई० ए० एस० की अतिरिक्त आवश्यकताएं निर्धारित की जा रही हैं, और जभी और आर्डर मिले कानपुर कारखाने में एच० एस० 748 विमान के अतिरिक्त अवयवों का निर्माण हस्तगत करना सम्भव हो जाना चाहिए ।

विद्रोही नागाओं की गतिविधियां

714. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के "इण्डियन नेशन" में 'विद्रोही नागाओं की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो नागालैंड में शान्ति बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ग) इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) छिपे नागाओं द्वारा गैर-कानूनी कार्रवाइयों को रोकने और नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए नागालैंड राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है । राज्य सरकार ने प्रशासानिक अधिकारियों को पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं कि हिंसात्मक कार्रवाइयों को रोकने के लिए वे पुलिस की शक्ति का और अगर आवश्यकता पड़े तो सिविल अधिकारियों को सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षा सेना का उपयोग करें ।

(ग) कुछ दुर्घटनाएं नागालैंड में हुई हैं । लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां बढ़ रही हैं । जनवरी से सितम्बर, 1966 तक की अवधि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

1 जनवरी, 1966 से 30 सितम्बर, 1966 तक नागालैंड में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां
(घटनाओं की संख्या)

महीना	नागाओं द्वारा गोलीबारी	हत्या	अपहरण	अन्य घटनाएं
जनवरी	1	–	22	1
फरवरी	–	–	17	–
मार्च	–	–	6	1
अप्रैल	–	–	7	1
मई	1	1	8	–
जून	–	1	1	–
जुलाई	–	–	–	10
अगस्त	–	–	–	13
सितम्बर	–	–	–	9

News Broadcast

715. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the news broadcasts, which took place during the last session of Parliament, have given publicity only to Opposition parties; and

(b) if so, whether Government are considering the proposal to allot time to various political parties for news broadcast on the basis of their strength in Parliament?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No, **Sir.**

(b) Does not arise.

कच्छ क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के विरुद्ध पाकिस्तान का विरोध

716. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री बासप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ के रण में सीमावर्ती क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के बारे में पाकिस्तान ने भारत से विरोध प्रकट किया है और यह भी कहा है कि वह इस मामले में जो भी कार्यवाही आवश्यक समझे कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सूचना दी है कि जैसा कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया है, 24 समानान्तर के उत्तर में कोई सड़क बनाने का काम नहीं किया गया है ।

आकाशवाणी केन्द्र, कालीकट का प्रादेशिक समाचार एकक

717. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के आकाशवाणी केन्द्र के प्रादेशिक समाचार एकक को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इससे लक्कदीव द्वीपसमूह के श्रोताओं पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मलयाली कार्यक्रम

718. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में मलयाली भाषी लोग बहुत हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी की विदेश सेवा में कोई मलयाली कार्यक्रम शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में विदेश सेवा कार्यक्रम में मलयाली कार्यक्रम चालू करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विदेश में मलयाली भाषी लोग कितने हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विदेशों में श्रोताओं के लिए कौन कौन सी प्रसारण सेवाएं होनी चाहिए, इसका निश्चय करने में सरकार कई बातों को ध्यान में रखती है जिनमें मुख्य बातें हैं टैक्नीकी तथा अन्य साधनों की उपलब्धि और प्रसारण क्षेत्र का महत्व । संसार की स्थिति को देखते हुए अधिक महत्व उन प्रसारणों को दिया जाता है जो विदेशी श्रोताओं को आधारभूत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत की स्थिति और उसका दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं । इस प्रकार के प्रसारणों की आवश्यकता को देखते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए प्रसारणों की प्राथमिकता स्वाभाविक ही कम है ।

(घ) जी, नहीं ।

त्रिवेन्द्रम में कमजोर ट्रांसमीटर

719. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम का ट्रान्समीटर बहुत कम शक्ति का है और त्रिवेन्द्रम जिले के कुछ तालकों में भी आवाज बड़ी धीमी सुनाई देती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस ट्रान्समीटर की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) त्रिवेन्द्रम में इस समय मीडियम वेव के दो ट्रांसमीटर हैं। इनमें एक मध्यम शक्ति का है और दूसरा अल्प शक्ति का। अल्प शक्ति वाला ट्रान्समीटर जिससे विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं केवल त्रिवेन्द्रम और उसके इर्द गिर्द के शहरी क्षेत्र के लिए है। मध्यम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के कार्यक्रम त्रिवेन्द्रम जिले के अधिकांश भाग में संतोषजनक रूप से सुने जाते हैं ।

(ख) साधन की कमी के कारण त्रिवेन्द्रम के ट्रान्समीटर की शक्ति और बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं होगा।

मिग कारखाना, कोरापुट

720. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कोरापुट उड़ीसा में मिग कारखाने के कार्यों से संबंधित निविदाओं को स्वीकार करने के बारे में कुछ कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच विभाग से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) असैनिक निर्माणकार्य राँज्य सरकार द्वारा हस्तगत किए जा रहेहैं। सेन्ट्रल ब्यूरों आफ इन्वेस्टीगेशन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों से संबद्ध है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अम्बाझारी कारखाना

721. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक ऋण विक्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीकी सहायता से अम्बाझारी आयुध कारखाने की स्थापना में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि सहायता उपलब्ध हो, तो क्या उसे स्थगित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का अमरीकी सहायता के बिना इस कार्यक्रम को किस प्रकार आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रायोजना अध्ययन के लिये वित्त सैनिक-ऋण-क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत जुटाया गया था। इस प्रायोजना के लिए आगामी सहायता अभी स्थगित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अम्बाझारी कार्यक्रम मुख्यत: स्वतंत्र विदेशी मुद्रा से प्रगतिशील बनाया जा रहा है।

पोर्टेबल एयर कम्प्रैशर

722. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप में जापानी सहयोग से पोर्टेबल एयर कम्प्रैशरों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ हुआ था;

(ग) क्या उसमें अब तक कोई कम्प्रैशर बनाये गये हैं ;

(घ) क्या उनका परीक्षण किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये कम्प्रैशर जापान में बनाये गये कम्प्रैशरों की तुलना में कैसे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां। गार्डन रीच वर्कशाप लि० जापान की सर्वश्री कोकुएत्स् काग्यों कम्पनी से लाइसेंस करार के अन्तर्गत सुवाहम घूर्णक वायु संपीडकों का निर्माण कर रही है। करार के अन्तर्गत (160 सी०एफ०एम०, 250 सी०एफ०एम०, 340 सी० एफ० एम० और 600 सी० एफ० एम०) चार प्रकार के वायु संपीडक निर्माण के लिए हस्तगत किए जा रहे हैं।

(ख) संघटकों का निर्माण 1965 में आरम्भ हो गया था और 250 सी० एफ० एम० और 340 सी० एफ० एम० वायु संपीडकों का संयोजन सितम्बर 1966 में।

(ग) एक वायु संपीडक संयोजित हो चुका है और चार अंतिम संयोजन प्रावस्था में हैं।

(घ) तथा (ङ). संपीडकों का निरीक्षण किया गया है और सहयोगियों द्वारा निर्मित संपीडकों से अच्छी तरह लाग खा सकता है।

हैदराबाद में वायु सेना अकादमी

723. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में वायु सेना अकादमी का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) उसके द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी नहीं।

(ख) समग्र प्रायोजना के 1971 तक सम्पूर्ण होने की आशा है।

(ग) आशा है अकादमी लगभग 1969 के मध्य तक काम करना आरम्भ कर देगी जिस समय तक प्रायोजना की पहली प्रावस्था सम्पूर्ण होने की प्रत्याशा है।

ढाका में भारत-पाकिस्तान संघर्ष सम्बन्धी इश्तहारों की प्रदर्शनी

724. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढाका में एक चीनी चित्रकार ने पाकिस्तान की सुरक्षा के प्रयास में ऐसे इश्ताहारों की प्रदर्शनी लगाई थी जिनमें सितम्बर 1966 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष को चित्रित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के पुस्तकालय

725. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के पुस्तकालयों में इस समय कुल कितनी पुस्तकें मौजूद हैं और उनमें अंग्रेजी तथा हिन्दी की पुस्तकों की पृथक् पृथक् संख्या क्या है ;

(ख) इन पुस्तकालयों के वाचनालयों में हिन्दी और अंग्रेजी के कितने समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती हैं ;

(ग) क्या हिन्दी की पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

Indian Tunes of Military Bands

726. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of countries which have shown interest in the Indian tunes of Military bands;

(b) the number of Indian tunes for which demand has been received from foreign countries;

(c) the names of countries to which these have been sent and the number of tunes sent to them, countrywise; and

(d) the future programme to increase the number of these tunes?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) to (c). We have received enquiries showing interest in Indian Military band tunes from countries like Thailand, Laos and USA along with requests for supply of music scores. Accordingly 17 music scores have been supplied to the concerned authorities in Thailand, 12 in Laos and six in USA.

(d) There is no programme at present to increase the number of these tunes.

Weeklies and Monthlies Purchased by External Affairs Ministry

727. Shri Ram Sewak Yadav: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry purchase weeklies and monthlies and send them to foreign countries; and

(b) if so, the basis on which this is done and whether magazines containing opposite views are also purchased and sent to the foreign countries?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir; some periodicals are sent to Indian Missions abroad.

(b) The periodicals are selected on the basis of recommendations of Indian Missions keeping in view their national prominence, usefulness abroad, local demand and cost. Such selection covers national activities in their entirety and project a representative picture of India as far as possible.

Electronic Factory in Ballabhgarh

723. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Mohan Swarup:
Shri R. Barua:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an electronic factory is being set up in Ballabhgarh (Faridabad) with German collaboration;

(b) if so, the nature of assistance to be provided by Germany;

(c) the proposed capacity of the factory and the expenditure to be incurred thereon; and

(d) whether any progressive earning of foreign exchange will be possible as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) The foreign company will provide technical know-how and subscribe for shares of the value of cost of imported plant and machinery required for the project upto 49 per cent. of the equity capital of the firm.

(c) The equity capital of the firm will be Rs. 75 lakhs and its proposed installed annual capacity will be as follows :

Item	Capacity annual (Nos.)
1. Radio Receivers	40,000
2. Radio components :	
(i) I. F. Transformers	3,96,000
(ii) Audio & output Transformers	2,64,000
(iii) Coil sets	1,32,000
(iv) Paper condensers	9,60,000
(v) Loudspeakers upto 8"	2,40,000
(vi) Band switches	2,40,000
(vii) Mica condensers	9,60,000
(viii) Valve and transistor holders	9,60,000

(d) The firm will be permitted to export freely the items produced by it, and it should be able to earn foreign exchange progressively as it secures markets abroad.

Pension Rates for J.C.Os.

729. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give higher pension to Short-Service Commissioned Officers and Temporary Commissioned officers:

(b) if so, the former and the revised rates of pension; and

(c) when it will be given effect to?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) yes, Sir.

(b) and (c) The old and revised rates of the minimum pension admissible to JCOs/ORs, who were granted short service and temporary commissions and who opted to forego the terminal gratuity in respect of their commissioned service and to count their commissioned service towards pension in the substantive rank held before the grant of officers' commission, are as follows :—

Total Qualifying Service As For A Combatant	Old Rate	Revised Rate
Years	Rs. p. m.	Rs. p. m.
15	100.00	115.00
16	105 00	120.00
17	110.00	125.00
18	115.00	130.00
19	120.00	135.00
20	125.00	140.00
21	130.00	145 00
22	135 00	150.00
23	140.00	155.00
24	145.00	160.00
25 and above	150.00	165.00

2. The revised rates have effect from 1st April 1961, that is they apply to the officers who became/become non-effective on or after that date and who had elected/who elect to make the option referred to above.

तारापुर परमाणु बिजली घर

730. **श्री महेश्वर नायक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना प्रशासन की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि तारापुर परमाणु बिजली घर में तैयार की गई बिजली की लागत 3·7 पैसे से लेकर 4·9 पैसे प्रति यूनिट तक आयेगी कब तक इस बिजली घर में बिजली तैयार की जाने लगेगी तथा उससे देश की आवश्यकता पूरी होने लगेगी ;

(ख) अन्य दोनों परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) इन तीनों परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आशा है कि तारापुर परमाणु बिजली घर अक्तूबर 1968 तक पूरी क्षमता से कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य ने राजस्थान तथा मद्रास परमाणु बिजली केन्द्रों के सम्बन्ध में पूछा है आशा है ये बिजली घर निम्नलिखित तारीखों को चालू हो जायेगें :—

राजस्थान परमाणु बिजली घर	पहला एकक - 1969
तदेव	दूसरा एकक - 1971
मद्रास परमाणु बिजली घर	पहला एकक - 1971
तदेव	दूसरा एकक - 1973

(ग) अनुमान है कि इन तीनों बिजली घरों पर इस प्रकार लागत आयेगी :—

	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
तारापुर परमाणु बिजली परियोजना	85.47
राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना	104.00
मद्रास परमाणु बिजली परियोजना	104.00

Trained Librarians for Indian Mission

731. **Shri Vishram Prasad:**
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Daljit Singh:
Dr. Ranen Sen:
Shri P. H. Bheel:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether there are trained Librarians available in his Ministry, at present;

(b) if so, their number and qualifications;

(c) whether some of these will be sent for appointment against the existing vacancy in the Library of the Consulate General in New York and against the posts that are likely to fall vacant in Indian High Commission in London; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) They are 5 in number—1 Librarian and 4 Assistant Librarians. All are either Graduates or Post Graduates and possess Diploma in Library Science.

(c) and (d). It has been decided in principle to convert the existing local post of Librarian in each of our Missions in New York and London into that of India-based Librarian. It is intended to select the incumbents from among the suitable Librarians working in the Government of India Offices in consultation with the Union Public Service Commission. The eligible librarians in the Ministry of External Affairs can also apply for the posts.

Trained Librarians in Indian Missions Abroad

732. **Shri Kashi Ram Gupta:** **Shri Daljit Singh:**
Shri Vishram Prasad: **Shri Ranen Sen:**
Shri Nardeo Snatak: **Shri P. H. Bheel:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether several Indian Embassies abroad have requisitioned the services of trained Librarians;

(b) If so, the names of Embassies;

(c) the arrangements being made for sending trained persons to Embassies; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh (a) and (b). Yes, Sir. The following 16 Embassies have asked for trained Librarians from India;

(1) Jedda (2) Rome (3) Beirut (4) Kuala Lumpur (5) Karachi (6) Ottawa (7) Nairobi (8) Bonn (9) Kabul (10) Dar-es-Salaam (11) Damascus (12) Gangtok (13) Rabat (14) Tokyo (15) London (16) New York.

(c) and (d). It has not so far been possible to send trained librarians for want of budgetary resources and because of the difficult foreign exchange position.

Arrangements will be made to send trained librarians to those Missions where the extent of work so justifies as soon as the financial and foreign ex-

change position improves. However it has been decided in principle to send India-based librarians.

देहू मोटर-गाड़ी डिपो

733. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहू मोटर-गाड़ी डिपो—प्रतिरक्षा विभाग को बन्द कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ख) इस कार्यवाही के फलस्वरूप कितने कर्मचारी बेकार हो गए हैं अथवा बेकार होने की सम्भावना है ;

(ग) इस डिपो के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत पर अब तक कुल कितनी लागत आई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस डिपो में किया जाने वाला कार्य इस के पश्चात् किसी और डिपो में किया जाएगा ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो तो जिस डिपो में देहू डिपो का कार्य हस्तान्तरित किया जाएगा उस संस्थापन पर कितना व्यय किया गया है अथवा किया जाएगा ; और

(च) देहू मोटर-गाड़ी डिपो के कर्मचारियों को क्या वैकल्पिक रोजगार—क्षतिपूर्ति—पुनः प्रशिक्षण दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केन्द्रीय गाड़ी डिपो देहू को बन्द कर देने का विचार है।

(ख) तथा (च) अभी तक किसी कार्मिक की छंटनी नहीं की गई। केन्द्र द्वारा शासित असैनिक गैर-औद्योगिक कर्मचारी, केन्द्रीय रोस्टर पर उनकी वरिष्ठता के अनुसार अन्य डिपुओं में खपाये जाएंगे। औद्योगिक कर्मचारी और स्थानीयतः शासित गैर औद्योगिक कर्मचारी यथा सम्भव देहू-पूना क्षेत्र में अन्य डिपुओं में खपाये जाएंगे। शेष जहां तक रिक्त स्थान प्राप्त हुए, अन्य रक्षा सिब्बन्दियों में खपाए जाएंगे। वैकल्पिक काम को स्वीकार करने में गैर रजामन्द औद्योगिक कर्मचारियों तथा स्थानीयता शासित गैर औद्योगिक कर्मचारियों को जिन्हें वैकल्पिक काम की पेशकश नहीं की जाती, साधारण नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने कर्मचारी छंटनी किए जायेंगे।

(ग)

निर्माण . . .	7,12,000 रुपये
अनुरक्षण	5,22,000 रुपये
मरम्मत	1,72,000 रुपये
कुल योग . . .	14,06,000 रुपये

(घ) गाड़ियां रद्द करने की नीति पर अमल करने से डिपुओं में रहने वाली अखिल-भारतीय गाड़ियों का सुरक्षण देहू गाड़ी डिपो को बनाए रखना अनावश्यक बना देने से पहले से बहुत कम हो जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Military Truck Accident

734. Shri Mohan Swarup: **Shri Brij Raj Singh:**
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a military truck met with an accident near Dharchula on the 25th September, 1966; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). A military truck carrying Army personnel fell in a khud at about 17.15 hours on 24th September, 1966 near Mile Stone 6-7 on Dharchula-Relagat road. As a result of this accident, 19 Army personnel including 1 JCO died and 8 Army personnel sustained serious injuries. The injured were admitted in Military Hospital, Bareilly. A Military Court of Inquiry to investigate the cause of the accident is in progress.

पादरी माइकल स्काट

735. श्री भागवत झा आजाद : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री दे० द० पुरी :
श्री स० चं० सामन्त : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा : श्री बसुमतारी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड शान्ति दल के भूतपूर्व सदस्य पादरी माइ कल स्काट ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपनिवेशवाद विषयक समिति के समक्ष नागालैण्ड का प्रश्न उठाने का गुप्त रूप से प्रयत्न किया ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रश्न किस प्रकार और किन शब्दों में उठाया गया; और

(ग) समिति में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का उत्तर क्या था और इस बारे में समिति की प्रतिक्रिया क्या थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र उपसमिति के सामने माइकल स्काट ने नागालैण्ड का उल्लेख किया था; उन्होंने इसका उल्लेख पाकिस्तानी प्रतिनिधि के एक सवाल के जवाब में किया था जिसमें उन्होंने माइकल स्काट से पिछले दो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र से अनुपस्थित रहने के कारण पूछे थे ।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि ने तत्काल ही आपत्ति की और कहा कि माइकल स्काट एक ऐसे मामले का जिक्र कर रहे हैं जिसका विचाराधीन विषय दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के सवाल से कोई सरोकार नहीं । समिति के प्रधान ने भारतीय प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आपत्ति को ठीक माना और स्काट को निर्देश दिया कि वे सिर्फ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बारे में ही टिप्पणी करें । ऐसा समझा जाता है कि इस समिति के कई सदस्यों ने माइकल स्काट की इस कार्रवाई को गलत कहा और पाकिस्तान की दांवघात की चाल को भी ।

भारत-चीन सीमा विवाद

736. श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री फिरोडिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अं० क० गोपालन :
श्री इम्बीबोबावा :
श्री दशरथ देव :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि वह कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर भारत-चीन सीमा विवाद पर विचार-विमर्श करने तथा उसको निपटाने के लिए तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी न हीं। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Assistance to Tanzania

738. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply gives to Unstarred Question No. 900 on the 1st August, 1966 and state:

(a) the number of Indian experts sent to Tanzania so far; and

(b) the amount in rupees equivalent to the foreign exchange for which the machinery and other goods have been supplied so far?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Three experts have so far been deputed to Tanzania to advise that Government on setting up of an industrial estate. One weaving expert has also been selected for the proposed Handicraft and Cottage Industries Training Centre in Tanzania and he will be leaving for Tanzania soon.

(b) The following items have been gifted to the Government of Tanzania:

(i) Wood-working machinery, Carpentry tools, handlooms etc. valued at Rs. 85,000 CIF.

(ii) 5000 gunny bags valued at Rs. 13.50, CIF. Arrangements are being made to despatch the gunny bags.

Theft of Tyres and Tubes from Palam Air-Port area

739. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 892 on the 1st August, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that investigations have been since completed by the Police into the theft of tyres and tubes at the Palam Airport area;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the investigations?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) No, Sir; the case has been referred to the Central Bureau of Investigation by the Local Civil Police, and the case is under investigation.

(b) This does not arise.

(c) The time likely to be taken for the finalisation of the enquiries by the Central Bureau of Investigations cannot be anticipated at this stage.

Accident on Mahabaleshwar Road

740. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 25 on the 25th July, 1966 and state:

(a) whether a decision has since been taken to grant special pension to the family of the civilian killed in a military accident on Mahabaleshwar Road;

(b) if so, the amount of monthly pension given to them;

(c) whether Government have received the report on the causes of the accident;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, when the report is likely to be received?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). The position is being ascertained.

(c) to (e) The report of the Military Court of Innquiry has not yet been received. The Military authorities have been directed to expedite.

नेपाल को भारतीय सहायता

741. श्री तुलाराम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल की तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए 40 करोड़ रुपये की सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सहायता की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी, हां। इस वर्ष अक्तूबर में प्रधान मंत्री ने अपनी नेपाल की यात्रा के दौरान घोषणा की कि भारत सरकार नेपाल की तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में, जोकि जुलाई, 1965 से जुलाई, 1970 तक है, लगभग 40 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था करना चाहती है। आर्थिक क्षेत्र में नेपाल के साथ सहयोग के कार्यक्रम पर होने वाला वास्तविक खर्च, कार्य की तीव्रता और अन्य सम्बद्ध बातों पर निर्भर करता है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कितना-कितना धन खर्च होगा, इसका विवरण 1966—1971 की हमारी चौथी योजना अवधि के संदर्भ में तैयार किया गया है। इस अवधि में जिन योजनाओं पर धन लगाया जाएगा, उनका संबंध बड़ी-बड़ी चालू प्रायोजनाओं से होगा और इस अवधि में उनके अनुमानित कार्य का मोटे तौर पर विवरण इस प्रकार है :—

	लाख रुपयों में (लगभग)
बड़ी चालू योजनाएं	
सोमाली-पोखरा रोड	990
छत्तरा नहर	450
त्रिशूली पन-बिजली प्रायोजना	450
बड़ी नई प्रयोजनाएं	
पूर्व-पश्चिम राजपथ (पूर्वी क्षेत्र)	2100

इन-कई अन्य छोटी-छोटी प्रायोजनाएं और योजनाएं हैं, जिनमें ऐसी बहुत तरह की स्कीमें आती हैं जिन पर कुछ खर्च किया जायगा। इस के अलावा, कुछ और प्रायोजनाएं भी हैं जैसा कि पूर्व-पश्चिम राजपथ के पूर्वी भाग का निर्माण—जिस पर लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

(ग) भारत की वित्तीय सहायता दोनों सरकारों द्वारा सहमति प्रायोजनाओं और योजनाओं के लिए अनुदान के रूप में होगी। इस में सभी प्रायोजनाएं आ जाएंगी, सिवाय 1 करोड़ रुपये के ऋण के—जो नेपाल में औद्योगिक संस्थाओं को सहायता देने के लिए अलग से निश्चित किया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस ऋण की अदायगी 15 समान वार्षिक किश्तों में करनी है, और ब्याज की दर 3 प्रतिशत होगी।

एच० एफ० 24 परियोजना

742. **श्री मधु लिमये :**
श्री उटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने एच० एफ० 24 परियोजना कब आरम्भ की थी ;

(ख) इसमें अब तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ;

(ग) क्या एच० एफ० 24 के विमान के ढांचे के लिए ब्रिस्टल सिडले एविएशन कम्पनी आफ इंग्लैंड आफियस इंजन का एक नया डिजाइन दे रही है ;

(घ) क्या आफिया के स्थान पर काम आने वाला एक अन्य उपयुक्त इंजन तैयार करने के सम्बन्ध में अन्य देशों /कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है ;

(ङ) क्या इस बातचीत में सफलता मिली है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस एच० एफ० 24 परियोजना का भविष्य क्या होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रायोजना 1956 में स्वीकृत की गई थी।

(ख) विकास की लागत सहित लगभग 25 करोड़।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) यू० ए० आर० में विकासाधीन ई–300 इंजन शायद, एच० एफ० 24 मेक 2 विमान के लिए उपयुक्त शक्ति संयंत्र साबित हो। एच० ए० एल० (बंगलौर विभाग) द्वारा निर्मित एक एच० एफ० 24 फ्रेम यू० ए० आर० भेजा गया है कि ई–300 इंजन के विकास के लिए उड़ान परीक्षण में आधार का काम दे। उड़ान परीक्षण के परिणाम भावी निर्धारण के लिए प्रतीक्षित हैं।

(च) एच० एफ० 24 मेक 1 विमान ए० ए० एल० में उत्पादनाधीन है। कुछ यह विमान भारतीय वायुसेना को डिलिवर कर दिए गए हैं। एच० ए० एल० में एच० एफ० मेक 1 की संशोधित कृति भी विकासाधीन है।

सैनिक समाचार

743. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वारियर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैनिक समाचार" के मुद्रण का कार्य वर्तमान मुद्रक को देने के कोई विशेष कारण थे; और

(ख) क्या "सैनिक समाचार" के मुद्रण के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के वर्तमान मुद्रणालयों में से किसी एक की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) सैनिक समाचार का मुद्रण किसी ऐसी एजेंसी को सौंपना पड़ता है जिसके यहां, ब्लाकों का वह्री सेट प्रयोग में लाकर उन सभी भाषाओं में मुद्रण की सुविधाएं विद्यमान हों कि जिन में सैनिक समाचार प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान मुद्रक उन दो में से एक हैं जिन्होंने कोटेशन भेजे थे, और उन के कोटेशन निम्न होने के आधार पर, वर्तमान मुद्रकों से ठेका कर लिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली बारी

744. **श्री तुलाराम :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर के आरम्भ में पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उत्तेजना के जम्मू-स्यालकोट सीमा से लगते हुए रनबीर सिंह पुरा क्षेत्र में भारतीय पुलिस चौकियों पर लगातार दो दिन तक गोलियां चलाई ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक पर, जो स्थिति की जांच करने आया था तथा सफेद झंडा लिए हुए था और जिसकी जीप पर संयुक्तराष्ट्र के स्पष्ट जिन्ह लगे हुए थे, गोलियां चलाई; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां। वास्तव में पाकिस्तानी गोलाबारी 8 अक्तूबर से 11 अक्तूबर, 1966 तक जारी रही।

(ख) जी, हां।

(ग) संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता की मांग की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने क्षेत्र का भ्रमण किया था। दोनों ओर के सैक्टर कमांडरों की बैठकें आयोजित की गई थीं, जिनके फलस्वरूप 11 अक्तूबर 1966 को युद्ध-विराम कार्यान्वित हुआ, और दोनों सैक्टर कमांडरों ने गोली न चलाना तथा निर्णय योग्य किसी मामले को, अगर कोई हो, उच्च अधिकारियों को सौंप देना स्वीकार किया है।

ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य राज्यमंत्री की भारत यात्रा

745. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ब्रिटेन के वैदेशिक-कार्य राज्य मंत्री नई दिल्ली में आये थे और उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर बात चीत की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार की ओर से उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में तीन परमाणु-शक्तियों—संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस और युनाइटेड किंगडम द्वारा गैर-परमाणु राष्ट्रों को एक सामूहिक गारंटी दिया जाना सम्भव होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (घ) बातचीत के दौरान निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ था। इस बातचीत में आणविक शस्त्रों का उत्पादन न करने पर चर्चा हुई और इस पर भी कि अणु अस्त्रधारी देशों द्वारा गैर-अणु अस्त्र वाले देशों को आणविक युद्ध के विरुद्ध गारंटी देने से और किस हद तक गारंटी देने से इस विषय पर सुविधापूर्वक संधि संपन्न हो सकती है। बहरहाल, लार्ड चैलफांट ने भारत सरकार के विचारार्थ कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखे।

जमाये मांस को डिब्बों में बन्द करने का संयंत्र

746. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा जिले में टूंडला के निकट शीघ्र जमाये गये मांस के डिब्बों में बन्द करने के संयत्र को स्थापित करने के विरुद्ध जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस स्थान पर इसकी स्थापना का विरोध किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां।

(ख) इसका मुख्यत: इस कारण विरोध हो रहा है कि फैक्टरी की स्थापना से, जिसमें प्रतिदिन भारी संख्या में बकरियां और भेड़ें अन्तर्ग्रस्त होंगी, आसपास के क्षेत्रों की जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी, जो शाकाहारी हैं।

(ग) सरकार के विचार में आपत्तियां व्यापक स्वरूप की हैं, जो इस उद्देश्य के लिए चुने गए किसी भी स्थान के लिए समान रूप से हो सकती हैं। वर्तमान स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति से और ऐसी फैक्टरी की स्थापना में अन्तर्ग्रस्त सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात चुना गया था।

Indians in Burma

747. Shri Dhuleshwar Meena: **Shri Ramapathi Rao:**
Shri Vishram Prasad: **Shri C. M. Kedaria:**
Shri Daljit Singh:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons of Indian Origin in Burma who want to return to India;

(b) the handicaps in their coming back to India;

(c) the assistance rendered to them by the Indian Embassy at Rangoon; and

(d) .the time taken by them in obtaining visa ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) About 80,000 Indian citizens in Burma are reported to be wanting to return to India. As regards persons of Indian origin who may be Burmese citizens Government have no information.

(b) to (d). There are no handicaps in the way of the Indian citizens' return. In the case of persons of Indian origin who are Burmese citizens, they have to get travel documents from the Government of Burma. Indian Visas are given on such travel documents by the Indian Embassy in Rangoon without any delay.

केरल में प्रतिरक्षा उद्योग

748. श्री अ० क० गोपालन : **श्री कोल्ला वेंकय्या :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री दशरथ देब :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से अब तक प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उद्योगों में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ख) उक्त अवधि में केरल में कुल कितनी राशि विनियोजित की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए केरल में एक भी कारखाना स्थापित करने की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) वर्ष 1960–61 से अब तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के छः उपक्रमों अर्थात हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, प्राग्य टूल्स लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशापस, मजागांव डाक लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में प्रतिवर्ष खर्च की गई कुल पूंजी इस प्रकार है :—

1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66
(लाख रुपयों में)					
527.55	311.67	284.34	486.14	533.52	831.67

(ख) कुछ भी नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात अब तक केवल कुछ प्रतिरक्षा उत्पादन एकक स्थापित किये गये हैं। ऐसे एककों को स्थापित करते समय विभिन्न बातों जैसे कि बिजली और कच्चे माल की उपलब्धता तथा सामरिक और जल वायु से सम्बन्धित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में यह बताया जाना चाहिए कि ऐसे कई राज्य हैं जिनमें प्रतिरक्षा उत्पादन एकक नहीं हैं, उदहारणार्थ आसाम, गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाना, राजस्थान आदि ।

भारतीय वायु सेना में तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती

749. श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री दशरथ देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना में तकनीकी व्यक्ति अधिकतम संख्या में केरल से भर्ती किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भर्ती कार्यालय बंगलौर में स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल निवासियों का, जो इन पदों में भर्ती होने के इच्छुक हैं, होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(घ) क्या केरल में भारतीय वायु सेना का एक नियमित भर्ती केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय वायु सेना के तकनीकी व्यवसायों के लिए भर्ती किये गये छात्रों की अधिकतम संख्या केरल राज्य से सम्बन्धित है ।

(ख) प्रशासनिक सुविधा के लिए वायुसेना का एक भर्ती केन्द्र बंगलौर में स्थापित किया गया है ।

(ग) तथा (घ). वायु सेना भर्ती केन्द्रों से भर्ती दल अपने अपने सत्ता-क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों का निरीक्षण और चयन करने के लिए भ्रमण करते हैं । वर्तमान प्रबन्ध अब तक सन्तोषप्रद और पर्याप्त सिद्ध हुए हैं ।

जवानों को तबादले के समय निशुल्क सामान ले जाने की सविधा

750. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तबादले के समय जवानों को रेल पर केवल 3 मन सामान नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों को 60 मन सामान नि:शुल्क ले जाने तथा रेलों में अपनी गाड़ियां जैसे कार, स्कूटर तथा मोटर साईकिल की नि:शुल्क बुकिंग कराने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का जवानों को इस समय दी जा रही सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, जो व्यक्ति विवाहित एस्टेब्लिशमेन्ट में हैं उन्हें तीन मन की अनुमति है, और जो अविवाहित एस्टेब्लिशमेण्ट में हैं उन्हें 2 मन की ।

(ख) जी हां, विवाहित अफसरों को नि:शुल्क 60 मन सामान की अनुमति है, और अविवाहित अफसरों को 40 मन सामान की । इसके अतिरिक्त मोटर कारों, स्कूटरों, मोटर साइकलों के परिवहन की इस शर्त के साथ अनुमति है कि नये ड्यूटी स्थानों पर कर्तव्यों के कुशल निष्पादन के मोटर कार इत्यादि की आवश्यकता प्रमाणित की जाये ।

(ग) न तो सेवा कर्मचारियों की दोनों श्रेणियों की यात्रा सम्बन्धी देयताऐं ही समान हैं और न सेवा की शर्तें और परिस्थितियां ही । इसके अतिरिक्त कमीशन प्राप्त अफसरों के विरुद्ध जवानों को नि:शुल्क फर्नीचर उपलब्ध हैं और तदनुसार स्थानान्तरण पर उन्हें भारी सामान साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती ।

(घ) सामान सम्बन्धी देयताओं में बृद्धि का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है, परन्तु स्थानान्तरण पर नकद भत्ते की अदायगी से सम्बन्धित व्यापक प्रश्न विचाराधीन है ।

केरल में विकलांग जवानों के लिये भूमि

751. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए संघर्ष में विकलांग जवानों से केरल में भूमि के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1965 से प्राप्त हुए ऐसे आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें दी गई भूमि का कुल क्षेत्र कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ में गिरजाघर

752. श्री जं० ब० सिं० विष्ट : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ पर पुर्तगाली शासुन की समाप्ति के बावजूद भी गिरजाघर के मामलों के सम्बन्ध में गोआ का गिरजाघर अब भी पुर्तगाल का हिस्सा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर वैटिकन से लिखा-पढ़ी की है और गोआ के गिरजाघर को भारतीय कैथोलिक गिरजाघर का अंग बनाने के लिये कहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गोवा में चर्च पुर्तगाल का कभी भाग नहीं रहा क्योंकि इसका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है । 1937 से भारत-स्थित पोप के प्रतिनिधि के अधिकार-क्षेत्र में गोवा भी शामिल है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"समाचार भारती"

753. श्री जं० ब० सिं० विष्ट : श्री मधुलिमय :
श्री उंटिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने समाचार भारती नाम के समाचार अभिकरण के अंश खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और उन्होंने कितनी कितनी राशि लगाई है; और

(ग) क्या टेलीप्रिंटरों का आयात करने के लिए इस अभिकरण को कोई आयात लाइसेंस दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार समाचार भारती के ईक्विटी कैपिटल में 5 लाख रुपये लगाना चाहती है। परन्तु राज्य सरकार को इस मामले में मुनासिब सलाह दी जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

खून का शुष्क रक्तरस (प्लाजामा)

754. श्री बसुमतारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित अणु ऊर्जा संस्थान खून से शुष्क रक्तरस तैयार करने के लिए छः रक्तरस (प्लाज्मा) एकक बना रहा है; और

(ख) उन एककों में काम आरम्भ होने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पहला एकक लगभग बन कर तैयार हो गया है। आशा है दूसरा एकक इस वर्ष के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगा। अतः स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चुने गये स्थानों पर दोनों एकक जनवरी, 1967 तक चालू हो जाने चाहिये। आशा है कि तत्पश्चात् प्रत्येक तीन महीनों में एक के हिसाब से शेष चार एकक दे दिये जायेंगे।

फगवाड़ा में हुए दंगे में प्रयुक्त प्लास्टिक बम

755. श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अक्तूबर, 1966 को फगवाड़ा (पंजाब) में हुए दंगे में, जिसमें कुछ मजदूर नेता मारे गये थे, प्रयुक्त हुआ प्लास्टिक बम किसी भारतीय आयुध कारखाने में बना हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच पड़ताल की है कि वह बम उस कारखाने के बाहर कैसे लाया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इस प्रकार का बम भारी आयुध कारखानों में तैयार नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कोसीपुर तोप तथा गोला कारखाना

757. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित कोसीपुर तोप तथा गोला कारखाने के ट्रेक्टर अनुभाग को बन्द कर दिया गया है या किया जा रहा है या उसको घटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ट्रैक्टर निर्माण का सब कार्य किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). गन और शैल फैक्टरी कोसीपुर में ट्रैक्टरों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य भारत अर्थ पूर्वज लि० बंगलौर में स्थानान्तरित होने की क्रिया में है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन राजकीय क्षेत्र का एक उपक्रम है। इस से कोसीपुर की फैक्टरी हथियारों के निर्माण पर पूरा ध्यान दे सकेगी।

(ग) जी नहीं।

त्रिराष्ट्रीय सम्मेलन पर व्यय

758. **श्री प० ह० भोल**
श्री कपूर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, राष्ट्रपति नासर और राष्ट्रपति टीटो के बीच नई दिल्ली में हाल ही में हुए त्रिराष्ट्रीय सम्मेलन पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति भवन के सम्मेलन कक्ष में माइक्रोफोन और अन्यीध्वनि और बिजली का प्रबन्ध एक गैर-सरकारी पक्ष को दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस की शर्तों का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार अभी तक यह सूचना देने की स्थिति में नहीं है। व्यौरेवार बिल आदि आजाने पर ही ठीक-ठीक खर्च का हिसाब लगाया जा सकता है।

(ख) और (ग). राष्ट्रपति भवन के अशोक कक्ष में (जहां त्रिपक्षीय बैठक का प्रारंभिक अधिवेशन हुआ था) केवल सार्वजनिक भाषण व्यवस्था के प्रतिष्ठापन का काम ही एक प्राइवेट कार्य को 75.00 रु० एक यूनिट प्रतिमद प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया था।

एयरमैनों की भरती

759. **श्री गुलशन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 22 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2935 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में एयरमैन, तकनीकी तथा गैर तकनीकी वर्गों में नियुक्ति के मामले में हायर सैकेण्ड्री भाग एक को मैट्रिक के बराबर मानने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न में अन्तर्ग्रस्त है शिक्षा-मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श ।

Documents of Rev. Michael Scott

760. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have returned the documents left behind in India by Rev. Michael Scott on a request received from him to this effect; and

(b) if so, when and why ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र

761. **श्री हु० च० लिंग रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में विद्यमान प्रसारण केन्द्रों की संख्या तथा नाम क्या हैं :

(ख) श्रोताओं और विशेषकर ग्रामीण किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर में किन-किन स्थानों पर प्रसारण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, और उनकी स्थापना की स्थिति क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) मैसूर में चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आजकल मैसूर राज्य में आकाशवाणी के दो केन्द्र हैं :—एक बंगलौर में तथा दूसरा धारवाड़ में । इसके अतिरिक्त भद्रावती में एक सहायक केन्द्र काम कर रहा है और दूसरा सहायक केन्द्र इस सप्ताह गुलबर्ग में चालू होने वाला है ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में धारवाड़ में लगभग 7.8 लाख रुपये की लागत से मीडियम शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर तथा श्रवण केन्द्र और भद्रावती में लगभग 15.95 लाख रुपये का एक एक सहायक केन्द्र चालू किये गये गुलबर्ग के सहायक केन्द्र का, जो चालू होने वाला है, अनुमानित खर्चा 10.71 लाख रुपये है । इन सब योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के श्रोताओं के

लिए बंगलौर तथा धारवाड़ में क्रमशः अगस्त 1962 तथा नवम्बर 1964 में विविध भारती सेवा भी आरम्भ की गई।

(ग) देश में प्रसारण के विकास के लिए चतुर्थ पंशवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

मैसूर में ग्राम्य प्रसारण

762. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में ग्राम्य प्रसारण की क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं और कितनी पंचायतों को ये सुविधायें उपलब्ध हैं और कितनी पंचायतों को नहीं; और

(ख) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के आशय से शुरू किये गये कृषि-उपज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार कितना बढ़ाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देहाती कार्यक्रम आकाशवाणी के बंगलौर, धा वाड़ और भद्रावती केन्द्रों से प्रसारित किए जा रहे थे। गुलबर्ग में एक और केन्द्र शीघ्र ही चालू होने वाला है। ये केन्द्र मैसूर राज्य के और पंचायतों के लगभग आधे भाग में प्रसारण करेंगे ।

(ख) इन केन्द्रों के प्रसारणों में कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम नियमित रूप से शामिल किए जाते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में एक फार्म एवं घरेलू प्रसारण यूनिट बंगलौर में स्थापित करने का विचार है। यह यूनिट गहन कृषि विकास कार्यक्रम वाले मंडया जिले और एक या दो अन्य गहन कृषि क्षेत्र वाले जिलों के लिए कृषि सम्बन्धी विशेष जानकारी प्रसारित करेंगे।

सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का मामला फिर से उठाने का पाकिस्तान का प्रयास

763. श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान 20 सितम्बर, 1965 के संकल्प संख्या 211 के अनुसरण के काश्मीर का मामला फिर से सुरक्षा परिषद् में उठाने कां प्रयास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) : जी हां।

(ख) कश्मीर के बारे में भारत की स्थिति संसद् और सुरक्षा पषिरद् में कई बार स्पष्ट कर दी गई है। अगर पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में इस सवाल को उठाता है, सरकार उस स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

Indian in Nepal

764. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that those Indians who had settled in Nepal for generations together are being uprooted from there under the New Land Reform Law of Nepal; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) The Government are aware of the legislation enacted by the Government of Nepal barring registration of land in the name of foreigners including Indians without prior approval of the Government of Nepal and this has created some obstacles for Indians living in Nepal.

(b) It has been pointed out to the Government of Nepal that this legislation is not in conformity with the Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950. The matter has been under correspondence with them and an *aide memoire* was sent to them in June this year. Their reply is awaited.

नागरिक अभिनन्दन समारोह में संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रगान की गलत ध्वनि का बजाया जाना

765 श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दरलाल :

क्या वैदेशिक-कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राष्ट्रपति नासर के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में पुलिस द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रगान की गलत ध्वनि बजाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि के लिए कौन उत्तरदायी है ; और

(ग) क्या ऐसी त्रुटियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। जो राष्ट्रगान बजाया गया था, वह सीरिया द्वारा संघ से अलग होने से पूर्व संयुक्त अरब गणराज्य का था।

(ख) और (ग) : म्यूनिसिपल अधिकारियों ने उस उत्सव का आयोजन किया था। यह गलती खेदजनक असावधानी के कारण हुई। इस तरह की गलतियां फिर न होने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं और यह मंत्रालय संबद्ध अधिकारियों से भविष्य में निकट समन्वय करेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के उत्तर में शुद्धि

Correction of reply to Unstarred Question No. 3616

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): 31 जुलाई, 1966 को भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर के विवश हो कर उतरने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के भाग (क) के उत्तर में, मैं ने अन्य बातों के साथ यह कहा था कि विमान चालक के अलावा हेलीकॉप्टर में तीन सेवी कर्मचारी थे।

सही स्थिति यह है कि हेलीकॉप्टर में विमान चालक समेत तीन सेवी कर्मचारी थे। मैं पहले दिये गये उत्तर में शुद्धि करता हूं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में शुद्धि

Correction of reply to Unstarred Question No. 61.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): 25-7-1966 को लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर देते हुए, मैंने एक विवरण सभा-पटल पर रखा था। उस विवरण की मंडिका 3(ग) में मैंने यह कहा था :—

"3(ग) आयुद्ध कारखाना सहकारी समिति

स्वर्गीय श्री पट्टलो आयुद्ध कारखाना सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्य थे और समिति की मृत्यु-एवं-हितकारी निधि योजना परिवार सहायता निधि के अन्तर्गत उनका परिवार इन निधियों से क्रमशः 500 रुपये तथा 150 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। कानूनी दायदता प्रमाणपत्र न होने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।"

2. इस बीच यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अग्रेतर जांच करने पर पहले दिया गया विवरण जो आयुद्ध कारखाना सहकारी समिति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था, सही नहीं पाया गया है, स्वर्गीय श्री पट्टलो आयुद्ध कारखाना सहकारी समिति, लिमिटेड, किर्की के सदस्य नहीं थे और इस लिये उनका परिवार समिति की मृत्यु-एवं-हितकारी निधि योजना तथा परिवार सहायता निधि के अन्तर्गत किसी भुगतान के लिये पात्र नहीं है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE AND MOTION FOR ADJOURNMENT (Query)

श्रीमती विमला देवी : (एलुरु): श्रीमान मैंने आंध्र प्रदेश की स्थिति के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है और मुझे बताया गया है कि यह अस्वीकृत कर दी गई है। यह अनुचित है। मुझे यह विषय उठाने की आज्ञा दी जानी चाहिये। वहां पर से सेना तथा नौ सेना बुलाई गई है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय महिला सदस्य से मेरा अनुरोध है कि सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्रीमती विमला देवी : आंध्र प्रदेश में स्थिति बहुत गम्भीर है। मैं वहां के लोगों का वहां पर प्रतिनिधित्व करती हूं। आंध्र प्रदेश के लोगों को भड़काने वाले वक्तव्य दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कहेंगी उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया।

श्रीमती विमला देवी : * * *

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप का नाम लेकर पुकारना होगा। हर बात की कोई सीमा होती है मुझे कार्यवाही करने पर बाध्य किया जा रहा है।

श्रीमती विमला देवी * * *

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया सभा भवन से बाहर चली जायें।

(इसके पश्चात् श्रीमती विमला देवी सभा भवन से बाहर चली गयीं)।

(Shrimati Vimla Devi then left the House)

Shri Rameshwaranand (Karnal): Sir, I have given notice of adjournment motion. People from all parts of our country have come outside the Parliament House (अन्तर्बाधा)

Mr. Speaker: Swamiji please sit down.

Shri Rameshwaranand: I will sit down, but you please listen to me. You should adjourn the House and meet them and assure them.... (*interruptions*)

Mr. Speaker: Have you come determined to disturb the proceedings and not to sit. Please sit down.

Shri Rameshwaranand: You please listen to me in the first instance. You will have to listen. I will not go out.

Shri Madhu Limaye: It is correct. Members have got a right to speak here.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Sir, you have made it a point that you will not allow any notice. Is there any pressure on you from Government. We have been giving notices regularly but you have not allowing them (*interruptions*).

Mr. Speaker: Government has made a statement day before yesterday.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: That statement is useless.

Shri Rameshwaranand: Sir, the demand for ban on cow slaughter is a democratic demand.

Mr. Speaker: I am not going to yield. You please go out. (अन्तर्बाधा)

Shri Rameshwaranand: Why do you not listen to me.

Mr. Speaker: That is not the way.

**Not recorded.

**कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

Mr. Speaker: I name Shri Rameshwaranand, a member of this House. He is indulging in disorderly conduct. (अन्तर्बाधाएं)

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य स्वामी रामेश्वरानन्द को जिन्हें अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker, I request that House should be adjourned so we could listen to the demand of lakhs of people who have gathered outside.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य स्वामी रामेश्वरानन्द को जिन्हे अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

श्री रंगा (चित्तूर): श्रीमान् मैं आप की स्थिति को जानता हूं परन्तु सभा के नेता के प्रस्ताव को मैं ठीक नहीं समझता। आप सदन से कह सकते हैं कि सदस्य को एक दिन या दो दिनों के लिये निलम्बित किया जाये परन्तु पूरे सत्र के लिये क्या ऐसा करना ठीक है ? इस प्रकार का प्रस्ताव उचित नहीं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मैं चाहता था कि स्वामी जी चुप हो जाते। किन्तु एक सदस्य को इतने अधिक समय के लिये निलम्बित करना उचित नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : दण्ड तो अपराध की गम्भीरता के अनुसार होना चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिंह : यदि आप चाहें तो अवधि कम कर सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि इस सभा के सदस्य स्वामी रामेश्वरानन्द को जिन्हें अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है, दस दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य स्वामी रामेश्वरानन्द को जिन्हे अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है, दस दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

Lok Sabha divided.

पक्ष में 171 : **विपक्ष में 31**

Ayes 171: Noes 31.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Mr. Speaker: I request Swamiji to go out as the House has decided just now.

Shri Rameshwaranand: Sir, I have great regard for you and the House, but I want that I may be given an opportunity to say a few words.

Mr. Speaker: No question of discussion now.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मुझे खेद है कि श्री रामेश्वरानन्द बाहर नहीं गये (मैं भी बाहर जा रहा हूं)।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The House should be adjourned for 10 or 15 minutes.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा 12 बज कर 52 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Fifty two minutes past Twelve of the Clock.

लोक सभा 12 बजकर 50 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at 12.50 hrs.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री की सभा सचिव (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 7224/66]

चल चित्र वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7225/66]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत चलचित्र, वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) वर्ष 1963-64 और 1964-65 के लिए चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7226/66]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA) 1966-67

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं वर्ष 1966-67 के लिये केरल राज्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगे दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1966-67

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं 1966-67 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: COMMONWEALTH PRIME MINISTER'S CONFERENCE

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आपकी अनुमति से मैं इस वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7227/66] मैं

नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव के बारे में —जारी

RE: MOTION UNDER RULE 388—*contd.*

संसदीय तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं चाहता हूं कि इसे कल तक के लिये स्थगित किया जाये। कल तथा परसों शनिवार और इतवार की छुट्टी होने के कारण मैं परामर्श नहीं कर सका। इसलिये मैंने समय मांगा है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इसे कार्य सूची में शामिल कर लिया जाये।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANY (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :—

"कम्पनी अधिनियम, 1956 मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ORDINANCE

कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1966

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): मैं कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1966 द्वारा परन्तु विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7228/66]**

मेटल कार्पोरेशन आंफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक

METAL CORPORATION OF INDIA (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राजस्थान राज्य के जवार क्षेत्र में और उसके आसपास जस्ते और सीसे के निक्षेपों का लोकहित में पूर्ण संभव विस्तार तक सदुपयोजन करने तथा उन खनिजों

का ऐसी रीति से उपयोग, जिससे सामान्य भलाई हो, करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से दी मेटल कारपोरेशन ग्रॉफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के ग्रर्जन के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को उपस्थापति करने की ग्रनुमति दी जाये।"

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राजस्थान राज्य के जवार क्षेत्र में ग्रौर उसके ग्रासपास जस्ते ग्रौर सीसे के निक्षेपों का लोकहित में पूर्ण संभव विस्तार तक समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग, जिससे सामान्य भलाई हो, करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से दी मैटल कारपोरेशन ग्रॉफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के ग्रर्जन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The motion was adopted.

श्री सु० कु० डे० मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

ग्रध्यादेश के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING ORDINANCE

मैटल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया (उपक्रम का ग्रर्जन) ग्रध्यादेश, 1966

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : मैं मेटल कारपोरेशन ग्रॉफ इंडिया (उपक्रम का ग्रर्जन) ग्रध्यादेश, 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 71(1) के ग्रन्तर्गत सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय म रखी गई । देखिये संख्या एल० डी० 7229/66]**

कोयला वाले क्षेत्र (ग्रर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक
COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : मैं प्रस्ताव करता कि कोयला वाले क्षेत्र (ग्रर्जन तथा विकास) ग्रधिनियम, 1957 में ग्रागे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कोयला वाले क्षेत्र (ग्रर्जन तथा विकास) ग्रधिनियम, 1957 में ग्रागे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The motion was adopted.

श्री सु० कु० डे० : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :—

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा 3 नवम्बर, 1966 को रखे गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि यह सभा मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है"।

श्री स्वैल (आसामस्वायत शासी जिले) : मंत्री लोग कहते हैं कि सदन के इस ओर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। अतः वे सरकार की बागडोर किसी को नहीं दे सकते हैं।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*}

हमारी सरकार ने देश को अत्यन्त शोचनीय स्थिति में खड़ा कर दिया है। 19 वर्षों से सत्ता कांग्रेस के हाथ में है।

आपने रुपये का अवमूल्यन करके देश का अवमूल्यन कर दिया है। और फिर भी निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। यदि आपने अपने संसाधनों का सही उपयोग किया होता तो आप विदेशी सहायता के बिना भी काम चला सकते थे। कांग्रेस ने अपने 19 वर्ष के अखण्ड शासन में मामलों को बुरी तरह उलझा दिया है। उसके 15 वर्षों के आयोजन और विनियोजन के कारण देश भीषण अकाल की स्थिति में पहुंच गया है। अब हालत यह हो गई है कि आपके पुलिस वाले भी आपके विरुद्ध नारे लगा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपको एक अच्छा अवसर मिला था। चीन की अपेक्षा आपकी स्थिति अधिक अच्छी थी और मित्रता, मार्ग दर्शन तथा प्रेरणा के लिये पूरे एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्र हमारी ओर देख रहे थे। परन्तु आज हम विश्व में उपहास-पात्र बन कर रह गये हैं।

सरकार विरोधी दलों पर यह आरोप नहीं लगा सकती है कि वे ही इस समय देश की सभी कठिनाइयों के लिये उत्तरदायी हैं। अब जबकि अधिकांश जनता का सरकार पर विश्वास उठ गया है फिर भी सरकार उलझन और निराशा पैदा करती जा रही है। सरकार नैतिक पतन से पीड़ित है। उसमें अपने उत्तरदायित्व के प्रति सम्मान नहीं है। मंत्रीगण यहां उपस्थित न रह कर भारत की जनता का अपमान करते हैं उनकी अपनी इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिये।

नागा समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। इस विषय पर कई बार बातचीत भी हुई है परन्तु हम केवल गतिरोध की ओर ही जा रहे हैं। मिजो विद्रोह ने भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। आसाम के पहाड़ी लोगों के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई गई है। यदि भारत सरकार इस विषय पर अभी भी सोती रही और तुरन्त कोई कड़ी कार्यवाही न की गई तो सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र के लोग सरकार के विरुद्ध भड़क उठेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग कई वर्षों से सरकार से राजनीतिक मान्यता अर्थात्

अपना एक राज्य प्राप्त कर के भारतीय समाज में एक समान स्थान दिये जाने की मांग करते रहे हैं। इसके लिये उचित कारण भी हैं ; किन्तु सरकार ने इस विषय में टालमटोल की है। यदि वहां कोई अवांछनीय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी।

Mr. Deputy Speaker: Shri Raghunath Singh:

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, I want to raise a point of order under rule 376. It has been the convention of this House that when discussion on a no-confidence motion is going on, the Chair calls only those members to speak on behalf of different groups, whose names have been sent to the Chair by the leaders of the respective groups. So far as this no-confidence motion is concerned the leader of our group Shri Bagri had sent a chief to the chair on the 3rd instant stating that Shri Madhu Limaye would speak on behalf of our groups on the 4th instant. But Shri Yashpal Singh was called to speak and it was argued that as a member of their group had already spoken, Shri Madhu Limaye had not been given time. On the contrary Shri Swell a member of another group was allowed to speak. So I want to know why this discrimination is made with our group?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Why are they afraid of my speach so much?

An hon. Member: Who is afraid?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने कल इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाया था और मैंने विनिर्णय दिया था कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री यशपाल सिंह ने, जो कि उनके दल के सदस्य हैं लगभग पूरा समय ले लिया है। अतः मैं इनके दल को और अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमारे दल के लिये जो समय नियत किया गया है उस में से उनको 10 मिनट दे दिये जायें।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Sir, the opposition parties have brought the no-confidence motion for the third time during the brief tenure of 292 days of the present Prime Minister. I am sorry to say that the opposition parties have not discharged their duties properly. They should have given enough time to the Prime Minister to take stock of the situation and set the matters right. The opposition parties are doing the greatest disservice to the nation by wasting the precious time of the House.

The opposition parties have been harping on the drought conditions prevailing in the country and criticising the Government; but they have not given any concrete suggestions to solve the problems. By rousing the people to acts of violence, they are simply damaging the image of the country.

The opposition parties fail to realise that the situation which they are trying to create will only create lawlessness in the country. This ring the death knell of democracy and it will take its fold all including the opposition parties. They are converting democracy into mobocracy which will bring in its wake the dictatorship as is evident from the history of countries like Italy, France, and Germany.

It is important that our rural population have refused to be swayed and misled by the empty slogans of the opposition parties, because they comprehend the dangers involved in following them.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): During all the General Elections Congress has been saying to the Mohammedans that Congress is the only organisation that can safeguard their interests. On the contrary Congress has commi ted innumerable atrocities upon the Mohammedans. For example, in Rajasthan Mohammedans were forced to leave for Pakistan without giving them the permission to take their belongings with them.

Large scale misappropriations have been made in the name of export promotion. The result of all this campaign has been that enormous amount of foreign exchange has been wasted away and the country has gone into liquidation on account of which the rupee has been devalued. As a matter of fact this plan has been formulated for the benefit of the industrialists and it is only for their benefit that it has been modified from time to time. There has been tremendous misuse of licences especially in the field of textiles. To cite an example M/s. Madhuban Das Goverdhan Das has defalcated in licences worth crores of rupees and still that firm has not been prosecuted. The reason for this is that that firm has got the protection and support of the Commerce Minister. Commerce Secretary and the Controller of Imports and Exports. All these persons should be seeked forthwith and the affairs of this firm as also of its associate firm M/s. Universal Exporters and Importers should be investigated. Unless the Prime Minister dismisses the Commerce Minister from the Council of Ministers nobody will have confidence in this Government. Today I am supporting this no-confidence motion because**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सूचना देनी चाहिए ।

Shri Madhu Limaye: I have given notice.

श्री त्यागी : मुझे आश्चर्य है कि मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है यदि आप उसको समझ पाये हैं ***

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री मधु लिमये नहीं बैठेंगे तो मुझे उन्हें बाहर चले जाने को कहना होगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I want to place the papers before the Government.

श्री मुहम्मद कोया (कोझीकोड) : औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करने का तो हमें अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई औचित्य प्रश्न सुनने को तैयार नहीं ।

श्री त्यागी (देहरादून) : ये लोग पटल पर कुछ पत्र रखना चाहते हैं, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती * * *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं, बैठ जाइये ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): There is lathi charge and firing outside. I have also received lathi blow. You cannot go on like this.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सभा का कार्य नहीं चल सकता है। श्री कछवाय कृपा करके बाहर चले जायें आखिर सभा में तो शांति रखी ही जानी चाहिए।

[इसके पश्चात् श्री कछवाय सभा से बाहर चल गये]
[**Shri Kachhavaiya then left the House.**]

श्री राजाराम (कृष्णागिरि): मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 1962 में हमने कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए आन्दोलन किया था। हमने इस बारे में जो सलाह दी थी सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकार करदाताओं के माल को बहुत बुरी तरह खर्च करती रही है और मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही शोचनीय बना दी गई है। इसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, परन्तु सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया और कीमतें निरन्तर बढ़ती चली गयीं। अब बिना किसी विचार के रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया और अब सरकार स्वयं ही खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ा रही है। मेरा मत यह है कि यदि सरकार को हमनें इसी तरह छूट दिये रखी तो शीघ्र ही देश में बड़ी भयंकर स्थिति का निर्माण हो जायेगा। सरकार को कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए तुरन्त पग उठाने ही होंगे। यह भी कहा गया है कि हम 800 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। चाय, पटसन और रूई की चीजें लगभग 400 करोड़ रुपये की निर्यात की जाती हैं। अब हमारा निर्यात व्यापार भी खतरे में है। इस बारे में स्थिति यह है कि जब रुपये का अवमूल्यन हुआ था तो उस समय यह कहा गया था कि इस तरह हम और अधिक विदेशी मुद्रा कमा लेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा निर्यात संकट में है। इस तरह यह आशा करना भी गलत होगा कि लोग सरकार पर विश्वास रखते हैं।

मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि सेलम के लिए कई वर्षों से एक इस्पात के कारखाने की मांग की जा रही है परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में केवल एक अस्पष्ट आश्वासन देने के अतिरिक्त कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। आश्चर्य की बात है कि संयन्त्र के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तो तैयार रखा है परन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। बोकारो कारखाने के लिए सरकार 900 करोड़ रुपये देने को तैयार है परन्तु दक्षिण में एक संयन्त्र लगाने के लिए सरकार केवल 300 करोड़ भी व्यय नहीं करना चाहती। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दक्षिण के विरुद्ध कोई षड्यन्त्र चल रहा है।

अब यह नारा लगाया जा रहा है कि 'एक दल, एक झंडा और एक नेता'। मैं अपने विशिष्ट बन्धुओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए बलिदान किये थे कि हम इस देश में तानाशाही की स्थापना करें। मेरा विचार यह है कि यदि यह नारा सफल हो गया तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। योजना भी हमारी प्रायः असफल हो रही है। पर इस पर भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सम्मेलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी यह कहती है कि गैर कांग्रेसी सरकार को क्रांति से उखाड़ फेंका जायेगा। क्या ऐसा लोकतंत्र संसार भर में हमने कभी देखा है। शक्ति और गोली के बल से ये लोग अपनी सत्ता कायम रखेंगे। (अंतर्बाधा)**

प्रधान मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस विवाद के दौरान कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो पहले कभी न सुनी गयी हो अथवा न कही गई हो। यद्यपि विरोधी पक्ष की अलग अलग राय हैं परन्तु फिर उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त

** कार्यवाही से निकाल दिया गया।
Not recorded.

करने का अवसर दिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। आज जो हिंसा का वातावरण बना हुआ है, उस पर मुझे बहुत ही क्षोभ है। जो कुछ बाहर हो रहा है, वह आपके सामने है। चाहे यह विद्यार्थी लोग कर रहे हों, अथवा अन्य लोग। मैं यह महसूस करती हूं कि हिंसा को जान बूझ कर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में हिंसात्मक कार्य किये जायें और हम शक्ति का प्रयोग करें। परन्तु क्या किया जाय जब सरकारी इमारतों को जलाया जाय और विविध प्रकार से कानून तोड़ा जाय तो फिर क्या किया जाये। शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है।

आज देश की स्थिति ऐसी नहीं कि हम छोटी-छोटी चीजों के लिए लड़ते रहें। छोटे-छोटे दलगत मामलों पर उलझते रहें। आज तो हमें राष्ट्र के हित में कदम मिला कर चलना होगा। जो शिकायतें हैं उन्हें सुनने से हमें कभी आपत्ति नहीं हुई। यदि शिकायतों को ठीक तरह से प्रस्तुत किया जाय तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। मेरा मत यह है कि राज्यों को शिकायतों को प्रकट करने के ढंग का विरोध जरूरी करना होगा, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते, तो अन्य साधन अपनाने पड़ेंगे। वह तरीका और भी अधिक खतरनाक होगा और उसके लिए कहीं अधिक कीमत चुकानी होगी। इस बारे में दुःख की बात यह है कि विद्यार्थी भी यह नहीं जानते कि उनकी मांग क्या है।

जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जो कुछ बाहर हो रहा है यह सरकार पर ही आक्रमण नहीं है। यह तो हमारी जीवन पद्धति, मान्यताओं और विचारधारा को समाप्त करने का भी प्रयास है। हम अपने विचारों पर दृढ़ हैं। हमारा अहिंसा के सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास है चाहे कोई इसका उपहास ही क्यों न करे। हमनें क्योंकि अहिंसा के रास्ते को ही ठीक समझा इसलिए दृढ़ता से उस पर चलते रहे। उसमें हमें सफलता भी मिली है। फिर यह भी बात है कि हमनें इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम भी विरोधी पक्ष को पूरी प्रतिष्ठा देने को तैयार हैं, परन्तु मेरा निवेदन है कि कई बार विरोधी दलों के सदस्य अवसरों का अनुचित लाभ उठाते है, और आज जो कुछ बाहर हुआ है, यह इसका एक उदाहरण है। आज जो कुछ किया जा रहा है यह लोकतंत्र को समाप्त करने वाली बातें हैं। मेरा पक्का विचार है कि यदि सरकार स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला नहीं करती है, तो लोकतंत्र नहीं चल सकता।

देश के समक्ष बहुत कठिनाइयां हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेटों को बहुत कठिन परीक्षा से निकलना पड़ रहा है। यदि वे तुरन्त कुछ नहीं करते तब भी शिकायतें होती है और यदि वह कड़ी कार्यवाही करते है तो तब भी कोलाहल होने लगता है। ठीक है यदि शक्ति का प्रयोग होगा तो कई मासूम व्यक्तियों को भी हानि उठानी होगी। मुझे इसका दुःख है और ऐसे लोगों से मुझे पूरी सहानुभूति है और उनकी सहायता भी करनी चाहिए। परन्तु स्थिति का मुकाबला तो मजबूती से करना ही होता है। जो भी कठिनाइयां हैं, मेरा मत यह है कि हमें स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक होना चाहिए और सामूहिक प्रयत्न करने चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि देश के कुछ भागों में सूखे की भयंकर स्थिति है और आज यह संकट बड़े गम्भीर रूप में हमारे सामने हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बड़े प्रयत्न कर रही हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने

[श्री राजा राम]

एक सर्वदलीय समिति का गठन किया है जो सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों में सहयोग प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमें हर स्तर पर तेजी से कार्य करना है तथा जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई उन क्षेत्रों में अनाज इत्यादि भेजा जाय। हमें ऐसा भी करना होगा कि जो कुछ हमारे पास है उसका ठीक तरह से वितरण हो जाय। हमें इस तरह के आन्दोलनों की व्यवस्था करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों को अपेक्षित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुयें दी जा सकें।

मेरा अब भी यह मत है कि स्थिति जैसी भी हो पर उसे ठोस कदम जठा कर बदला जा सकता है। उत्पादन के लिए स्थायी साधन निर्माण किये जा सकते हैं। सहायता कार्य को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कृषि उत्पादन बढ़े और वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके। निर्माण कार्य को भी काफी प्लाभदायक ढंग से संगठित करना होगा। इसे बढ़ाना भी होगा। मुझे आशा है कि बच्चों के अन्नपोषण के कार्य को भी शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें वास्तव में गरीबी से लड़ना है। खाद्य समस्या भी इस गरीबी की समस्या का एक अंग है। हम अपनी योजनाओं के माध्यम से उसका सामना कर रहे है। हो सकता है कि मैं अपनी चौथी योजना के लिए पर्याप्त सहायता न मिले, फिर भी हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिएं।

इस बात को भी समुचित रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए कि जहां तक इस्पात संयन्त्रों तथा अन्य उद्योगों के स्थानों का सम्बन्ध है हम सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखना चाहते हैं परन्तु इस समय हमें सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इस समय इस्पात संयन्त्रों की बात करना बहुत ही अव्यवहारिक बात है। अभी तुरन्त उन्हें स्थापित कर देने का तो प्रश्न ही नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम जनता की भावनाओं को ठुकरा रहे हैं। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भूख हड़तालें और प्रदर्शन करके सरकार को कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और न सरकार होगी ही।

बहुत से माननीय सदस्यों ने विदेश नीति पर आलोचना की है। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष तौर पर उल्लेख किया है। मेरा निवेदन यह है कि हमें इस सम्मेलन का उपहास नहीं करना चाहिए। सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, यद्यपि उसका निश्चित परिणाम कुछ समय बाद सामने आयेगा। जहां तक इस अविश्वास प्रस्ताव का का सम्बन्ध है इसके लिए अवास्तविक वातावरण पाया जाता है। थोड़ी ही समय में हमारी परीक्षा होने वाली है। हमें जनता की राय जानने के लिए उसके सामने जाना है। मुझे इस बात का विश्वास है कि अन्तिम विजय हमारी होगी, लोग हमें पुनः अपना विश्वास प्रदान करेंगे। यद्यपि समय बड़ा कठिन है तथापि हमें लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तो बनाये ही रखनी है।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): I have gone out of the House but my faith in democracy has urged me to come back. We are sitting here, but outside, there is firing going on. If we allow such thing to happen in a democratic set up, then the future of democracy is very dark. Only a Judicial probe can tell us, who is at fault. But Government will have to put an enquiry for that. We should try to act up to the standards of democracy and should not lower down our pedestal.

As there was no opposition member yesterday in the House, the Food Minister continued speaking for about fifty minutes for the first time and ultimately admitted the difficulties put forward by us. People are dying and starving. What we wanted to say was said by him. So what should we say now in connection with this no-confidence motion. Shri S. K. Patil also did his best. But I am sorry to note that the points raised by me while moving the motion have not been satisfactorily answered. I feel the Government have no answer to the charges which have been made against them. Nothing has been said regarding eradication of corruption from the country. It is also a fact that Government have been using the administrative machinery for election purposes. This is a thing which is not done anywhere in the world.

Government have admitted my point that the corruption is rampant and it is not possible for them to eradicate it. At the time of devaluation, it was stated that this is going to help us in our exports. But in the long run it has proved quite contrary. Government are not doing anything to promote exports. This is clear from the fact that unnecessary delay is being done in framing the scheme of the export of art silk. Government have developed a mentality that nothing is done without an agitation. People have developed the agitational approach due to that. I hope that inquiry should be held with regard to the incidents which have taken place today outside the Parliament House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha divided.

पक्ष में 36; **विपक्ष में** 235

Ayes; 36 Noes 235.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

Motion was negatived

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE.* PROCLAMATION IN RELATION TO STATE OF KERALA.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : मैं श्री नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1966 से छः मास की अग्रेतर अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करती है ।"

मैं एक बार पुनः उन हालातों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं जिनके कारण यह उद्घोषणा करनी पड़ी । जिन परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ा वह बिल्कुल स्पष्ट है । यह समझा

[श्री हाथी]

गया था कि यदि इस प्रकार की उद्घोषणा न की गई तो चुनाव करवाने होंगे और यह चुनाव, यदि बड़ी शीघ्रता भी की गई तो जनवरी से पहले नहीं हो सकेंगे। ऐसा करना न ठीक ही है, न उपयुक्त ही। इसे व्यवहारिक भी नहीं कहा जा सकता। जब फरवरी में सामान्य चुनाव हो रहे हैं तो जनवरी में इन चुनावों को कर ने की कोई तुक नहीं है। अतः सारे हालात का अनुमान लेकर यही उचित समझा गया कि उद्घोषणा की अवधि को छः मास के लिए और बढ़ा दिया जाय। मैं यह आशा करता हूं कि आने वाले आम चुनावों के बाद केरल में लोकप्रिय मंत्रिमंडल स्थापित हो जायेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केरल की बहुत सी समस्यायें हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत सरकार ने इन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया है। परन्तु यह बात ठीक है कि इससे लोगों को पूरा सन्तोष नहीं हो सकता। यह इच्छा स्वाभाविक ही है कि वहां उनके प्रतिनिधियों की सरकार होनी चाहिए। भारत सरकार को इस बात से प्रसन्नता होगी कि 1967 में सामान्य चुनावों के बाद यथाशीघ्र एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं मंत्री महोदय के इस संकल्प का समर्थन करता हूं। परन्तु 24 मार्च, 1965 की प्रारम्भिक उद्घोषणा को जारी करने के उद्देश्य अथवा कारणों से मेरी सहमति नहीं है। गत अन्तरिम चुनावों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अन्य दल भी इस स्थिति में नहीं थे कि संविधान के अन्तर्गत मंत्रिमंडल बना सकें। सरकार बनना असम्भव हो गया था। परन्तु हमारे दल के प्रवक्ता का विचार यह नहीं था। उनका मत था कि संविधान के अनुच्छेद 356(1) का गलत अर्थ लगाया गया है। वहां के राज्यपाल की यह रिपोर्ट कि वहां कोई सरकार बन ही नहीं सकती, गलत थी। और इस प्रक्रिया पर भी आपत्ति की जा सकती है। यह तर्क भी सारहीन था कि केरल राज्य की विधान सभा में चुने हुए दल संवैधानिक सरकार बनाना नहीं चाहते। इस बात का प्रतिवाद सभी दलों ने किया है।

अब हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे दल की यह नीति है कि भारत में विधान मंडलों के निष्पक्ष चुनाव करने के लिए सत्तारूढ़ दल को चुनावों से कम से कम 3 महीने पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए और इसके समर्थन से यह नीति पूरी होती है। मेरा विचार यह भी है कि ऐसा करने से केरल राज्य में निष्पक्ष चुनाव सम्भव हो सकेंगे।

इसके साथ ही मैं कुछ पंजाब और हरियाना के दो नये राज्यों के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं इन दो राज्यों में अनुचित जल्दबाजी में मंत्रिमंडल बनाये जाने की निन्दा करता हूं। यह अच्छा था कि इन राज्यों में मंत्रिमंडल न बनाये जाते ताकि केरल की तरह यहां भी निष्पक्ष चुनाव सम्भव हो सकते। मेरे विचार में अब वहां चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे।

श्री केप्पन (मवातुपुजा) : चुनाव फरवरी में होने जा रहे हैं, इस तथ्य को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इस संकल्प का विरोध नहीं करेगा। परन्तु एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि राष्ट्रपति के शासन को वहां कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कई दिशाओं में तो वह शासन नितान्त असफल रहा है। जो समस्या केरल राज्य के समक्ष सितम्बर, 1964 में थीं आज वे सभी विकराल रूप में आज भी विद्यमान हैं और नई नई समस्यायें और उभर आई हैं। आज वहां चावल 55 रुपये से 125 रुपये तक बिक रहा है। यह उस भ्रष्टाचार का एक रूप है जो कि राष्ट्रपति राज्य के काल में केरल में निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी की समस्या

पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो गई है। यह कितने खेद और आश्चर्य की बात है कि 400 से अधिक इंजीनियर स्नातक तीन वर्षों से बेरोजगार घूम रहे हैं।

[श्री पी. वेंकटसुब्बया पीठासीन हुए]

Shri P. Venkatasubbiah in the Chair

अब हम चौथी योजना का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और केरल राज्य के लिए चौथी योजना के दौरान एक अग्रिम परियोजना बनाई जा सकती है। इसके लिए जो 23,000 करोड़ रुपये की धन राशि रखी जा रही है, यदि इससे 1000 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया जाय तो राज्य की समस्या हल हो सकती है। यह ऐसी मांग है जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यह अनुचित मांग नहीं की जा सकती। रबड़ आयात करने के कारण राज्य में रबड़ के दाम काफी गिर गये हैं। इसके परिणामस्वरूप छोटे-छोटे रबड़ उत्पादकों की आय पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्हें ठीक मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आयातित रबड़ का भुगतान कर रही है।

60,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि रबड़ का उत्पादन करते हैं। उनको भारी हानि हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने काली मिर्च पर भी 1.50 रुपये का निर्यात-शुल्क लगा दिया है। परन्तु लाल मिर्च पर कोई कर नहीं लगाया गया। अधिक आय तो लाल मिर्च से ही होती है। मेरा विचार तो यह है कि काली मिर्च पर से निर्यात-शुल्क हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से गरीब उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सकेगा। काली मिर्च के द्वारा काफी मात्रा में विदेशी विनिमय कमाया जा सकता है। इसी प्रकार आयातित गरी से राज्य व्यापार निगम को काफी लाभ होता है। सरकार इसकी ओर तो ध्यान देती नहीं परन्तु व्यापारियों पर यह आरोप अवश्य लगाती है कि वे ऊंचे लाभ कमाते हैं। इस बारे में मेरा आग्रह यह है कि मिल वालों को गरी उचित भावों पर दी जाय ताकि वे लोग भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकें।

तीन पंच वर्षीय योजनाओं के होते हुए भी केरल में कुछ भी नहीं हुआ है। इस अवधि में केरल में अपेक्षित निवेष नहीं किया गया। अतः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह कमी चौथी योजना में पूरी की जाय। और चौथी योजना के अन्तर्गत केरल द्वारा जो राशि मांगी गई है, वह उसे दे दी जानी चाहिए। उसका प्रारूप तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। केरल में रेलों की भी काफी गुंजाइश है। क्विलोन तथा अर्नाकुलम के बीच एक तटीय रेलवे लाइन की नितान्त आवश्यकता है। अर्नाकुलम–कोट्टयम–त्रावनकोर लाइन को जो इस समय छोटी लाइन है, बड़ी लाइन बनाया जाना चाहिए। इस बात को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि कृषि उत्पादन के लिए मंडी भी तलाश की जा सके। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कोचीन जो कि एक उपेक्षित पत्तन की हालत को पहुंच चुका है, के विकास के लिए कदम उठाये जायें। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता को आयेगी और जो कुछ भी इस दिशा में अपेक्षित है, उसकी व्यवस्था करेगी।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : गृह-कार्य मंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन विरोधी पक्ष की ओर से भी किया गया है। परन्तु इसके साथ ही यह बात भी बताई गई है कि राष्ट्रपति के शासनकाल में राज्य में स्थिति क्या रही है और क्या होता रहा है। मैं विस्तार में इस बात की ओर नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में उपयुक्त पग उठायेगी। आज केरल का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई नहीं है, इस लिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस बारे में सहृदयता से ही काम ले। यह उनका कर्तव्य है कि केरल का हक उसे दे और उसे आज की दल दल की स्थिति से बाहर निकाले।

[श्री मणिरंगाडन]

आज केरल में लोकप्रिय सरकार नहीं है। पिछली तीन योजनाओं में कहा तो यह गया था कि क्षेत्रीय विषमतायें दूर होंगी पर व्यवहारिक रूप में वे बढ़ गई हैं। गृह-कार्य मंत्री का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वह केरल की ओर ध्यान दें और धनराशि के आवंटन के बारे में केरल के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कहा गया था कि राष्ट्रपति के शासनकाल में बहुत कुछ किया गया है। यह देख कर दुःख होता है कि केरल प्रशासन के सभी भागों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और मेरा आग्रह यह है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खेद की बात है कि केरल के वन क्षेत्रों में बसने वालों के मामले में, बसने वालों के प्रश्न को हल करने के लिए एक जांच समिति की स्थापना की गई थी। सलाहकार समिति ने इस समिति की रिपोर्ट को एकमत से स्वीकार कर लिया था। परन्तु इस रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया। सारे राज्य भर में सर्वत्र यह आवाज उठाई जा रही है कि इस रिपोर्ट को तुरन्त कार्यान्वित किया जाय।

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का भी आन्दोलन हो रहा है। गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापक काफी अर्से से यह मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन क्रमों को ठीक किया जाय। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बारे में वक्तव्य भी दिया है, परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः 7 तारीख से वे लोग हड़ताल कर रहे हैं। पता नहीं कोई समझौता हुआ है कि नहीं, यदि हुआ है तो यह अच्छी बात है। अध्यापकों की मांगों की ओर सरकार को ध्यान देना ही चाहिए।

खाद्य स्थिति के बारे में देश भर में जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, वे बहुत ही खेदजनक हैं। भारत के विभिन्न भागों और विशेष रूप में बिहार से सूखे की खबरें बहुत ही परेशान करने वाली हैं। केरल के लोग इस राष्ट्रीय विपत्ति में उनका पूरा साथ देने को तैयार हैं। पर हमारी मांग यह है कि हमें भी उन वस्तुओं में हिस्सा मिलना चाहिए जो कि इस देश में पैदा होती हैं। जो कुछ भी इस देश में है उसका समान वितरण सारे देश में होना चाहिए। केरल में साथ लगते राज्यों में चावल का भाव बहुत कम है, परन्तु केरल में चावल का भाव बहुत अधिक है। यह स्थिति दूर की जानी चाहिए। बस इतनी-सी ही हमारी मांग है जिस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

एक बात और भी है वह यह कि केरल और मैसूर के सीमा विवाद को सीमा आयोग के पास भेजा गया है। यह खेद की बात है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया है। गृह-कार्य मंत्रालय ने इस बात की छानबीन करने की कोई चिन्ता ही नहीं की। उन्होंने यह देखने का भी कष्ट नहीं किया कि यह विवाद वास्तव में है क्या ? मेरा निवेदन है कि यह अच्छा होता यदि आयोग नियुक्त करने से पूर्व उन मामलों के बारे में राज्य में सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक परामर्श कर लिया जाता। मेरा यही निवेदन है कि केरल के मामलें में गृहकार्य मंत्री को और अधिक रुचि लेनी चाहिए, चौथी योजना के अन्तर्गत केरल से अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री अ० क० गोपालन (कासर गोड़) : गत एक वर्ष से केरल में राष्ट्रपति का शासन है, और वह अभी भी चल रहा है। वहां राष्ट्रपति शासन प्रथम बार नहीं लागू हुआ कई बार लागू हो चुका है। यदि इस राज्य को इसी तरह से ही लागू रखा जाना है तो अच्छा है कि संविधान में यह संशोधन कर लिया जाये कि जहां कहीं भी कांग्रेस को सत्ता प्राप्त नहीं है, वहां राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाय। यदि ऐसा हो जाये तो तब उद्घोषणा जारी करने और उसे पास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे तो सारी स्थिति को देखते हुए यह भी आशंका है कि चुनावों के बाद भी विरोधी दल की सरकार वहां बनने नहीं दी जायेगी। पता नहीं केरल ने क्या पाप किये हैं।

भारत का वह प्रथम राज्य था जहां कि गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था। यद्यपि गत चुनावों में में विरोधी दल एक नहीं हो पाये थे परन्तु कांग्रेस पराजित ही हुई थी। विरोधी दलों को सरकार बनाने ही नहीं दी गई। केरल के साथ बहुत भंयकर भेदभाव किया गया है। एक तरफ केरल है, जहां विधान सभा बुलाई ही नहीं गई, क्योकि वहां कांग्रेस का बहुमत नहीं। दूसरी ओर पंजाब में विधान सभा तोड़ी नहीं गई क्योकि वहां कांग्रेस का बहुमत था यह भेद भाव नहीं तो और क्या है। मेरा निवेदन यह है कि अब सरकारी नौकरों में भी राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध विद्रोह होने लगा है।

मैं इतना कह सकता हूं कि केरल की जनता के सभी वर्ग जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल है, राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध हैं। कारण यह है कि इस तरह का राज्य एक नौकरशाही का स्वरूप है,जिसके विरुद्ध स्वयं कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। कुछ दो एक उच्चधिकारियों को छोड़ कर बाकी लगभग सबने वहां हड़ताल करदी है, अथवा हड़ताल का नोटिस दे दिया है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हुआ है। सर्वत्र हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही है। केरल में शांति है, परन्तु वहां सरकार शांति कायम नहीं रहने देना चाहती। मैसूर-केरल सीमा के मामले को लेकर वहां असन्तोष बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि शांति भंग हो जाने की संभावना रहती है। मेरा कहना है कि केरल में सीमा विवाद पर गड़बड़ी को रोकने का एक ही उपाय है कि नई सरकार बनने तक इस मामलें को स्थगित कर दिया जाय। सीमा आयोग को जोकि इस समस्या को सुलझायेगा। भाषायी सम्बन्धी निकटवर्ती क्षेत्र के आधार पर और गांव को ईकाई मान कर मामला तय करना चाहिए। अन्य राज्यों में भी इसी तरह किया गया है।

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में स्थिति क्या है? योजना का एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि विभिन्न क्षेत्रों की विषमता को समाप्त कर दिया जाय। जो क्षेत्र औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा पिछड़े हुए हैं उनके लिए अधिक धन निर्धारित किया जाये ताकि एक अथवा दो वर्षों में अन्य क्षेत्रों के साथ उन क्षेत्रो का भी विकास हो सके। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक पंच वर्षीय योजना के पश्चात् यह जानने के लिए कि स्थिति में कितना सुधार हुआ है,दूसरे क्षेत्रों को तुलना में उसका कितना विकास हुआ है, असमानता किस हद तक दूर हुई है, जाच की जायेगी और यदि असमानता दूर नहीं हुई तो पिछड़े क्षेत्र के लिए अधिक निर्धारित किया जायेगा। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाता तो आंन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ वह नहीं होता। परन्तु इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया। गत पन्द्रह वर्षो में केरल के लोगों को बहुत से आश्वासन दिए गये परन्तु उनमें से किसी एक को भी पूरा नहीं किया गया है। कोचीन में दूसरे जहाज-निर्माण कारखाने के लगाने के लिए समय पहले वचन दिया गया था। पहले इसके लिए 20 करोड़ रुपये रखे गये थे परन्तु कुछ चर्चा के पश्चात् इस राशि में कटौती कर दी गई। इस परियोजना को प्राथमिकता देने के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अन्य परियोजनाओं के बारे में भी यही स्थिति है। यही कारण है कि केरल अभी भी पिछड़ा हुआ है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हिंसा की घटनाएं होती हैं और एक दिन केरल में भी ऐसा होगा और सरकार तब जनता को दोषी ठहरायेगी।

केरल में इस समय जनता द्वारा निर्वाचित कोई विधान मण्डल नहीं है। इसलिए जनता द्वारा निर्वाचित विधान मण्डल गठित होने तक सरकार को चौथी योजना पर चर्चा स्थगित कर देनी चाहिये। पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में केरल की उपेक्षा की गई थी। इसलिए यदि चौथी योजना में सरकार केरल के लिए कुछ अधिक धन निर्धारित करना चाहती है तो इस बारे में सर्वदलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

[श्री अ० क० गोपालन]

केरल में मत्स्य उद्योग के विकास की बड़ी गुंजाईश है। इस हमसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे। लगभग दो लाख मछुए इस उद्योग पर निर्भर हैं। सरकार को इस उद्योग के विकास के लिए अधिक धन निर्धारित करना चाहिए ताकि हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

जहाँ तक कोचीन पत्तन का सम्बन्ध है यह भारत की अच्छी पत्तनों में से एक है। कुछ निकायों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पत्तन के सुधार के लिए पांच करोड़ से दस करोड़ रुपये न रखे गये तो यह पत्तन बेकार हो जायेगा हम लोग इसके लिये आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को चावल, कपड़े तथा सब्जी के लिये उतना ही मूल्य देना पड़ता है जितना कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को। फिर उनके भत्तों तथा वेतन आदि में भेदभाव क्यों है। दोनों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। केरल में अराजपत्रित अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। यदि सरकार इन कम आय वाले कर्मचारियों की मांगे स्वीकार न किया तो सरकार को उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। उद्योग में भी सरकार नियोजकों के समर्थन की नीति का अनुसरण कर रही है। रबड़ उद्योग में काम करने वाले श्रमिको ने 90 दिन तक हड़ताल की परन्तु सरकार ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। रबड़ के भाव बहुत अधिक हैं अतः नियोजक श्रमिकों को कुछ अधिक मजूरी दे सकते हैं। केरल परामर्शदाता समिति ने भी सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार नियोजकों का समर्थन करना चाहती है।

तिरविल्लूर काटन मिल्स में 2000 श्रमिक काम करते थे परन्तु अब वहां बिल्कुल थोड़े श्रमिक काम करते हैं। श्रमिकों से एकत्र की गई भविष्य निधि सरकार को नहीं दी गई है। 1958 में जब छंटनी की गई थी तो सरकार ने कुछ सहायता दी थी। परन्तु अब छंटनी सम्बन्धी मजूरी भी नही दी गई है। अब वहां केवल 25 अथवा 30 श्रमिक काम कर रहे हैं। उनके अभ्यावेदन के बावजद भी सरकार ने इस मिल्स को अपने हाथ में नहीं लिया है।

अवमूल्यन के कारण काजू तथा नारियल के रेशों के मूल्य बढ़ गये हैं और इस प्रकार इन उद्योगों के मालिको के लाभ में भी वृद्धि हो गई है। परन्तु जहां तक कर्मचारियों के वेतन का सम्बन्ध है इनमें वृद्धि के बजाय कमी कर दी गई है। यदि कर्मचारियों की ओर से सरकार ने समय पर हस्तक्षेप नही किया तो उसमें गड़बड़ हो जायगी। इन दो उद्योगों में लाखों श्रमिक काम करते हैं। अवमूल्यन के कारण निर्यातकों को अपने उत्पाद का अधिक मूल्य मिल रहा है, इसलिए यह उचित है कि श्रमिकों को भी कुछ अधिक वेतन दिया जाये।

केरल परामर्शदाता समिति का अभी अभी उल्लेख किया गया है। यह समिति एक प्रहसन है। इस समिति ने मणियंगाडन समिति नियुक्त की थी परन्तु इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है हालांकि परामर्शदाता समिति के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार इनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

वदवसनचेरी में वलियान्परा बा में एक आर्ट्स कालेज स्थापित करने के लिए काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। ये काश्तकार वहां पर पन्द्रह वर्ष से हैं। मैं भी उनकी ओर से कलैक्टर तथा सरकार को मिला था और उनको बताया कि पास ही एक जगह खाली पड़ी है और वहां पर आर्ट्स कालेज बनाये जाने से किसी को कोई आपत्ति नही होगी। परन्तु कुछ सुनवाई नहीं हुई और

काश्तकारों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। यदि किसानों को बेदखल करना ही है तो कम से कम कुछ उनको मुआवजा तो दिया जाना चाहिए ।

पघडापारा में कोट्टयम में एक अनुसंधान केन्द्र है। एक नियोक्त ने कहा था कि यदि इस केन्द्र को अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया जाये तो वह इसलिए हजारों एकड़ भूमि दे सकते हैं। परन्तु सरकार ने इससे इन्कार कर दिया। परन्तु वहां से इलायची के काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। ये लोग भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। यदि इन को बेदखल किया जाना है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अगले आम चुनाव में कांग्रेस को केरल में हार होगी। यदि कांग्रेस को हार होती है तो वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन होगा।

श्री मुहम्मद इस्माइल : इस समय आम चुनाव में कुछ ही महीने रहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए कहना सम्भव नहीं है। अतः सभा के समक्ष प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करना आवश्यक है। इस बारे में मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने जिन क्षेत्रों का दौरा किया है वहां की जनता की कठिनाइयों का वर्णन किया है। केरल में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। देश में वर्तमान स्थिति के लिए सरकार ही जिम्मेदार है।

जहां तक केरल में राष्ट्रपति के शासन का सम्बन्ध है, उसमें कम से कम एक लाभ की आशा की जा सकती थी। यदि वहां लोकप्रिय सरकार होती तो मंत्रियों पर इधर-उधर से बड़े प्रभाव डाले जा सकते थे जब कि राष्ट्रपति के शासन में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जहां समूचे राज्य के हित निहित हों वहां इसे निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए था। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि राज्य के कुछ भागों में इसने कुछ मामलों में निष्पक्ष रूप से कार्य किया है।

मत्स्य उद्योग केरल का सब से महत्वपूर्ण उद्योग है। लोग कुछ मुख्यालयों तथा केन्द्रों को तिरुर, तानूर तथा पोतनी में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मछली उद्योग में काम करने वाले लोग विशेष मालाबार के लोग देश में सब से गरीब लोग हैं। इन गरीब लोगों के स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार को विशेषकर राष्ट्रपति के शासन ने विशेष प्रयास करने चाहिएं ।

लोग फेरोक से नीलाटुर तक जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए वर्षों से मांग कर रहे हैं। 18 अक्तूबर को संसद् सदस्यों की एक बैठक में इस प्रश्न को उठाया गया था और सरकार से पूछा गया था कि राज्य सरकार ने केन्द्र को रेलवे के सम्बन्ध में जो कि सिफारिश की है उसमें इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अब हमें यह आश्वासन दिया गया है कि इस रेलवे लाइन को रेलवे की सूची में शामिल कर लिया जायेगा। यह तो केवल मालाबार के बारे में है परन्तु वास्तव में समस्त केरल राज्य में परिवहन तथा संचार व्यवस्था की कमी है। केरल में क्विलोन से अरनाचलम तक केवल एक ही नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। रेलवे को अधिक लाभदायक तथा युक्तियुक्त बनाने के लिये अन्य रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

[श्री मुहम्मद इस्म इल]

लगभग दो वर्ष पूर्व केरल राज्य का तकनीकी सर्वेक्षण किया गया था। उसके प्रतिवेदन में केरल राज्य में निरन्तर बहने वाली 44 नदियों से बिजली उत्पन्न करने की प्रमुख मांग की गई थी। उस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया था कि इससे न केवल केरल राज्य को बल्कि पड़ौसी राज्यों को भी लाभ होगा। पता नहीं राष्ट्रपति शासन ने इसके लिए क्या कार्यवाही की है।

कासरगोड प्रश्न के बारे में महाराष्ट्र तथा मैसूर में झगड़ा है और कांग्रेस हाई कमान इस झगड़े को सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। उस समय वहां पर राष्ट्रपति का शासन था परन्तु वह भी कुछ नहीं कर सका।

सीमावर्ती झगड़ों के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति में केरल का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इस मामले में कुछ कहने के लिए राज्य में लोकप्रिय सरकार भी नहीं है। इसलिए केरल सम्बन्धी सीमा के झगड़े को एक व्यक्ति की समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं लाया जाना चाहिए।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Atleast six times President's rule has been imposed in Kerala since the establishment of a democratic government there. Although they are the most educated people yet it has been proved that they have failed to rule themselves.

Cochin Port is beautiful, natural and is also one of the best ports in India. It is not only in the interest of Kerala but also in the interest of whole of India that this port is developed. So far as the question of silting in this port is concerned Government has already appointed a committee to see how far this can be removed.

Government is prepared to give more and more aid to the fishermen and owners of the sailing vessels so that they could install diesel engines in their boats but the people of Malabar are not taking the advantage from this offer.

We certainly want that a railway line from Trivandrum to Cape Comourine should be laid.

Timber of Kerala can be used for construction of anti-mines sweepers. Research should be conducted in this regard.

So far as the question of establishing a second shipyard in Cochin is concerned the total required land has not been acquisitioned. I hope that Government will take a quick decision in this regard as this matter is pending for a long time and also we have to pass huge sum of foreign exchange to foreign countries for purchase of ships. I would also like to suggest that maximum efforts should be made for the development of Haikul port.

Few small scale industries should also be established there so that resources of the state and energy of the manpower could be made use of. All the parties should make efforts for the development of Kerala.

श्री वासुदेवन् नायर (अम्बलपुजा) : जहां तक मेरा सम्बन्ध है इस प्रस्ताव के समर्थन का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार लगभग गत दो वर्षों से किसी न किसी बहाने से वहां पर राष्ट्रपति के शासन को लागू रखना चाहती है। केरल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो केरल में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के पक्ष में हो।

राज्य सभा में इस समय केरल के 50 प्रतिशत प्रतिनिधि हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सभा के लिए सदस्य चुनने का अवसर भी वहां के लोगों को नहीं दिया। जैसा कि मंत्री महोदय ने इच्छा

व्यक्त की है । हमें भी आशा है कि अगले आम चुनाव के पश्चात केरल में लोकप्रिय सरकार स्थापित हो जायेगी । परन्तु देखना यह है कि उस समय की केन्द्रीय सरकार हमारे राज्य के साथ न्याय करती है अथवा नहीं ।

हमारे राज्य के लिए इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रश्न सब से महत्वपूर्ण है । इसलिए सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि अब जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है केरल में लोकप्रिय सरकार नहीं है । यह एक खेदजनक बात है । जब दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी उस समय भी केरल में राष्ट्रपति का शासन था । गृह-कार्यमंत्री को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में योजना आयोग के पास आने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ गैर-सरकारी व्यक्ति भी आवें जो केरल की समस्याओं को जानते हैं । प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में अधिक धन लगाया जाना चाहिए । तीन पंच वर्षीय योजनाओं में हमने काफी गलतियां की हैं उनको अब नहीं दोहराया जाना चाहिए ।

केरल मैसूर सीमा विवाद को आयोग को सौंपने पर केरल की जनता काफी उत्तेजित है । जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है हम ग्राम को एक एकक मान कर तथा भाषा तथा लोगों की इच्छाओं के अनुसार सीमा विवादों को हल करने के पक्ष में हैं । परन्तु कठिनाई यह है कि सरकार इन सिद्धान्तों को स्वीकार करने से हिचकिचाती है । सरकार ने इन सिद्धान्तों को न मान कर स्वयं ही कठिनाई उत्पन्न की है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

अब पंजाब के बारे में भी सरकार को ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । चण्डीगढ़ के लिए अकाली नेता संत फतेहसिंह आन्दोलन करने वाले हैं ।

मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा विवाद में केरल को घसीटना एक आश्चर्यजनक बात है । हमारे राज्य सम्बन्धी राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी विवाद का प्रश्न लोक प्रिय सरकार के बन जाने के पश्चात ही उठाया जाना चाहिए क्योंकि हमें आशंका है कि सलाहकार के शासन में केरल के मामले सम्बन्धी तक आयोग में पेश नहीं किये जा सकते । विचारणीय विषय के बिना आयोग की नियुक्ति करना अनुचित है । आयोग को कहा जाना चाहिए कि वह भाषा लोगों की इच्छा तथा ग्राम एकक को आधार मान कर सीमा सम्बन्धी झगड़ों का हल करे ।

सरकार को चाहिये कि वह विभिन्न दबावों के वशीभूत होकर इडुकी जलविद्युत परियोजना को हानि न पहुंचने दे । जल विद्युत परियोजना के लिये सरकार को चाहिये कि वह पर्याप्त धन नियत करे ताकि 1970–71 तक हम विद्युत जनित्र को खरीदने की स्थिति में हो जायें । कनाडा के सहभागियों के साथ शीघ्र ही इस सम्बन्ध में करार किया जाना चाहिए ।

राज्य सरकार को चाहिये कि वह, वन अधिवासियों की समस्याओं के बारे में संसदीय सलाहकार समिति की सर्वसम्मत सिफारिश को तुरन्त स्वीकार करे तथा क्रियान्वित करे । इस मामले में विलम्ब नहीं होना चाहिये । जहां तक मालाबार क्षेत्र में निजी वनों का प्रश्न है वह राज्य के लिये काफी महत्व का प्रश्न है । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकार द्वारा भेजे गये विधेयक के प्रारूप को निर्विलम्ब पारित करे ।

[श्री वासुदेवन नायर]

गरी के आयात को इतना सरल न बना दिया जाये कि नारियल के मूल्य पर इसका काफी असर पड़े। इस समय ऐसा ही हो रहा है और मूल्य काफी गिर गये हैं। या तो आयात की कोई सीमा होनी चाहिये या कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जाये कि केरल, मैसूर, मद्रास तथा अन्य राज्यों में उत्पादित देशी गरी तथा नारियल के मूल्य किसी न्यूनतम स्तर पर कायम रखे जा सकें।

सलाहकार तथा राज्यपाल हमारे राज्य की सामान्य जनता की भावनाओं को यथासम्भव अधिक समझने का प्रयत्न करें ताकि जनता के दुखों का यथासम्भव निवारण किया जा सके। ऐसा अनुभव किया जाता है कि हमारे राज्य में उच्चतम सलाहकार समिति द्वारा किये गये निर्णयों का आदर नहीं किया जाता है और उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। क्या प्रतिपक्षी सदस्य यह समझते हैं कि वहां पर प्रतिनिधि सरकार छः महीने से कम समय में, अर्थात् अप्रैल तक बनाई जा सकती है? फरवरी के महीने में सारे देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है केवल वही नारों की बात करता है। जो व्यक्ति समृद्धि नहीं चाहते हैं केवल वही नारों की बात करते हैं। मैं प्रतिपक्षी सदस्यों को बता देना चाहता हुं कि अब समय बदल गया है और राष्ट्रपति के शासन के दौरान केरल के लोगों को पता लग गया है कि समृद्धि का कौन सा रास्ता है। इस बार वे धोखा खाने वाले नहीं हैं।

श्री मोहम्मद कोया (कोजीकोड): अब समय आ गया है जब कि सरकार को राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति का शासन हमारे संविधान के अनुसार सलाहकारों एवं आई० सी० एस० अधिकारियों का शासन है। वैधानिक अवरोध आ जाने से यही एक विकल्प रह गया था। किन्तु यह चल नहीं पायेगा। केरल में लोग राष्ट्रपति शासन से ऊब गये हैं। दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। अतः सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या समस्त प्रशासनिक अधिकार कुछ आई० सी एस० एवं आई० ए० एस० अधिकारियों को देने के बजाय क्या कोई और भी विकल्प हो सकता है। केसरगोट के प्रश्न पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा बाद में सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में गड़बड़ी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विवाद मैसूर एवं महाराष्ट्र के बीच था। अतः केरल को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब वहां पर हर प्रकार की गड़बड़ फैली हुई है। यह सब केन्द्रीय सरकार की अदूरदर्शिता की नीति के कारण है।

केरल के लिए एक परामर्शदातृ समिति है। किन्तु वह समिति निरर्थक है। हमने कुछ निर्णय करने हैं परन्तु आई० सी० एस० अधिकारी और सचिव अपनी ही उच्छृन्खलताओं से काम करते हैं। परामर्श दातृ समिति को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। लोगों को परामर्श दातृ समिति के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोग अपने कष्टों को बता सकें। उन्हें कुछ आई० सी० एस० अधिकारियों के रहम पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के अधीन केरल उपेक्षित रहा है। कालीकट में हवाई अड्डा बनाने और मेलत्तूर से फेरोक तक रेलवे लाइन बनाने की ओर लालफीताशाही के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगले आम चुनावों के बाद केरल में स्थिर और स्थायी सरकार बन सकेगी जिससे राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित हो सकेगी । जहां तक केरल के प्राथमिक अध्यापकों का सम्बन्ध है वे आन्दोलन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बीच जो वेतन सम्बन्धी असमानता है उसको दूर किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री भाषण देना चाहते हैं । अतः माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING INCIDENTS IN DELHI

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): एक जलूस, गोबध रोक का समर्थन करने वाले संगठनों और दलों द्वारा संगठित लगभग 12.30 बजे संसद भवन पहुंचा । संसद भवन के निकट पहुंचने से पहले भी सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति पर पथराव करने की कुछ घटनाओं की सूचना दी गई थी। मुख्य जलूस लगभग 1.30 बजे तक शांत रहा। उस समय स्वामी रामेश्वरानन्द ने जुलस में एक काफी उत्तेजक भाषण दिया। उन्होंने संसद भवन घेरने के लिये तथा मंत्रियों को बाहर आने से रोकने के लिए भीड़ को उत्तेजित किया । भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। वे कुछ पीछे हटे और उन्होंने पुलिस पर ईंटें फेंकी । इस पर पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा। तब घुड़सवार पुलिस ने, जिसके पीछे पैदल सिपाही थे, स्थिति को काबू में करने के लिए प्रयत्न किया । भीड़ ने आकाशवाणी भवन के उद्यान को आग लगा दी । ट्रांसपोर्ट भवन तथा श्रमशक्ति भवन के प्रांगण में खड़ी कुछ कारों तथा स्कूटरों को जला दिया । आकाशवाणी भवन पर भी हमला किया गया । इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी । परिणामस्वरूप भीड़ पीछे हटने लगी । हटते समय उसने विभिन्न कार्यालयों में खड़ी कई निजी तथा सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी । भीड़ ने जो नुकसान तथा विनाश किया उसका पूरा अनुमान नहीं लगाया गया है । अभी तक मिली सूचनाओं के अनुसार कम से कम आठ व्यक्ति गहरे घायल हुए हैं । उनमें से दो के मर जाने की सूचना मिली है। हटते समय भीड़ ने इर्विन रोड पर स्थित पैट्रोल पम्प को आग लगा दी । आकाशवाणी भवन को काफी नुकसान पहुंचाया गया है । गोल डाकखाने के निकट एक नई दिल्ली नगर पालिका तथा एक डाक की बैन के पूरी तरह जलाये जाने की सूचना मिली है । इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि व्यवस्थित समाज के ढांचे को हिंसा से भारी खतरा होने की सम्भावना है । अराजकता तथा गुंडागर्दी को सख्ती से रोकने के लिए हम कदम उठा रहे हैं । संसद भवन से काफी दूर तक जुलूस लाने की अनुमति न देने का अब सरकार ने निश्चय किया है । यह सीमा दो मील के घेरे तक हो सकती है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : आज की दुर्घटना गुंडों द्वारा की गई है। उन्होंने इसके लिए पहले से योजना बना रखी थी । अब हमरे सामने मुख्य प्रश्न गोहत्या के गुणदोषों में जाने का नहीं है अपितु देश में विधि और व्यवस्था स्थापित करने का है । सरकार को तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए । विधि और व्यवस्था पर हमारे

[डा० लक्ष्मिल्ल सिंघवी]

लोकतंत्र की बुनियाद टिकी हुई है। यदि हमने इस प्रकार की घटनाओं को नहीं रोका तो हमारा लोकतंत्र संकट में पड़ जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The hon. Member has been made the Director of the Institute which is being set up by Parliament. In this way flattery is being taught to the people.

श्री रंगा (चित्तूर) : इस सारे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग मरे हैं या जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है उन को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : जब कि सरकार को काफी पहले से पता था कि एक बहुत बड़ा जुलूस आने वाला है तो सरकार ने गुंडागर्दी करने वाले लोगों को काबू में करने के लिए क्या कदम उठाये ? दूसरी चीज़ यह है कि पुलिस को गोली किन परिस्थितियों में चलानी पड़ी। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र पार्टी के नेता प्रो० रंगा ने जो मांग की है वह उचित ही है और सरकार न्यायिक जांच कराने की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : आज उस चीज़ को खतरा पैदा हुआ है जो हमें बहुत प्रिय है और जिसके लिए पिछले कई वर्षों में देशभक्तों ने कष्ट उठाये हैं, संघर्ष किया है और बलिदान दिया है। इस घटना पर हम सबको गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हम सबको लोकतंत्र तथा संसदीय संस्थानों की रक्षा के लिये प्रयत्न करने चाहिए। हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि गाय कृषि के लिये उपयोगी है, परन्तु गाय से भी अधिक महत्व लोकतंत्र का है।

Shri Bagri (Hissar): A congressman was one of the speakers. Another congressman was also present. A judicial enquiry should be held into this tragic incident.

Dr. Govind Das (Jabalpur): Sir, I was present there and I can say that Government is not in the least responsible for what has happened there. What has happened today has dealt a severe blow to the cause of anti-cow slaughter. Such acts of violence are going to bring about ban on cow slaughter. I extend my fullest support to the Government in this regard.

Shri Tyagi (Dehra Dun): This House is unanimous in its opinion that it does not approve of violence, arson, looting and firing. The Minister of Home Affairs ought to have known beforehand regarding what was going to happen and he should have taken precautions against it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : संसद भवन के बिलकुल निकट ही आज जो घटनाएं हुई हैं, वे बहुत ही निन्दाजनक हैं, मुझे इस बात का डर है कि उन घटनाओं का प्रभाव बहुत दूर तक विशेष रूप से देश के उत्तरी भाग में फैल सकता है।

ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई हैं। और गृह-कार्य मंत्री के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि भविष्य में प्रदर्शन कारियों को संसद् भवन के निकट नहीं आने दिया जायेगा। हम न्यायिक जांच का समर्थन करते हैं क्योंकि उससे इन समूची घटनाओं को पृष्ठ भूमि की जांच होगी। हम यह जानना चाहते हैं कि इन बातों के लिए कौन उत्तेजित करता रहा है और इसके साथ सम्बन्धित लोग कौन हैं, हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस ने अत्याचार किए हैं। हमें मिल कर इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि यह मामला और आगे न बढ़ने पाये।

डा० कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : आज समूचे देश की निराशा ज्वाला मुखी के रूप में फूट पड़ी है। आज का घटनाचक्र इसका ही एक प्रमाण है। आज का मामला दलों के बीच का मामला नहीं अपितु यह एक राष्ट्रीय समस्या है। वास्तव में आज लोकतंत्र संकट में है। मैं सत्यनिष्ठा से यह आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री सभी दलों के सदस्यों का एक सम्मेलन बुलायेंगी और उनका समर्थन प्राप्त करेंगी। हम आपस में झगड़ रहे हैं और चीन तथा पाकिस्तान हमारा उपहास कर रहे हैं। हमें मिलकर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ना है।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur): I would like to urge the hon. Home Minister that it is not sufficient to impose a ban on the crowd assembling near the Parliament House. Care must also be taken with regard to other parts of the city. It is not also sufficient to take stern action against those who incite such processions and meetings. Congressmen should not have joined that meeting.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore): This incident is first of its kinds after the attainment of independence. When a huge procession came here for a pious cause, some events took place which violated the sanctity of purpose and which were a curse for the democracy. I personally told those people that their representatives were there in the Parliament to convey their feelings in the House. Therefore, it was not necessary for them to do something which resulted in violence and violated the sanctity of purpose.

After my speech, I came down the stage because I was told that 15 or twenty persons were heading towards the Parliament House. In the meanwhile tear gas shells were thrown which caused the situation to deteriorate. We have seen with our own eyes the destruction of public property and we also saw blood on the road. It is, therefore necessary to know the reality. I am definitely of the view that judicial enquiry in this matter should be held so that truth can be found out.

अध्यक्ष महोदय : सभा कल तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 नवम्बर, 1966/17 कार्तिक, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 8th November, 1966/Kartika 17, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2160(Ai) LS—7-3-1967—600.